www.navpradesh.com

दैनिक नवप्रदेश

आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्

प्रदेश के साथ पूरा देश...

अंदर के पृष्ठों पर ◆◆ 2 | छत्तीसगढ़ 4 | अभिव्यक्ति 9 | कारोबार/खेल

बिलासपुर, शुक्रवार, 7 अगस्त 2026 कृष्ण पक्ष-नवमी, विक्रम संवत -2083 / वर्ष-12 अंक- 117 पृष्ठ-12 मूल्य-5 रुपए रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित

प्रदेश में खरीफ फसलों का होगा डिजिटल 'एक्स-रे' गड़बड़ी पर नपेंगे अफसर

■ शत-प्रतिशत व पारदर्शी गिरदावरी के कड़े निर्देश

■ राजस्व विभाग का फरमान, लापरवाही पर होगी सीधी अनुशासनात्मक कार्रवाई

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य में समर्थन मूल्य पर धान, मक्का और प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत उड़द, मूंग, सोयाबीन, मूंगफली व अरहर की खरीदी की तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने एक बड़ा और कड़ा रुख अपनाया है। विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को खरीफ फसल की शत-प्रतिशत और त्रुटिरहित गिरदावरी सुनिश्चित करने के स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। शासन ने साफ कर दिया है कि गिरदावरी कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या हेरफेर बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरुद्ध तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

गांव-गांव में होगी मुनादी, जन-प्रतिनिधियों के सामने खुलेगा रिकॉर्ड

गिरदावरी की तिथियों से ग्रामीणों को अवगत कराने के लिए गांवों में कोटवारों के जरिए मुनादी कराई जाएगी। गिरदावरी के दौरान स्थानीय जन-प्रतिनिधियों को भी जांच के समय उपस्थित रहने का अवसर दिया जाएगा साथ ही किसान स्वयं उपस्थित होकर अपना फोटो खिंचवा सकते है।

20 सितम्बर तक गिरदावरी पूरी होगी

प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए शासन ने स्पष्ट समय-सीमा तय कर दी है। इसके तहत 20 सितंबर 2026 तक गिरदावरी का कार्य पूर्ण कर खसरा एवं भुईयां सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि व त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके बाद 25 सितंबर 2026 को ग्रामवार फसल क्षेत्राच्छादन प्रतिवेदन का प्रारंभिक प्रकाशन होगा, जिसके आधार पर प्राप्त होने वाली दावा-आपत्तियों का निराकरण करते हुए 30 सितंबर 2026 तक खसरा पांचसाला और भुईयां सॉफ्टवेयर में अंतिम संशोधन कर दिया जाएगा।

7 स्तरीय भौतिक सत्यापन की व्यवस्था

छत्तीसगढ़ में गिरदावरी प्रक्रिया की शुद्धता, पारदर्शिता और मैदानी फर्जीवाड़े पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए शासन ने उच्च अधिकारियों से लेकर मैदानी अमले तक 7-स्तरीय भौतिक सत्यापन की सख्त व्यवस्था लागू की है। इस नई व्यवस्था के तहत पटवारी अपने हल्के के शत-प्रतिशत रकबे का सत्यापन करेंगे। इसके साथ ही राजस्व निरीक्षक और कृषि विस्तार अधिकारी 25-25 प्रतिशत रकबे की जांच करेंगे, जबकि तहसीलदार व नायब तहसीलदार को 10 प्रतिशत और अनुविभागीय अधिकारी को 5 प्रतिशत रकबे के सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गई है।प्रशासनिक कसावट को और मजबूत करते हुए जिला स्तरीय अधिकारी 1प्रतिशत तथा राज्य व संभाग स्तरीय अधिकारी 0.1 प्रतिशत गिरदावरी का औचक निरीक्षण करेंगे।

फसल बदली तो फोटो खींचना अनिवार्य, गलत एंट्री पर गिरेगी गाज

सरकारी रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि यदि किसी किसान ने धान की जगह अन्य फसल बोई है या जमीन खाली छोड़ी है, तो पटवारी और राजस्व निरीक्षक को मोबाइल से उस खेत का खसरावार फोटो अपलोड करना होगा। राजस्व रिकॉर्ड और वास्तविक बोए गए रकबे में अंतर पाए जाने पर संबंधित मैदानी अमले और पर्यवेक्षण अधिकारियों की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी।

आज बेबाक

सही बात है। हर नेता पीएम मोदी जैसा सहनशील नहीं होता। जो गंदी- गंदी गाली देने वालों को माफ कर दे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय जोसेफ ने अपनी महिला मित्र पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले उदयनिधि स्टालिन को पुलिस से घसीटवा कर उठवा लिया। आधा दर्जन धाराओं में अपराध दर्ज करा दिया। यह वही पेंगुइन है जो अपने बाप के मुख्यमंत्री रहते सनातन धर्म को बीमारी बताता था। उसने सोचा अब वो नेता प्रतिपक्ष है इसलिए जो मुंह में आए बक देगा और उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा लेकिन नये सीएम ने इस बीमारी का इलाज कर सारी हेकड़ी निकाल दी।

मानसून सत्र: विपक्ष देश के 140 करोड़ लोगों के मुद्दे उठा रहा, सरकार चर्चा से भाग रही

पीएम-गृहमंत्री सदन में बयान दें : खरगे

नई दिल्ली/वार्ता। संसद में गृह मंत्री अमित शाह को बुलाने की विपक्ष की मांग लगातार जारी है। गुरुवार को राज्यसभा में सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को निर्देश दिया कि वे विपक्ष की भावना गृह मंत्री तक पहुंचाएं। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को सदन में आकर बयान देने का अनुरोध किया, जिस पर सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली।

नेता प्रतिपक्ष खरगे की मांग: नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सदन में कहा कि विपक्ष देश के 140 करोड़ लोगों के मुद्दे उठा रहा है और सरकार चर्चा से भाग रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सदन में आकर बयान देने की मांग की।

संसदीय कार्य मंत्री रिजिजू की आपत्ति: संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने खरगे के अनुरोध पर आपत्ति जताते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष सदन को अपने हिसाब से नहीं चला सकते और वे यह तय नहीं कर सकते कि किस मंत्री को किस दिन सदन में आना चाहिए।

सभापति का हस्तक्षेप: सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने स्पष्ट किया कि खरगे ने कोई आदेश नहीं बल्कि केवल आसन के जरिए अनुरोध किया है। इसके साथ ही उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा कि वे विपक्ष की इस भावना को गृह मंत्री तक पहुंचाएं, जिस पर रिजिजू ने आश्वासन दिया कि वे यह बात पहुंचा देंगे। हंगामे और नारेबाजी के बीच सभापति ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे से बढ़ाकर अपराह्न 2:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

हिरोशिमा बरसी पर श्रद्धांजलि: सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष ओम बिरला ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने की 81वीं बरसी पर मारे गए लोगों को याद किया और सदन ने दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

विपक्ष का हंगामा और नारेबाजी: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्य आसन के समक्ष आकर नारेबाजी करने लगे। गृह मंत्री के बयान और राम मंदिर चढ़ावा चोरी की जांच की मांग को लेकर लगातार हंगामा जारी रहा।

रिजिजू की राहुल गांधी से मुलाकात, राजनीतिक मतभेद हैं, पर देशहित में संसद चलना जरूरी

संसद के मानसून सत्र में लगातार जारी हंगामे और गतिरोध के बीच, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात की है। इस मुलाकात को 'सकारात्मक' बताते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकार विपक्ष के साथ निरंतर संवाद और बेहतर समन्वय चाहती है। रिजिजू ने बताया कि राहुल गांधी के साथ एक विशेष मुद्दे और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राजनीतिक विरोध का मतलब दुश्मनी नहीं होता। राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर सभी दलों को मिलकर काम करना चाहिए।

विधेयक पारित: पीठासीन सभापति संध्या राय ने हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 'कराधान और अन्य विधियां (संशोधन) विधेयक, 2026' को ध्वनिमत से पारित कराने की प्रक्रिया पूरी की। सदस्यों द्वारा लगातार हंगामा जारी रखने के कारण पीठासीन अधिकारी ने सदन की कार्यवाही को पहले दोपहर 2 बजे और बाद में हालात न सुधरने पर शुक्रवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

संसद ठप होने पर चिंता

बार-बार सदन के बाधित होने पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि इससे देश में गलत संदेश जा रहा है कि विपक्ष सदन चलाना नहीं चाहता। संसद न चलने से अंततः जनता का ही नुकसान होता है। विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री संसद में मौजूद रहते हैं और नियम के मुताबिक जिस मंत्री का विधेयक चर्चा में होता है, वही सदन में उपस्थित रहता है।

डीपफेक पर सरकार का शिकंजा मजबूत, अब लेबलिंग अनिवार्य

नई दिल्ली/ए.। केंद्र सरकार ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार डीपफेक और अन्य कृत्रिम रूप से उत्पन्न सामग्री से होने वाले नुकसान से निपटने के लिए नियामक ढांचे को मजबूत किया है। आईटी नियमों में किए गए हालिया संशोधनों के तहत एआई-जनित सामग्री की स्पष्ट लेबलिंग और पता लगाने योग्य मेटाडेटा सुनिश्चित करना अनिवार्य किया गया है। साथ ही, सरकार या अदालत के आदेश के आधार पर गैरकानूनी सामग्री हटाने की समयसीमा 36 घंटे से घटाकर तीन घंटे कर दी गई है। यह जानकारी केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने 5 अगस्त 2026 को ■ शेष पृष्ठ 8 पर

डीपफेक के खतरों पर सरकार की नजर

सरकार ने कहा कि वह एआई से संचालित डीपफेक से पैदा होने वाले खतरों के प्रति सचेत है। इसमें कृत्रिम ऑडियो, वीडियो और लिखित सामग्री शामिल हैं। सरकार का उद्देश्य उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह साइबरस्पेस सुनिश्चित करना है। इसी दिशा में मौजूदा कानूनों और नियमों के जरिए डीपफेक के विभिन्न पहलुओं से निपटने की व्यवस्था की गई है।

आईटी अधिनियम में कई प्रावधान

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने, कंप्यूटर संबंधी अपराध, पहचान की चोरी, प्रतिरूपण और निजता के उल्लंघन जैसे अपराधों के खिलाफदंड का प्रावधान है। अश्लील या यौन रूप से स्पष्ट सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण पर भी कार्रवाई की जा सकती है। अधिनियम की धारा 69ए के तहत विशिष्ट सूचना या लिंक तक पहुंच को अवरुद्ध करने और धारा 79 के तहत गैरकानूनी गतिविधियों में इस्तेमाल की जा रही जानकारी को हटाने की व्यवस्था है।

बीएनएस में भी कार्रवाई का प्रावधान

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 में भी डीपफेक से जुड़े अपराधों पर कार्रवाई के प्रावधान हैं। धारा 319 के तहत प्रतिरूपण के जरिए धोखाधड़ी, जबकि धारा 336 के तहत धोखाधड़ी और किसी व्यक्ति को धोखा देने या उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करने पर कार्रवाई की जा सकती है। धारा 353 गलत या भ्रामक बयान, अफ़्वाह और रिपोर्ट के जरिए दुष्प्रचार फैलाने पर अंकुश लगाती है।

विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना का दावा गलत : नायडू

नई दिल्ली (वार्ता)। नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू ने विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना के दावों को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा है कि ऐसी बातों से हवाई यात्रियों में अनावश्यक चिंता पैदा होती है। श्री नायडू ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि यह दावा पूरी तरह से झूठा और गैर-जिम्मेदाराना है कि सरकार की विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की योजना है। उन्होंने कहा कि ऐसी किसी भी योजना का प्रस्ताव नहीं है। उल्लेखनीय है कि मीडिया में इस तरह की खबरें आयी थीं कि सरकार ने विमान ईंधन में एथेनॉल मिलाने की अनुमति दे दी है।

गरमा-गरम

तरुण तेजपाल को 2013 रेप केस में 10 साल की सजा

नई दिल्ली/वार्ता। बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा बेंच ने गुरुवार को सीनियर पत्रकार तरुण तेजपाल को 2013 के चर्चित रेप केस में 10 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मापुसा सेशन कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें मई 2021 में उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।

यह है पूरा मामला नवंबर 2013 में 'तहलका' मैग्जीन के तत्कालीन एडिटर-इन-चीफ़ तरुण तेजपाल पर गोवा के एक होटल में उनकी जूनियर सहयोगी ने यौन उत्पीड़न और रेप का आरोप लगाया था। घटना के बाद तेजपाल ने ईमेल भेजकर पीड़िता से बिना शर्त माफी भी मांगी थी।

हाईकोर्ट ने गोवा सरकार की अपील मंजूर करते हुए आईपीसी की धारा 376(2)(एफ) और 376(2)(के) के तहत 10-10 साल की कठोर कैद और 5-5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा धारा 354ए, 354बी, 341 और 342 के तहत भी सजा और जुर्माना तय किया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि तेजपाल की सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।

वेनेजुएला समेत अमेरिका का दुनिया के 60 फीसदी तेल पर नियंत्रण: ट्रंप

वाॅशिंगटन (स्पुतनिक/वार्ता)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का दुनिया के 60 प्रतिशत तेल पर कंट्रोल है, जिसमें वेनेजुएला के रिसोर्स को भी अमेरिकी क्षमता का हिस्सा माना गया है। लास वेगास में अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए श्री ट्रंप ने कहा, हमारे पास दुनिया के किसी भी देश की तुलना में ज़्यादा तेल और गैस है। अब इसमें वेनेजुएला को भी जोड़ लें। इसे जोड़ने पर, वेनेजुएला सहित हमारे पास दुनिया का 60 प्रतिशत तेल और गैस है। अमेरिका ने 3 जनवरी को वेनेजुएला में एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया, जिसके दौरान निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क ले जाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन पर नार्को-टेररिज्म (नशीले पदार्थों की तस्करी से जुड़ा आतंकवाद) में शामिल होने के आरोपों के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। मादुरो और फ्लोरेस ने न्यूयॉर्क की अदालत में आरोपों से इनकार किया।

मादुरो की गिरफ्तारी के बाद, वेनेजुएला के सुप्रीम कोर्ट ने अस्थायी रूप से राष्ट्रपति पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति रोड्रिग्ज को सौंप दिया। ■ शेष पृष्ठ 8 पर

23,731 करोड़ की 'गोबरधन'योजना को मंजूरी

■ केन्द्रीय कैबिनेट: देश में संपीड़ित बायोगैस क्षेत्र को बढ़ावा देने बनी योजना

नई दिल्ली/ए.। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपये की लागत वाली राष्ट्रीय सर्कुलर बायोएनर्जी योजना 'गोबरधन' को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य कृषि अवशेष, गोबर, शहरी जैविक कचरे और अन्य बायोमास संसाधनों को संपीड़ित बायोगैस, जैविक खाद और ग्रामीण आय के स्रोत में बदलना है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक लागू रहेगी और भारत की ऊर्जा व्यवस्था में संपीड़ित बायोगैस को एक प्रमुख ■ शेष पृष्ठ 8 पर

किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा लाभ

सरकार के अनुसार, यह योजना किसानों, सहकारी समितियों, फीडस्टॉक आपूर्तिकर्ताओं और ग्रामीण उद्यमियों के लिए आय के नए अवसर पैदा करेगी। साथ ही कृषि अवशेष, गोबर और शहरी जैविक कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आएगी और जैविक खाद के उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। सरकार का कहना है कि गोबरधन योजना ऊर्जा सुरक्षा, 'वेस्ट टू वेल्थ', आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के लक्ष्य को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

सुशासन की नई व्यवस्था : पारस पोर्टल से हर माह होगी योजनाओं की राज्यस्तरीय समीक्षा

सीमांकन मामलों में लापरवाही पर सीएम सख्त, समय-सीमा में करे निराकरण

■ जनहित की योजनाओं में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त, मुख्यमंत्री साय ने दिए स्पष्ट निर्देश

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गुरुवार को मंत्रालय महानदी भवन में 'पारस पोर्टल' की पहली राज्यस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सुशासन और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जनहित की योजनाओं और आम नागरिकों के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से विभिन्न विभागों के कार्यों की राज्यस्तरीय समीक्षा की जाएगी।

सीमांकन मामलों में नाराजगी और निर्देश: मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में सीमांकन से जुड़े लंबित ■ शेष पृष्ठ 8 पर

एग्रीस्टैक में शत-प्रतिशत किसान पंजीयन

मुख्यमंत्री ने किसानों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एग्रीस्टैक के तहत प्रत्येक पात्र किसान का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही के कारण यदि कोई किसान वंचित रहा, तो संबंधित अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होगी।

■ अब प्रत्येक माह के अंतिम मंगलवार को पारस पोर्टल के माध्यम से होगी राज्यस्तरीय समीक्षा

सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा

बैठक में बताया गया कि सीएम हेल्पलाइन (1076) पर अब तक 1.10 लाख से अधिक शिकायतें मिल चुकी हैं, जिनमें से 65 हजार से ज्यादा का निराकरण किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा, पंचायत और राजस्व विभागों से जुड़ी शिकायतों के समयबद्ध समाधान के लिए विशेष कार्ययोजना तैयार करने को कहा है।

स्कूलों में किचन गार्डन और पौधारोपण

मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों को ताजा और पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने के लिए स्कूल परिसरों में 'किचन गार्डन' विकसित करने तथा सहजन व कटहल जैसे उपयोगी पौधे लगाने के अभियान को गति देने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव विकास शील, अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

6 नए जिलों में खेल अधिकारियों के पदों को मंजूरी

रायपुर/नवप्रदेश। राज्य शासन ने खेल गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए 6 नए जिलों गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और सक्ती में खेल अधिकारी के नए पदों को मंजूरी दी है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मंत्रालय से विगत 4 अगस्त को इन पदों की मंजूरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

अतीक के बेटे की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत

■ झांसी जेल जा रहे थे भाई से मिलने

प्रयागराज/ए.। अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे अबान (21) की एक भीषण सड़क हादसे में मौत हो गई है। यह हादसा गुरुवार सुबह करीब 10:30 बजे झांसी से 70 किलोमीटर पहले पूंछ थाना क्षेत्र में हुआ। अबान अपनी क्रेटा कार में चार दोस्तों के साथ प्रयागराज से झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली से मिलने जा रहा था। तेज रफ्तार क्रेटा कार हाईवे पर अचानक डिवाइडर से टकरा गई, जिससे वह हवा में उछल गई और उसका अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस दर्दनाक हादसे में अबान और उसके दोस्त सोनू की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार अन्य तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, हादसे के वक्त कार ■ शेष पृष्ठ 8 पर

न्यूज गैलरी

अपराजिता सम्मान समारोह में महिलाओं की प्रतिभा को मिलेगा नया मंच

भाटापारा / नवप्रदेश। महिलाओं की प्रतिभा, आत्मविश्वास, व्यक्तित्व विकास एवं सामाजिक सम्मान को नई पहचान देने के उद्देश्य से 'अगाता रनवे एवं अपराजिता सम्मान समारोह2026' का आयोजन आगामी 09 अगस्त , रविवार को भाटापारा ऑडिटोरियम में किया जाएगा। यह आयोजन न केवल फैशन एवं व्यक्तित्व प्रदर्शन का मंच होगा, बल्कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं के सम्मान का भी एक विशेष अवसर बनेगा।कार्यक्रम का आयोजन श्रीमती अभिलाषा झा के नेतृत्व में किया जा रहा है। आयोजन को सफल बनाने में स्वयंसिद्धा फाउंडेशन, सिद्धि विनायक टाइल्स एंड ग्रेनाइट, भाटापारा तथा एच.आर. ज्वेलर्स का विशेष सहयोग प्राप्त है। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष श्रीमती मोना सेन विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगी, वहीं मिस इंडिया यूनिवर्स2025 दामिनी देवांगन अपनी गरिमामयी उपस्थिति से प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करेंगी।समारोह में श्रीमती सीमा शर्मा, श्रीमती नेहा शर्मा, श्रीमती अंजु भृगु एवं दीपिका जैन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगी। कार्यक्रम के निर्णायक मंडल में श्रीमती किरण रात्रे, श्रीमती मीना शाक्य, श्रीमती उषा शर्मा,राजेश्वरी ध्रुव व आलिया परवीन शामिल रहेंगी। वहीं श्रीमती सीमा गुप्ता सह-आयोजक के रूप में कार्यक्रम के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ की संभाग स्तरीय बैठक 8 अगस्त को

कांकेर / नव प्रदेश। । छत्तीसगढ़ राज्य दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ (पंजीयन क्रमांक-620) के तत्वावधान में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की संभाग स्तरीय बैठक का आयोजन 8 अगस्त 2026, शनिवार को दोपहर 12 बजे मंडी प्रांगण, जगदलपुर में किया जाएगा। बैठक में बस्तर संभाग के सभी जिलों के कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया है। संघ की ओर से जारी जानकारी के अनुसार बैठक में जगदलपुर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर सहित बस्तर संभाग के अंतर्गत आने वाले जिलों के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी भाग लेंगे। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन को और अधिक मजबूत बनाना तथा कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं एवं मांगों पर विस्तार से चर्चा करना है। बैठक में छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों की भी विशेष उपस्थिति रहेगी। प्रदेशाध्यक्ष मिलापचंद यादव, महामंत्री निशांत राज दुबे, कोषाध्यक्ष तीरथ साहू, सहसचिव गज्जु सिन्हा तथा धमतरी जिला अध्यक्ष सहित प्रतिनिधिमंडल कर्मचारियों के बीच संगठन की भावी रणनीति, कर्मचारी हितों से जुड़े मुद्दों और संगठनात्मक मजबूती पर विचार-विमर्श करेगा। संघ पदाधिकारियों ने बताया कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, लंबित मांगों के समाधान तथा भविष्य की कार्ययोजना को लेकर यह बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बैठक के माध्यम से कर्मचारियों की समस्याओं को एकजुट होकर शासन-प्रशासन के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाने की रणनीति भी तैयार की जाएगी। संघ ने बस्तर संभाग के सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी साथियों से अधिक से अधिक संख्या में बैठक में शामिल होने की अपील की है। पदाधिकारियों का कहना है कि कर्मचारियों की एकजुटता ही संगठन की सबसे बड़ी ताकत है और सभी की सक्रिय भागीदारी से कर्मचारी हितों की लड़ाई को मजबूती मिलेगी।

वन डिस्ट्रिक्ट, वन स्पोर्ट्स के लिए आवेदन आमंत्रित

उत्तर बस्तर कांकेर / नव प्रदेश। / छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को तराशने तथा क्षमता के अनुरूप राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से तथा वर्ष 2030 के एशियाई खेल, वर्ष 2030 एवं 2034 के कॉमनवेल्थ खेल तथा देश में आयोजित होने वाले वर्ष 2036 के ओलंपिक खेलों में राज्य के खिलाड़ियों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए राज्य शासन द्वारा 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन स्पोर्ट्स' के तहत खेल प्रतियोगिता आयोजित कर प्रतिभा चिन्हांकन किया जाना है। कांकेर जिला में वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट खेल प्रतियोगिता 2026 के माध्यम से ग्रामीण एवं स्थानीय स्तर पर खेल प्रतिभाओं में चिन्हांकन एवं विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना है। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि कांकेर जिले की भौगोलिक परिस्थितियों, स्थानीय खेल परंपरा, उपलब्ध खेल अधोसंरचना, प्रशिक्षकों की उपलब्धता तथा खेल प्रतिभाओं की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए ओलंपिक, एशियाई खेल एवं कॉमनवेल्थ खेलों में सम्मिलित खेल विधाओं में से एथलेटिक्स खेल का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि अधिक से अधिक ग्रामीण स्तर पर बालक, बालिकाओं एवं छात्र, छात्राओं के पंजीयन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कांकेर एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को पत्र लिखा गया है। उन्होंने बताया कि जिले के ग्रामीण स्तर पर बालक-बालिकाओं एवं विद्यार्थियों को अपना आवेदन पत्र कार्यालय खेल अधिकारी, खेल एवं युवा कल्याण कांकेर, जिला शिक्षा अधिकारी, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कांकेर एवं समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत में अंतिम तिथि 15 अगस्त तक जमा कर सकते हैं।

आकाशीय बिजली गिरने एवं डूबने से मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत

अंतागढ़ / नव प्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रावधानों एवं राजस्व पुस्तक परिपत्र खंड 6-4 के तहत उत्तर बस्तर कांकेर जिला प्रशासन ने प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले व्यक्तियों के आश्रितों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। न्यायालय कलेक्टर उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा जारी आदेशों के अनुसार अंतागढ़ तहसील क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने एवं पानी में डूबने से हुई मृत्यु के पांच प्रकरणों में मृतकों के निकटतम वारिसों के लिए प्रत्येक प्रकरण में 4 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।स्वीकृत प्रकरणों में ग्राम लामकन्हार निवासी सविता दुग्गा की गड्ढे में डूबने से मृत्यु होने पर उनके पति प्रेमसिंह दुग्गा, ग्राम कलगांव निवासी मनराज ठाकुर की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर उनकी पत्नी यशोदा बाई, प्रकाश पटेल की आकाशीय बिजली गिरने से मृत्यु होने पर को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

डॉक्टरों की हड़ताल को मिला पूर्व विधायक रेखचंद जैन का समर्थन

■ **मुख्यमंत्री को पत्र लिख स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग,मेकाज पहुंचकर धरने में हुए शामिल**

जगदलपुर / नव प्रदेश। शासकीय मेडिकल कॉलेज (मेकाज) के इंटर्न डॉक्टरों की स्टाइपेंड वृद्धि की मांग को लेकर जारी हड़ताल को पूर्व विधायक एवं पूर्व संसदीय सचिव रेखचंद जैन का समर्थन मिला है। जैन अपने समर्थकों और सहयोगियों के साथ मेकाज पहुंचे तथा धरनास्थल पर बैठकर इंटर्न डॉक्टरों की मांगों का समर्थन किया।

पूर्व विधायक जैन ने कहा कि इंटर्न डॉक्टर स्वास्थ्य सेवाओं की महत्वपूर्ण कड़ी हैं और वे कठिन परिस्थितियों में लगातार मरीजों की सेवा करते हैं। इसके बावजूद उनके स्टाइपेंड में लंबे समय से कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और भूपेश बघेल के कार्यकाल में निर्धारित स्टाइपेंड में वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान कोई संशोधन नहीं हुआ है। बढ़ती महंगाई और कार्यभार को देखते हुए इंटर्न डॉक्टरों को उचित मानदेय मिलना आवश्यक है।

उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर इंटर्न डॉक्टरों का स्टाइपेंड शीघ्र बढ़ाने की मांग की है। जैन ने कहा कि सरकार को इस विषय में संवेदनशीलता दिखाते हुए जल्द सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए,ताकि डॉक्टर अपनी सेवाएं निर्बाध रूप से जारी रख सकें। जगदलपुर में आयोजित धरने के दौरान हेमू उपाध्याय, विजय सिंह,कुलदीप भदौरिया,निर्मल लोढ़ा,जावेद खान,जालंधर नाग सहित अन्य समर्थक भी उपस्थित रहे।

बढ़ते कार्यभार के अनुरूप स्टाइपेंड बढ़ाया जाना आवश्यक

पूर्व विधायक रेखचंद जैन ने इंटर्न डॉक्टरों की स्टाइपेंड वृद्धि की मांग का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र भेजा है। उनका कहना है कि महंगाई और बढ़ते कार्यभार के अनुरूप स्टाइपेंड बढ़ाया जाना आवश्यक है, ताकि युवा डॉक्टरों का मनोबल बना रहे और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित न हों।

माइनिंग का दुष्प्रभाव: खदानें दूर, लेकिन प्रदूषण से अंतागढ़ सबसे अधिक प्रभावित

अंतागढ़ / नव प्रदेश। नगर क्षेत्र में भले ही कोई लौह अयस्क खदान (माइन) संचालित नहीं हो रही है, लेकिन यहां की स्थिति किसी खनन क्षेत्र से कम नहीं दिखाई देती। क्षेत्र के लोग लंबे समय से धूल, प्रदूषण, जर्जर सड़कों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिन खदानों के कारण यह समस्या उत्पन्न हो रही है, वे अंतागढ़ से लगभग 15 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित हैं।

लगातार परिवहन से सड़कें हुईं जर्जर

क्षेत्र में संचालित रावघाट और मेटा-बिदेली की खदानों से प्रतिदिन भारी संख्या में लौह अयस्क से भरे वाहन गुजरते हैं। इन भारी वाहनों के लगातार आवागमन के कारण अंतागढ़ क्षेत्र की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। सड़कें जगह-जगह टूट गई हैं, जिससे आम नागरिकों के साथ-साथ स्कूली बच्चों, मरीजों और राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

हवा, पानी और ध्वनि प्रदूषण की चपेट में पूरा क्षेत्र

खनिज परिवहन के दौरान उड़ने वाली लाल धूल पूरे क्षेत्र में फैल रही है। स्थिति यह है कि सड़क किनारे स्थित मकानों, दुकानों, खेतों और पेड़-पौधों तक पर लाल धूल की परत जम जाती है। हवा प्रदूषित हो चुकी है, वहीं जल स्रोतों और मिट्टी पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लगातार चलने वाले भारी वाहनों के कारण ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ गया है, जिससे लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है।

डंप यार्ड के कारण सड़क से रेलवे स्टेशन तक लाल धूल का असर

डंप यार्ड और अयस्क परिवहन के कारण सड़क से लेकर रेलवे स्टेशन तक पूरा क्षेत्र लाल धूल की चपेट में है। ऐसा प्रतीत होता है मानो खनन कार्य अंतागढ़ में ही संचालित हो रहा हो, जबकि वास्तविक खदानें काफी दूरी पर स्थित हैं।

लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव

प्रदूषण का सीधा असर स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। क्षेत्र में सांस लेने में तकलीफ आंखों में जलन, एलर्जी, खांसी तथा अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। सबसे अधिक परेशानी बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को हो रही है।

खनन शुरू होने से पहले किए गए वादे अधूरे

खनन शुरू करने से पहले कंपनियों द्वारा क्षेत्र के विकास, रोजगार, स्वास्थ्य सुविधाओं और सामाजिक उत्तरदायित्व (ष्टस्क्र) के तहत कई वादे किए गए थे। समय-समय पर मेडिकल कैंप लगाए जाते थे और लोगों को निःशुल्क उपचार की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती थी। लेकिन अब अधिकांश सुविधाएं बंद हो चुकी हैं और क्षेत्रवासी स्वयं को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं।

शा. शहीद राजेश पवार हायर सेकेंडरी स्कूल में सेवानिवृत्त एवं पदोन्नत कर्मचारी का सम्मान

अंतागढ़ / नवप्रदेश। शासकीय शहीद राजेश पवार हायर सेकेंडरी स्कूल अंतागढ़ में बुधवार को सेवानिवृत्त व्याख्याता शर्मिला रानी कुमार, वरिष्ठ व्याख्याता मधुसूदन यदु तथा भृत्य कमलेश नेताम के सहायक ग्रेड-3 पद पर पदोन्नत होने के उपलक्ष्य में सम्मान एवं विदाई समारोह का आयोजन किया गया। पूरे कार्यक्रम के दौरान भावुक माहौल बना रहा। विद्यालय परिवार ने शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सभी का सम्मान करते हुए उनके दीर्घ एवं समर्पित सेवाकाल की सराहना की।

समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि शिक्षक केवल विद्यार्थियों को शिक्षा ही नहीं देते, बल्कि उनके व्यक्तित्व निर्माण, संस्कारों और उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव भी रखते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रभारी प्राचार्य का दायित्व निभा चुकीं शर्मिला रानी कुमार तथा वरिष्ठ व्याख्याता मधुसूदन यदु ने अपने लंबे सेवाकाल में हजारों विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर उनके भविष्य को संवारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वहीं कमलेश नेताम ने भी विद्यालय में अपने दायित्वों का ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ निर्वहन करते हुए सभी का स्नेह और सम्मान अर्जित किया।कार्यक्रम के दौरान सम्मानित अतिथियों ने अपने सेवाकाल के अनुभव साझा किए। शर्मिला रानी कुमार एवं मधुसूदन यदु ने विद्यालय परिवार, विद्यार्थियों, नगरवासियों तथा ग्रामीणों द्वारा वर्षों तक मिले सहयोग, स्नेह और सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया तथा सभी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कलेक्टर ने 200 सीटर कन्या आवासीय विद्यालय का निरीक्षण कर ली जानकारी

कांकेर/दुर्गूकोंदल / नवप्रदेश। उत्तर बस्तर कांकेर जिले के सुदूरवर्ती विकासखंड दुर्गूकोंदल स्थित 200 सीटर कन्या आवासीय विद्यालय का गुरुवार को जिला कलेक्टर निलेश महादेव क्षीरसागर एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेश मंडावी ने निरीक्षण किया। अधिकारियों ने विद्यालय की शैक्षणिक, आवासीय एवं आधारभूत व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लेते हुए छात्राओं से सीधे संवाद किया और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान विद्यालय में अनुशासित वातावरण, स्वच्छता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण व्यवस्था की सराहना करते हुए आवश्यक सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने छात्राओं के शयन कक्षों का निरीक्षण कर उनसे दैनिक आवश्यकताओं के संबंध में चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से मच्छरदानियों की उपलब्धता के बारे में पूछा, जिस पर छात्राओं ने बताया कि उन्हें आवश्यकतानुसार सभी सुविधाएं मिल रही हैं। छात्राओं के आत्मविश्वास, अनुशासन और स्पष्ट अभिव्यक्ति से प्रभावित कलेक्टर ने उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने, बड़े लक्ष्य निर्धारित करने तथा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने छात्राओं से उनके गांव, विकासखंड और पूर्व विद्यालय की जानकारी भी ली।

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने बालक एवं बालिका छात्रावास के विद्यार्थियों से भी संवाद किया। इस दौरान बालक छात्रावास के विद्यार्थियों ने बिस्तर एवं गद्दों की आवश्यकता बताई, जबकि दोनों छात्रावासों के विद्यार्थियों ने खेल गतिविधियों के लिए समुचित खेल मैदान उपलब्ध कराने की मांग रखी। विद्यार्थियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि आवश्यक सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराई जाएंगी तथा खेल मैदान का निर्माण प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।

कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ ने विद्यालय की प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और कंप्यूटर लैब का भी निरीक्षण किया।

उन्होंने आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित प्रयोगशालाओं, समृद्ध पुस्तकालय, डिजिटल शिक्षण व्यवस्था और कक्षाओं की आकर्षक सजावट की सराहना करते हुए कहा कि तकनीक आधारित शिक्षा विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं और भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर ढंग से तैयार करती है। उन्होंने शिक्षकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण पर विशेष ध्यान देने और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयास करने की बात कही।

महामृत्युंजय हवन में उमड़ा बस्तर, किरण देव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए गूंजे वैदिक मंत्र

■ **चार दिवसीय अनुष्ठान की पूर्णाहुति में विभिन्न समाजों, संगठनों और राजनीतिक दलों के लोगों ने निभाई सहभागिता**

जगदलपुर/ नव प्रदेश। सावन मास की आध्यात्मिक बेला में भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण देव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ,दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना को लेकर गुरुवार को जगन्नाथ मंदिर परिसर में महामृत्युंजय मंत्र जप एवं हवन की पूर्णाहुति श्रद्धा और भक्ति के वातावरण में संपन्न हुई। चार दिनों तक चले इस धार्मिक अनुष्ठान के अंतिम दिन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आहुति देकर प्रदेश अध्यक्ष के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की।

लगातार तीन दिनों तक विद्वान पंडितों द्वारा महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप किया गया। चौथे दिन आयोजित पूर्णाहुति हवन का मुख्य अनुष्ठान प्रदेश अध्यक्ष के बड़े भ्राता कुमार जयदेव ने संपन्न कराया। इस अवसर पर बस्तर संभाग के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों ने धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेकर अपनी आस्था व्यक्त की।

कार्यक्रम की विशेषता यह रही कि इसमें विभिन्न समाजों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। आयोजन में सर्वसमाज की सहभागिता ने यह संदेश दिया कि किरण देव का सामाजिक और व्यक्तिगत जुड़ाव व्यापक है तथा उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना पूरे बस्तर की सामूहिक भावना बन गई है।

गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद किरण देव का मेदांता अस्पताल में सफल ऑर्थो सर्जरी हुई है। इसी क्रम में महामृत्युंजय जाप आयोजन समिति ने उनके पूर्ण स्वस्थ होने की मंगलकामना के साथ दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक विशेष मंत्र जप एवं हवन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।

महामृत्युंजय अनुष्ठान की प्रमुख बातें

चार दिवसीय महामृत्युंजय मंत्र जाप का समापन गुरुवार को पूर्णाहुति हवन के साथ हुआ। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के बड़े भ्राता कुमार जयदेव ने पूर्णाहुति संपन्न कराई। आयोजन में सर्वसमाज,सामाजिक संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मेदांता अस्पताल में उपचाररत किरण देव के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ और दीर्घायु की कामना के साथ पूरे बस्तर से पहुंचे श्रद्धालुओं ने हवन में आहुति देकर मंगलकामना की।

देवड़ा में किसानों को सहकारी योजनाओं,एफपीओ और आधुनिक उर्वरकों की दी जानकारी

सहकारिता की जानकारी से ही साकार होगा 'सहकार से समृद्धि' का लक्ष्य

जगदलपुर / नव प्रदेश। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ मर्यादित, रायपुर द्वारा आदिवासी सदस्य सहकारी शिक्षा योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर की सहकारी संस्था इफ्को के सहयोग से बस्तर विकासखंड के सोनारपाल लैम्प्स अंतर्गत ग्राम पंचायत देवड़ा में सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों और सहकारी सदस्यों को सहकारिता की उपयोगिता, कृषि योजनाओं तथा आधुनिक खेती से जुड़े विषयों की जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण में वरिष्ठ प्रशिक्षक विवेक पांडे ने कहा कि 'सहकार से समृद्धि' का लक्ष्य तभी पूरा होगा,जब सहकारी संस्थाएं मजबूत होंगी और ग्रामीणों की सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की योजना के तहत आगामी दो वर्षों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में लैम्प्स/पैक्स, दुग्ध एवं मत्स्य पालन जैसी सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही किसानों को सहकारी संस्थाओं की भूमिका,उपलब्ध सुविधाओं तथा कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।

इफ्को के क्षेत्रीय अधिकारी लाल बहादुर सिंह और सहायक फील्ड असिस्टेंट वैभव पांडे ने रासायनिक एवं जैविक उर्वरकों के संतुलित उपयोग,नैनो यूरिया एवं नैनो डीएपी के वैज्ञानिक प्रयोग तथा इफ्को उर्वरक की खरीदी पर मिलने वाली संकट हरण बीमा योजना की जानकारी दी। वहीं सोनारपाल लैम्प्स के प्रबंधक प्रेमनाथ वेद ने किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत ऋण वितरण और उससे मिलने वाले लाभों पर विस्तार से प्रकाश डाला।

किसानों को मिली योजनाओं की उपयोगी जानकारी

प्रशिक्षण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण कृषकों और सहकारी सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में सोनारपाल लैम्प्स के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी संघ के रोमांचल पाणिग्राही का विशेष सहयोग रहा। विशेषज्ञों ने किसानों से सहकारी संस्थाओं से जुड़कर आधुनिक तकनीक और सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाने का आह्वान किया।

रावतपुरा सरकार मामला: सीबीआई की फोन टैपिंग अवैध, रिकॉर्डिंग्स नष्ट करने हाईकोर्ट का आदेश

जारी रहेगा केस, चेयरमैन रविशंकर महाराज ने फोन-टैपिंग को दी थी चुनौती

बिलासपुर/नवप्रदेश। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल ने श्री रावतपुरा संस्थान के चेयरमैन और कथावाचक श्री रावतपुरा सरकार (रवि शंकर जी महाराज) को फोन टैपिंग मामले में बड़ी राहत दी है। डिवीजन बेंच ने सीबीआई के फोन टैपिंग को पूरी तरह से गैर कानूनी ठहराते हुए रद्द कर दिया है।

हाईकोर्ट ने टैपिंग के जरिए हासिल की गई सभी रिकॉर्डिंग्स को नष्ट करने के आदेश दिए हैं। हालांकि, डिवीजन बेंच ने सीबीआई की एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने से इनकार कर दिया है। अब सीबीआई को इस केस को फोन टैपिंग के सबूतों के बिना ही अन्य दस्तावेजों और गवाहों के आधार पर कोर्ट में साबित करना होगा। सीबीआई ने 30 जून 2025 को देश भर के 35 मेडिकल संस्थानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, इसमें आरोप था कि स्वास्थ्य मंत्रालय और एनएमसी के अधिकारियों के साथ मिलकर रिश्वत, फर्जी मरीज और घोस्ट फैकल्टी के जरिए मेडिकल कॉलेजों को अपने पक्ष में निरीक्षण रिपोर्ट दिलाई जाती थी। इस मामले में श्री रावतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, रायपुर के चेयरमैन होने के नाते रावतपुरा सरकार को भी आरोपी बनाया गया था। सीबीआई ने रावतपुरा सरकार के खिलाफ 28 जून 2025 को फोन टैपिंग का आदेश जारी किया था। हालांकि, गृह मंत्रालय और दूरसंचार विभाग की ओर से दाखिल हलफनामे में इसे 1 जून 2025 से 31 जुलाई 2025 तक वैध बताया गया। रावतपुरा सरकार ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में हाईकोर्ट ने एफआईआर और चार्जशीट को खारिज नहीं किया है। रायपुर की विशेष सीबीआई अदालत को निर्देश दिया गया है कि वह फोन टैपिंग के सबूतों को पूरी तरह नजरअंदाज कर केवल अन्य वैध सबूतों और गवाहों के आधार पर केस की सुनवाई आगे बढ़ाए।

हाईकोर्ट ने सीबीआई से पूछा- बैकडेट से कैसे दी मंजूरी

हाईकोर्ट ने सीबीआई के शपथपत्र पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि, जब मूल आदेश ही 28 जून को जारी हुआ, तो गृह मंत्रालय 27 दिन पुरानी तारीख से बैकडेट में इसे मंजूरी कैसे दे सकता है? हाईकोर्ट ने पाया कि फोन टैपिंग का आदेश जारी करते समय किसी प्रकार की सार्वजनिक आपातस्थिति या जनसुरक्षा के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया था। आदेश केवल औपचारिक तौर पर आदेश पास कर दिया गया था।

फोन टैपिंग किसी व्यक्ति की निजता पर हमला

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि फोन टैपिंग किसी व्यक्ति की निजता पर सीधा हमला है। इसके लिए तय कानूनी प्रक्रिया का कड़ाई से पालन होना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने 28 जून 2025 का सीबीआई का टैपिंग ऑर्डर, 4 जुलाई 2025 का गृह मंत्रालय का पुष्टि आदेश और 15 सितंबर 2025 की रिव्यू कमेटी की कार्रवाई रद्द कर दी है।

न्यूज गैलरी

तिरंगा यात्रा 15 को तैयारियां जोरों पर

रतनपुर/नवप्रदेश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तत्वाधान में आयोजित होने वाले ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा की जोरदार तैयारियां की जा रही है, 15अगस्त को होने वाले इस भव्य तिरंगा यात्रा में इस वर्ष एक हजार फिट लंबी तिरंगा यात्रा निकाल कर भारत माता की जयकारे लगाते हुए नगर भ्रमण करेगा। गौरतलब है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बीते सात वर्षों से 15अगस्त के दिन भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन धूमधाम के साथ नगरवासियों के सहयोग से निकाला जाता रहा है,इसी कड़ी में अभाविप के पदाधिकारियों की बैठक बीते दिनों सम्पन्न हुई, जिसमे सर्वसम्मति से एक हजार फिट लंबी तिरंगा यात्रा निकालने की सहमति बनाई गई,आयोजकों ने बताया हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पूरे भव्यता के साथ तिरंगा यात्रा 15अगस्त को सुबह ग्यारह बजे माँ महामाया महाविद्यालय से हजारों छात्र छात्राओं के साथ वंदेमातरम गायन करते ढोल ताशों के साथ निकाली जाएगी,जो कालेज से भीम चौक होते हुए मां महामाया चौक, पुराना बस स्टैंड, गज किला परिसर होते हुए अमर शहीद नूतन सोनी हाई स्कूल परिसर पहुंचकर संपन्न होगी।

6 नए जिलों में खेल अधिकारियों के पदों की मंजूरी

बिलासपुर/नवप्रदेश। राज्य शासन ने खेल गतिविधियों के सुचारू संचालन के लिए 6 नए जिलों गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, खैरागढ़-छुईखदान-गंडई, मोहला-मानपुर-अंबागढ़-चौकी, सारंगढ़-बिलाईगढ़, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर और सक्ती में खेल अधिकारी के नए पदों को मंजूरी दी है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा मंत्रालय से विगत 4 अगस्त को इन पदों की मंजूरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित

बिलासपुर/नवप्रदेश। भारत सरकार, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2027 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार हेतु ऑनलाइन नामांकन आमंत्रित किये गये है। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर 2026 तक है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता, मापदंड तथा नामांकन की प्रक्रिया निर्धारित पोर्टल अवार्ड्स डॉट जीओवी डॉट इन पर उपलब्ध है।

पेट के निचले हिस्से में दर्द व पेट में बढ़ रही गांठ से पीड़ित थीं

सिम्स में पहली बार 78 वर्षीय महिला मरीज के अंडाशय कैंसर ट्यूमर की सर्जरी

बिलासपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान (सिम्स), बिलासपुर के स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग ने एक अत्यंत जटिल एवं चुनौतीपूर्ण कैंसर शल्य चिकित्सा को सफलतापूर्वक संपन्न कर 78 वर्षीय महिला मरीज को नया जीवन प्रदान किया। मरीज , निवासी दर्रीघाट, बिलासपुर, पिछले 5-6 महीनों से पेट के निचले हिस्से में लगातार दर्द तथा पेट में तेजी से बढ़ रही विशाल गांठ से पीड़ित थीं।

लगातार परेशानी के कारण मरीज पहले निजी अस्पताल पहुंचीं, जहां जांच के बाद ऑपरेशन एवं उपचार पर लगभग 2 से 3 लाख रुपये तक का खर्च बताया गया। आर्थिक स्थिति के कारण परिजन चिंतित हो गए। इसके बाद मरीज को सिम्स, बिलासपुर लाया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परीक्षण के उपरांत आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका संपूर्ण उपचार एवं ऑपरेशन निःशुल्क किया गया। विस्तृत जांच के दौरान चिकित्सकों ने पाया कि मरीज रजोनिवृत्ति के बाद की अवस्था में थीं तथा उनके बाएं अंडाशय में लगभग 15म12म10 सेंटीमीटर आकार एवं लगभग 1 किलोग्राम वज़न का कैंसरयुक्त ट्यूमर विकसित हो चुका था। ट्यूमर के बड़े आकार के कारण आसपास के महत्वपूर्ण अंगों पर दबाव पड़ रहा था। इसकी जानकारी रेडियोलॉजी विभागाध्यक्ष डॉ. अर्चना सिंह द्वारा सोनोग्राफी जांच के माध्यम से प्राप्त हुई, जिसके आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि शल्य चिकित्सा अत्यंत जटिल एवं उच्च जोखिम वाली होगी। विशेषज्ञ चिकित्सकों की बहुविषयक टीम द्वारा मरीज का समुचित मूल्यांकन कर 03 अगस्त 2026 को कैंसर की चरण निर्धारण शल्य चिकित्सा, ट्यूमर भार कम करने की शल्य चिकित्सा, गर्भाशय एवं दोनों अंडाशयों को निकालने की शल्य चिकित्सा, बाईं मूत्रवाहिनी की मरम्मत तथा बाईं मूत्रवाहिनी में डबल-जे स्टेंट प्रत्यारोपण जैसी जटिल शल्य प्रक्रियाएं सफलतापूर्वक संपन्न की गईं। इस सफल ऑपरेशन में गायनेकोलॉजिकल सर्जरी टीम के डॉ. संगीता रमन जोगी (विभागाध्यक्ष एवं प्रोफेसर), डॉ. दीपिका, डॉ. सौम्या एवं डॉ. वर्षा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जनरल सर्जरी विभाग से डॉ. रघुराज सिंह (प्रोफेसर), डॉ. बी. डी. तिवारी (असिस्टेंट प्रोफेसर) एवं डॉ. गरिमा ने सहयोग प्रदान किया।

आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं व विशेषज्ञ चिकित्सकों की दक्षता से उपचार संभव: डॉ. रमणेश मूर्ति

सिम्स के अधिष्ठाता डॉ. रमणेश मूर्ति ने कहा कि रजोनिवृत्ति के बाद इस आकार का अंडाशय कैंसर ट्यूमर अत्यंत दुर्लभ एवं उच्च जोखिम वाली स्थिति होती है। ऐसे मामलों में शीघ्र एवं सटीक निदान, बहुविषयक विशेषज्ञों का समन्वय तथा उन्नत कैंसर शल्य चिकित्सा रोगी के जीवन की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सिम्स में उपलब्ध आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की दक्षता के कारण इस प्रकार के जटिल मामलों का सफल उपचार संभव हो रहा है। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को उच्चस्तरीय उपचार नि:शुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे जरूरतमंद मरीजों को बड़ी राहत मिल रही है। सिम्स के चिकित्सा अधीक्षक डॉ. लखन सिंह ने बताया कि इतने बड़े अंडाशय ट्यूमर की शल्य चिकित्सा के दौरान अत्यधिक रक्तस्राव तथा मूत्रवाहिनी, मूत्राशय एवं आंत जैसे महत्वपूर्ण अंगों को क्षति पहुंचने की संभावना बनी रहती है। ऐसे मामलों में उच्च स्तरीय शल्य कौशल, सटीक संज्ञाहरण प्रबंधन तथा ऑपरेशन के दौरान निरंतर निगरानी अत्यंत आवश्यक होती है। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने सभी चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए ट्यूमर को सुरक्षित रूप से निकालकर मरीज को नया जीवन प्रदान किया। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति लगातार संतोषजनक है तथा वे चिकित्सकीय निगरानी में स्वास्थ्य लाभ कर रही हैं। मरीज के परिजनों ने सफल एवं जीवनरक्षक उपचार तथा आयुष्मान योजना के अंतर्गत नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सिम्स के चिकित्सकों एवं समस्त स्वास्थ्यकर्मियों के प्रति आभार व्यक्त किया।

दीनदयाल उपाध्याय गार्डन के अधूरे विकास कार्यों से लोग परेशान

15 से पहले व्यवस्थाएं दुरूस्त करने की मांग

बिलासपुर/नवप्रदेश। नगर पालिका निगम बिलासपुर छत्तीसगढ़ द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय गार्डन में चल रहे विकास कार्य लगभग 2 माह से बंद होने के कारण वरिष्ठ नागरिकों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बुजुर्ग एवं बच्चे गिर रहे हैं।

नवनिर्मित योग सेड में लाइट एवं पंखा ना होने के कारण योगा करने वालों को भीषण गर्मी एवं उमस का सामना करना पड़ रहा है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। मुख्य पथ पर गिट्टी, रेती पड़े होने के कारण बुजुर्ग दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं पर नगर निगम में कई शिकायती होने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। अधिकारी बुजुर्गों की समस्या सुनने को तैयार नहीं है। लाफ्टर क्लब, योग क्लब एवं मेलोडी क्लब तथा यंग स्टार क्लब, मॉर्निंग वॉक क्लब इन सदस्यों द्वारा मांग किया जा रहा है कि इस पर गंभीरता से विचार करते हुए 15 अगस्त के पूर्व गार्डन को व्यवस्थित किया जाए ताकि बुजुर्ग एवं क्लब वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम सफलतापूर्वक कर सके। फ्लैग पोस्ट अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है उसमें 15 अगस्त को ध्वजारोहण किस प्रकार किया जाएगा यह प्रश्न वाचक है। पूर्व में भी महापौर के गार्डन निरीक्षण के दौरान लोगों के द्वारा मांग किया गया था कि ओपन जिम का मरम्मत कराया जाए एवं नया लगाया जाए तथा बैठने के लिए गार्डन में चेयर के नीचे कंक्रीट कार्य करवाया जाए ताकि बरसात में लोग आसानी से बैठ पाए परंतु निगम द्वारा अनावश्यक कार्य को ज्यादा प्राथमिकता दिया गया एवं नागरिकों के मांग पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है अतः निगम प्रशासन से मांग है कि इस पर पूरा विचार किया जाए। अनूप कुमार सोनी और सभी योग क्लब, लाफ्टर क्लब द्वारा मांग किया गया कि नागरिकों के मांग अनुसार अति शीघ्र कार्रवाई किया जाए ताकि जन आंदोलन की स्थिति न उत्पन्न हो।

पौधरोपण के साथ छात्रों ने लिया पर्यावरण संरक्षण का संकल्प, सैनिकों के लिए बनाएंगे रक्षा सूत्र

गतौरा स्कूल में पर्यावरण एवं देशभक्ति पर विशेष कार्यक्रम

बिलासपुर/नवप्रदेश। शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल गतौरा में पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति को समर्पित विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने पौधरोपण कर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया, वहीं सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 'ऑपरेशन सिपाही-रक्षा सूत्र' अभियान में भागीदारी का संकल्प भी व्यक्त किया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य रमेश चौधरी ने की। इस अवसर पर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स, बिलासपुर की पदेन जिला संगठन आयुक्त (गाइड) एवं व्याख्याता डॉ. पूनम सिंह, व्याख्याता आरती कश्यप, शालिनी पाल तथा विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाएं और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे। प्राचार्य रमेश चौधरी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि 'एक पेड़, एक जीवन। आज लगाया गया हर पौधा आने वाले समय में हमें शुद्ध हवा और हरियाली प्रदान करेगा।' इसके बाद विद्यालय परिसर में नीम, पीपल, बरगद और विभिन्न फलदार पौधों का रोपण किया गया। कार्यक्रम में डॉ. पूनम सिंह ने 'ऑपरेशन सिपाही-रक्षा सूत्र' अभियान की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों से घर में उपलब्ध सामग्री और मौली धागे से स्वयं रक्षा सूत्र तैयार करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि रक्षा सूत्र के साथ एक चुटकी मिट्टी और अपने हाथों से लिखा देशभक्ति एवं आभार का पत्र लिफाफे में रखकर सीमा पर तैनात सैनिकों तक भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह अभियान देश के वीर जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का अनूठा अवसर है तथा विद्यार्थियों से इसमें बढ़-चढ़कर भाग लेने की अपील की। कार्यक्रम के अंत में सभी विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, अधिक से अधिक पौधे लगाने तथा राष्ट्र सेवा के प्रति सदैव समर्पित रहने की शपथ ली।

घर में घुसकर हमला करने का आरोप, पीड़ित ने एसएसपी से लगाई निष्पक्ष जांच की गुहार

गुड़ी निवासी ने सरपंच समेत 20 से अधिक लोगों पर मारपीट का लगाया आरोप, थाना प्रभारी बोले- एक पक्ष की एफआईआर दर्ज, दूसरे पक्ष ने अब तक नहीं कराई रिपोर्ट

सीपत/नवप्रदेश। सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम गुड़ी निवासी लखन लाल साहू ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय बिलासपुर पहुंचकर शिकायत पत्र सौंपते हुए गांव के सरपंच समेत 20 से अधिक लोगों पर घर में घुसकर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार 29 जुलाई 2026 की रात लखन लाल साहू अपनी पत्नी के साथ घर पर मौजूद थे। इसी दौरान उनकी पत्नी मवेशियों को चारा डाल रही थीं। आरोप है कि गांव के सरपंच दुर्गा प्रसाद साहू के साथ जागेश्वर उर्फ बल्लू साहू, नरोत्तम साहू, शुभम साहू, पूजा साहू, रेवती साहू, लक्की साहू, लल्लन साहू, समारू विश्वकर्मा सहित करीब 20 अन्य लोग जबरन दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए। इसके बाद आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए डंडे, ईंट, पत्थर और लोहे की रॉड से पति-पत्नी पर हमला कर दिया। लखन साहू ने बताया कि शोर सुनकर उनका बड़ा भाई मौके पर पहुंचा और बीच-बचाव किया। सूचना मिलने पर पुलिस डायल-112 की टीम पहुंची और गंभीर रूप से घायल उनकी पत्नी को उपचार के लिए सिम्स अस्पताल भेजा गया, जहां वह बेहोश हो गई थीं। एक दिन बाद उन्हें होश आया। वर्तमान में उनका इलाज शहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है और उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित का आरोप है कि दबाव के चलते सीपत थाने में उनके खिलाफ ही अपराध दर्ज कर लिया गया। उन्होंने शिकायत में बताया कि सरपंच दुर्गा साहू के साथ मारपीट और छेड़छाड़ से जुड़ा एक प्रकरण पहले से न्यायालय में लंबित है। इसके अलावा उनके मकान को तोड़े जाने की कार्रवाई के खिलाफ उन्होंने न्यायालय में स्थगन आदेश मिला है। इसी रंजिश के चलते सरपंच और उनके समर्थकों ने हमला किया। लखन लाल साहू ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की है।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद से आरोपी लगातार उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जिससे पूरा परिवार भय के माहौल में जीने को मजबूर है। सीपत थाना प्रभारी राजेश मिश्रा का कहना है कि गुड़ी में दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था जिसमे सरपंच के पक्ष ने थाना आकर एफआईआर दर्ज कराया है वही दूसरे पक्ष लखन लाल साहू ने आज पर्यंत दिनांक तक थाना में एफआईआर दर्ज नही कराया है।

रिपोर्ट: जून की तुलना में जुलाई में बिजली खपत में 28.88 फीसदी कमी, निगम ने मानसून को बताया प्रमुख कारण

'स्मार्ट मीटर से नहीं बढ़ा बिल, 81 फीसदी उपभोक्ताओं की बिजली खपत 4 सौ यूनिट तक'

बिलासपुर/नवप्रदेश। स्मार्ट मीटर को लेकर चल रही राजनीतिक बहस और उपभोक्ताओं के बीच फैली आशंकाओं के बीच छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल) ने दावा किया है कि बिलासपुर नगर वृत्त में स्मार्ट मीटरधारी अधिकांश घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कमी आई है। कंपनी के अनुसार जुलाई-2026 के तुलनात्मक अध्ययन में 81 प्रतिशत उपभोक्ताओं की बिजली खपत 400 यूनिट तक रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस स्मार्ट मीटर के विरोध में राज्यव्यापी 'घर-घर अभियान' चला रही है।

सीएसपीडीसीएल द्वारा जून और जुलाई-2026 के आंकड़ों के तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार बिलासपुर नगर वृत्त में कुल 86,568 स्मार्ट मीटरधारी घरेलू उपभोक्ता हैं। इनमें से जुलाई में 70,368 उपभोक्ता (करीब 81 प्रतिशत) 400 यूनिट तक बिजली खपत वाले वर्ग में रहे। जून में यह संख्या 55,392 थी। यानी इस श्रेणी में उपभोक्ताओं की संख्या 27.04 प्रतिशत बढ़ी है। कंपनी के अनुसार जुलाई-2026 में कुल बिजली खपत 25.56 मिलियन यूनिट (एमयू) दर्ज की गई, जबकि जून-2026 में यह 35.94 मिलियन यूनिट थी। इस प्रकार एक माह में कुल बिजली खपत में 28.88 प्रतिशत की कमी आई। आंकड़ों के मुताबिक 400 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं की कुल खपत जून के 10.00 मिलियन यूनिट से बढ़कर जुलाई में 12.28 मिलियन यूनिट हो गई। वहीं 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 31,176 से घटकर 16,200 रह गई, जो 48.04 प्रतिशत की कमी है। इस वर्ग की कुल बिजली खपत भी 25.93 मिलियन यूनिट से घटकर 13.27 मिलियन यूनिट दर्ज की गई। सबसे अधिक गिरावट 600 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं के वर्ग में दर्ज की गई। इस श्रेणी में उपभोक्ताओं की संख्या में 60.14 प्रतिशत तथा बिजली खपत में 53.81 प्रतिशत की कमी आई है। सीएसपीडीसीएल का कहना है कि बिजली खपत में कमी का मुख्य कारण मानसून के दौरान तापमान में गिरावट है। मौसम ठंडा होने से एयर कंडीशनर, कूलर और अन्य विद्युत उपकरणों का उपयोग कम हुआ, जिससे बिजली की खपत स्वाभाविक रूप से घटी। बिलासपुर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक ए.के. अंबस्थ ने कहा कि सभी आंकड़े स्मार्ट मीटरधारी घरेलू उपभोक्ताओं की वास्तविक मीटर रीडिंग पर आधारित हैं। उनके अनुसार इससे यह स्पष्ट होता है कि स्मार्ट मीटर तेज चलने की धारणा तथ्यहीन है और मीटर वास्तविक बिजली खपत के अनुरूप ही रीडिंग दर्ज करता है। दूसरी ओर स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस का राज्यव्यापी अभियान जारी है, जिससे इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है।

पर्यावरण प्रेमी मंच ने रोपे पौधे

बिलासपुर/नवप्रदेश। मंच के अध्यक्ष सुदेश दुबे साथी एवं महासचिव अमीन मुगल ने बताया कि खमतराई हाई स्कूल में वटवृक्ष का पौधा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मध्यप्रदेश डा श्रीधर मिश्र चतरु बाबू की स्मृति में रोपित किया गया। इस अवसर पर शिवा मिश्र, राजेश शुक्ल, खमतराई वार्ड क्रमांक 58 कांग्रेस प्रत्याशी मनीष सेंगर अशोक सूर्यवंशी अमित नानू, अलका गौरहा, अरूणा पान्डेय, मिनाक्षी त्रिवेदी, जया बिसेन दीप्ति जावलकर नसरीन बानो, राजकिशोरी तिर्की, बाबी थामस, सिद्धांत दुबे, भरत जुर्यानी, संजय सोनी, रिंकू छाबड़ा, अमीन मुगल एवं सुदेश दुबे साथी शामिल रहे।

सुविचार

प्रार्थना ऐसे करो जैसे सब कुछ भगवान पर निर्भर है लेकिन प्रयास ऐसा करो जैसे सब कुछ आप पर निर्भर है।

पीडीए की नई परिभाषा

उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ माह ही शेष रह गये हैं। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमों अखिलेश यादव जहां संसद में चंदा चोरी के मुद्दे को लेकर भाजपा पर निशाना साध रहे हैं और इसे लेकर संसद के बाहर लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद प्रदर्शन कर रहे हैं जिसे अब कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन में शामिल अन्य दलों का भी समर्थन मिल रहा है यहां तक की नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जो जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर आक्रामक रूख अपनाये हुए थे वे भी समाजवादी पार्टी के सूर में सूर मिलाते हुए संसद के बाहर चंदा चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं। इसी प्रदर्शन के दौरान निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने साधू के वेश में चंदा चोरी का नाटक करके साधु संतो की नाराजगी मोल ले ली थी। जिन्होंने पप्पू यादव के साथ ही समाजवादी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा था। जब यह बात अखिलेश यादव के समझ में आई तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल के लिए ब्राम्हण जाति को साधने के लिए अपने पीडीए की परिभाषा फिर एक बार बदल ली पहले वे पीडीए का अर्थ पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताते थे बाद में उन्होंने ए का मतलब अल्पसंख्यक की जगह अगड़ा बताना शुरू कर दिया था और अब उन्होंने पीडीए में पी का मतलब पंडित बताया है। उन्होंने योगी सरकार पर ब्राम्हण समाज के साथ अन्याय करने का भी आरोप लगाया है और दावा किया है कि पीडीए ही ब्राम्हणों के हितों की रक्षा करेगा। दरअसल अखिलेश यादव अपना जनाधार उत्तरप्रदेश में कमजोर पड़ता जा रहा है। वहां का पिछड़ा वर्ग भाजपा के साथ रहा है सिर्फ यादव समाज ही समाजवादी पार्टी का समर्थक है लेकिन इसमें भी भाजपा सेंध लगा रही है। दलित वोट बैंक भी समाजवादी पार्टी से छिटकने का खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमों मायावती इस बार उत्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव पुरी ताकत से लड़ने जा रही हैं। यह चुनाव मायावती के लिए करो या मरो वाला है। मायावती जानती है कि यदि इस बार भ उनकी पार्टी का प्रदर्शन कमजोर रहा तो उनकी राजनीति ही खत्म हो जाएगी। आज भी उनके साथ दलित समाज का एक बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है। जाहिर है मायावती समाजवादी पार्टी का खेल बिगाड़ेंगी वे न सिर्फ दलित वोट को बल्कि मुस्लिम वोट को भी समाजवादी पार्टी के पाले से अपनी ओर खींच सकती हैं। समाजवादी पार्टी के परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक में भी इस बार अस्सद्दुदीन ओवैसी सेंध लगाने जा रहे हैं। उन्होंने पहले समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने की अपील की थी लेकिन कांग्रेस के विरोध के कारण अखिलेश यादव ओवैसी के साथ हाथ मिलाने में हिचक रहे हैं। अलग होकर चुनाव लड़ते हैं तो निश्चित रूप से वे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में नुकसान पहुंचाएंगे। भले ही वे पिछले विधानसभा चुनाव की तरह एक भी सीट न जीत पाये लेकिन कई सीटों पर चुनावी गण्ति को गड़बड़ा देंगे। यही वजह है कि अब अखिलेश यादव ने पीडीए की नई परिभाषा गढ़ी है। और पी का मंतलब पंडित बताकर ब्राम्हणों सहित अन्य अगड़ी जातियों को अपने पालें में लाने की कवायद कर रहे हैं। बिहार विधानसभा की बाकींपुर सीट पर हुए उपचुनाव में इस तरह से जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने अगड़ा बाहुल पीठ पर भाजपा को पराजित किया है। उससे भी अखिलेश यादव उत्साहित हो गये हैं। उन्हें लग रहा है कि अब अगड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे को लेकर भाजपा से नाराज हो गया है। ऐसे में स्वर्ण वोटों को साधने का उन्हें अनुकूल अवसर नजर आ रहा है। इसमें उन्हें इतनी सफलता मिलती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा।

आतंकी माड्यूल का खुलासा ; सतर्कता जरूरी

पंजाब पुलिस ने एक आतंकी माड्यूल का खुलासा करते हुए चार नाबालिग सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया है। जिनके पास से अवैध हथियार भी जब्त हुए हैं। पंजाब पुलिस के मुताबिक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान वहां बम फेकने की योजना बनाई गई थी। आतंकी माड्यूल के इस खुलासे के बाद संसनीय फैल गई है। एक बड़ा आतंकी हमला होने से बच गया है। यदि जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन और लंबा चलता तो वहां आंतकी वारदात हो जाती। पंजाब पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनसे पुछताछ में उनसे कई चौकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। यह ठीक है कि फिल्हाल तो खतरा टल गया है लेकिन देश को बहलाने की साजिश आगे भी हो सकती है। इसलिए अतिरिक्त सर्तकता बरतना निहायत जरूरी है। पंजाब की तरह ही बंगाल में भी आतंकी माड्यूल का खुलासा हुआ है। जाहिर है पड़ौसी देश पाकिस्तान भारत में इसी आंतकी घटना को अंजाम देने की फिराक में है और इसके लिए वह भारत में ही रहने वाले गद्दारों को मोहरा बना रहा है और इनमें भी वह नाबालिग बच्चों का सहारा ले रहा है। ऐसे में जम्मू कश्मीर, बंगाल और नई दिल्ली सहित देश के अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतेजाम करना आवश्यक है और संदिग्धों के खिलाफ युद्धस्तर पर अभियान भी चलाना होगा। तभी पाक के नापाक मंसूबे नाकाम होंगे और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर जो खतरा पैदा हुआ है वह दूर होगा।

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1880 - उचित वक्ता पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र द्वारा प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। 1996 - अमेरिकी वैज्ञानिकों द्वारा 13 हज़ार वर्ष पूर्व पृथ्वी पर गिरे उल्का पिंड के अवशेषों से मंगल ग्रह पर एक कोशिका वाले जीवों के होने की संभावना का पता चला। 1998 - केन्या एवं तंजानिया की राजधानियों में स्थित अमेरिकी दूतावासों पर आतंकवादी हमले में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु। 1999 - पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ़ ने एक बार फिर भारत से वार्ता की पेशकश की। 2000 - रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन द्वारा एक क़ानून पर हस्ताक्षर कर अपनी शक्ति का विस्तार। 2003 - बगदाद में जार्डन दूतावास के बाहर हुए कार बम विस्फोट में 12 लोगों की मृत्यु। 2005 - इस्रायल के वित्तमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया। 2008 - सार्वजनिक क्षेत्र के देना बैंक ने अपनी प्रधान ब्याज दरें 0.75% बढ़ाकर 14.25% करने की घोषणा की।

गरीब किसानों के मसीहा डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन

डॉ देवेन्द्र नाथ शर्मा
शिक्षाविद

हरित क्रांति से एवरग्रीन रिवोल्यूशन तक

सरकार का उच्चतम नेतृत्व यदि किसी वैज्ञानिक को शोध एवं अनुसंधान की पूरी स्वतंत्रता दे, देश की समस्याओं के समाधान के लिए उसके संकल्प पर विश्वास करे और आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए, तो वह वैज्ञानिक अपनी पूरी ऊर्जा राष्ट्र के उत्थान में समर्पित कर सकता है। इस सत्य को साकार किया 1960 के दशक में किसानों के मसीहा बने कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन ने। हरित क्रांति के माध्यम से उन्होंने भारत को भुखमरी से बचाया और खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया। देश उनका सदैव ऋणी रहेगा।

खाद्य संकट की घड़ी

1960 के दशक में बढ़ती जनसंख्या, सूखा और अकाल ने भारत की खाद्यान्न स्थिति को बेहद गंभीर बना दिया था। 1965-66 के भीषण सूखे ने संकट को और गहरा कर दिया। पारंपरिक खेती पुराने बीजों, वर्षा पर निर्भरता और सीमित सिंचाई पर आधारित थी, जिससे प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम रहता था। 1970 के दशक के आरंभ तक भारत अपने नागरिकों का पेट भरने के लिए विदेश से आयातित अनाज पर निर्भर था। अमेरिका से पीएल-480 योजना के तहत गेहूँ मँगाना पड़ता था। उस समय देश की सबसे बड़ी आवश्यकता थी–खाद्यान्न उत्पादन को कई गुना बढ़ाना। यदि ऐसा न होता, तो भूख और खाद्य असुरक्षा गंभीर संकट बन सकती थी।

हरित क्रांति की नींव

इसी चुनौतीपूर्ण काल में डॉ. मनकोम्बु संबासिवन स्वामीनाथन ने निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के सहयोग से भारत के वातावरण के अनुकूल उच्च उपज वाली गेहूँ की किस्में विकसित करने का कार्य शुरू किया। बोरलॉग से मैक्सिकन अर्ध-बौनी किस्में प्राप्त की गईं और भारत में उनकी व्यवहार्यता का परीक्षण किया गया। ये किस्में उच्च उपज देने वाली होने के साथ-साथ रोग-प्रतिरोधी भी साबित हुईं। स्वामीनाथन ने विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा के किसानों को इन किस्मों को अपनाने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि इन राज्यों में गेहूँ की खेती के लिए अनुकूल जलवायु थी।

1966 में उन्होंने भारतीय सरकार को मैक्सिको से 18,000 टन उच्च उपज वाले बीज खरीदने के लिए राजी किया। इन बीजों के आने के साथ ही भारत में हरित क्रांति का शुभारंभ हुआ। परिणाम चमत्कारी

रहे। मैक्सिकन गेहूँ की किस्में अपनाने वाले किसानों की पैदावार और मुनाफा तेजी से बढ़ा। भारत का गेहूँ उत्पादन 1964 में लगभग 12 मिलियन टन से बढ़कर 1970 में लगभग 20 मिलियन टन हो गया। इसके बाद सरकार ने देश को अनाज उत्पादन में आत्मनिर्भर घोषित कर दिया। आधुनिक कृषि पद्धतियाँ–उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग, उन्नत सिंचाई तकनीकें तथा मशीनीकरण–इसके बाद देश के अधिकांश राज्यों में तेजी से अपनाई जाने लगीं। गेहूँ उत्पादन में सफलता ने चावल की खेती में भी प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। स्वामीनाथन ने चावल की कई उन्नत किस्में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे चावल उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न संकट से उबारकर आत्मनिर्भर बनाया और खाद्य सुरक्षा को मजबूत नींव प्रदान की। सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खाद्य भंडारण व्यवस्था सुदृढ़ हुई। आज भारत विश्व के प्रमुख खाद्यान्न उत्पादक देशों में शामिल है।

एवरग्रीन रिवोल्यूशन

हरित क्रांति ने क्रांतिकारी बदलाव लाया, किंतु कई चुनौतियाँ भी खड़ी कीं। इसका लाभ मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे सिंचित क्षेत्रों तक सीमित रहा। छोटे और सीमांत किसानों को अपेक्षाकृत कम लाभ मिला। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता प्रभावित हुई, भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ, जैव विविधता घटी और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ा। कृषि लागत भी बढ़ गई। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए स्वामीनाथन ने 'एवरग्रीन रिवोल्यूशन' (सदाबहार क्रांति) का विचार प्रस्तुत किया। इसके अंतर्गत कम पानी में अधिक उत्पादन, जैविक एवं प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य में सुधार, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल कृषि तथा छोटे किसानों की आर्थिक सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। उद्देश्य था–प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट किए बिना दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

जीवन परिचय

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में एक कृषक परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने कम फसल उत्पादन के कारण कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की गरीबी को प्रत्यक्ष देखा। परिवार उन्हें सर्जन बनाना चाहता था, किंतु 1943 के बंगाल अकाल (जिसमें लाखों लोग मारे गए) ने उन्हें भारत के खाद्य संकट से निपटने के लिए प्रेरित किया। परिणामस्वरूप उन्होंने कृषि विज्ञान में करियर चुना।

1944 से 1954 तक के शैक्षणिक सफर में उन्होंने आनुवंशिकी और पादप प्रजनन में डॉक्टरेट तथा पोस्ट-डॉक्टरेट सहित कई डिग्रियाँ प्राप्त कीं। 1949 में यूनेस्को ने आलू की फसल को पाले और कीटों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाने के शोध के लिए उन्हें फैलोशिप दी। 1954 में उन्होंने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई) में कार्य आरंभ किया, जहाँ उनका अधिकांश शोध उर्वरकों और उन्नत किस्मों के माध्यम से चावल तथा गेहूँ के उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित रहा।

1950 के दशक में मेक्सिको में नॉर्मन बोरलॉग की सफलता के बारे में जानकर वे प्रेरित हुए। बोरलॉग द्वारा विकसित अर्ध-बौनी गेहूँ की किस्मों ने मेक्सिको को आयात-निर्भर देश से आत्मनिर्भर गेहूँ उत्पादक में बदल दिया था। इसी सफलता से प्रेरित होकर उन्होंने भारत में हरित क्रांति की नींव रखी।

पद और जिम्मेदारियां

स्वामीनाथन 1961 से 1972 तक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक, 1972 से 1979 तक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के महानिदेशक तथा 1982 से 1988 तक फिलीपींस के लॉस बान्योस स्थित अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक रहे। वे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष तथा 1989 से 1996 तक विश्व वन्यजीव कोष (भारत) के अध्यक्ष भी रहे। 2004 से 2006 तक राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष और 2007 से 2013 तक राज्यसभा सदस्य रहे। 1988 में उन्होंने एम. एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की, जो स्वयं को गरीब-समर्थक, महिला-समर्थक और प्रकृति-समर्थक संगठन के रूप में परिभाषित करता है तथा कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए विज्ञान व प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।

सम्मान

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन को उनके अमूल्य योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया। भारत सरकार ने उन्हें 1967 में पद्म श्री, 1972 में पद्म भूषण तथा 1989 में पद्म विभूषण से विभूषित किया। 1971 में फिलीपींस की रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया।

भाजपा: गलत निर्णयों की भरमार का दुष्परिणाम

राजीव खंडेलवाल

बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार चयन को लेकर हुई रणनीतिक भूल की तरह दतिया में भी भाजपा ने पिछले चुनाव के स्थापित, चिर-परिचित उम्मीदवार को बदलकर मानो "अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली।"इसी एक निर्णय ने "हार की नींव" उसी दिन रख दी थी।

मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में शामिल रहे भाजपा के वरिष्ठ कद्दावर नेता एवं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, जो पिछले चुनाव में मात्र लगभग 7 हजार मतों से पराजित हुए थे, का टिकट काटने का तो कोई ठोस, उचित और विश्वसनीय कारण कार्यकर्ताओं न तो बताया गया, और न ही उन्हें ÷मनाने÷ का गंभीर प्रयास हुआ। उनका दिल्ली दौरे में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात न हो पाना भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा।

स्थिति तब और बिगड़ गई, जब टिकट कटने के विरोध में जिला संगठन के अधिकांश पदाधिकारियों ने "सामूहिक इस्तीफे" दे दिए। इसके बावजूद पार्टी नेतृत्व ने 'असंतुष्ट' नरोत्तम मिश्रा को संगठन अथवा सरकार में कोई सम्मानजनक जिम्मेदारी देकर "संतुष्ट" कर नाराजगी दूर करने की कोशिश नहीं की। परिणामतः "बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहां से होय।"

नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटना: हार का सबसे बड़ा कारण?

मीडिया में सूत्रों के हवाले से यही कारण आया कि पार्टी के आंतरिक सर्वे में नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि जिन आशुतोष तिवारी को उनका स्थान दिया गया, क्या उनका भी उतना ही व्यापक सर्वे कराया गया था?

राजनीति में जब किसी स्थापित नेता का टिकट काटना होता है, तो सबसे आसान तर्क "तथाकथित सर्वे" ही बन जाता है। पर यदि सर्वे ही "ब्रह्मवाक्य" होता अंतिम सत्य हो तो अनेक चुनावी परिणाम उसके विपरीत क्यों आते?

वस्तुतः नरोत्तम मिश्रा के लिए "कुआं-खाई" जैसी स्थिति थी, तो भाजपा नेतृत्व "ऊहापोह" में फंसा था। शायद इसीलिए नामांकन के अंतिम दिन भाजपा उम्मीदवार की घोषणा हुई। "आखिरी समय में आनन-फानन" का फैसला अक्सर "गले की हड्डी" बन जाता है।

कांग्रेस की अधिकांश मोर्चों पर भाजपा पर बढ़त

अपेक्षाकृत ज्यादा गुटबाजी से ग्रस्त कांग्रेस ने यहां 2 दिन पहले ही उम्मीदवार घोषित कर भाजपा से "बाजी मार ली"। लंबे समय बाद ऐसा चुनाव देखने को मिला, जिसमें कांग्रेस अपेक्षाकृत "व्यवस्थित" दिखी और भाजपा "अव्यवस्थित" हो गई।

यद्यपि संसाधनों और बूथ प्रबंधन में भाजपा की दक्षता निर्विवाद है, लेकिन इस चुनाव में "जन ने "तंत्र" पर भारी पड़ने" का संदेश दे दिया।

नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटते ही भाजपा में भीतरघात की चर्चा "आम" हो गई थी। इससे निपटने की जिम्मेदारी प्रदेश नेतृत्व की थी, जिस पहली परीक्षा में ही वे असफल (फेल) हो गये। परिणाम आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का कथन कि "यदि कोई दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी" - इसका सीधा मतलब पार्टी अभी तक दोषी ही तय नहीं कर पाई।

4 अगस्त को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने जांच के लिए दो सदस्यीय समिति बनाई। आश्चर्यजनक रूप से समिति ने मात्र 6-7 घंटों में, दतिया विधानसभा क्षेत्र का दौरा किए बिना ही पूरे जिला संगठन को भंग करने की अनुशंसा कर दी। प्रदेश अध्यक्ष ने तुरंत आदेश जारी कर दिया। सवाल उठता स्वभाविक है कि क्या यह समस्या के समाधान का प्रयास था या सिर्फ "बलि का बकरा" खोजने की कवायद?

यदि चुनावी प्रबंधन में भी ऐसी ही "बुलेट ट्रेन जैसी त्वरित गति की "फुर्ती" दिखाई जाती, तो शायद परिणाम कुछ और होते।

दूसरी ओर कांग्रेस ने मतदान समाप्त होते ही, परिणाम आने से पहले ही पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। स्पष्ट है कि कांग्रेस नेतृत्व पूरे घटनाक्रम पर "बाज की नजर÷ रखे हुए था। विजयी प्रत्याशी ने भी "भीतरघात" की शिकायत पार्टी नेतृत्व से की थी।

भीतरघात: किसे कितना नुकसान ?

भीतरघात दोनों दलों में था, पर प्रकृति अलग थी।

भाजपा का "भीतरघात" चुनाव शुरू होते ही "चौराहे पर आ गया" और एक नरैटिव व परसेप्शन बनकर सार्वजनिक विमर्श का विषय बन गया। वहीं कांग्रेस का भीतरघात संगठन की चारदीवारी के "भीतर" ही रहा।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

हुआ सुदामा सा कभी,कब किसका सत्कार। कान्हा जैसा दूसरा,..हुआ नही फिर यार।। बना सुदामा मैं प्रभो,ज्ज्खोजूं सत्य चरित्र। कलियुग में भी श्याम सा, सीधा सच्चा मित्र ।। देख सुदामा मीत को , नजरे फेरें श्याम। बदल गये इस दौर में ,यारी के आयाम ।। जब यारी की नीवं ही,... नफा और नुकसान। चले नही ज्यादा दिवस ,उनकी कभी दुकान ।। रहे वहीं तक मित्रता, ...रहे वहीं तक प्यार जब तक हो व्यवहार में, शामिल नही उधार ।। मीत वही है ख़ास अब, है जो पूर्ण समर्थ। बदल गये हैं वाकई , अब यारी के अर्थ ।। लगे सामने यार के,अगर यार असहाय। यारी वो यारी नहीं, यारी वो व्यवसाय ।।

– रमेश शर्मा वशिष्ट

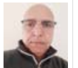

समय को पीछे छोड़ के आया समय को फिर भी आगे पाया समय बदलता पल-पल यारो मैं ही शायद बदल ना पाया। सोच-सोच कर आगे बढ़ता समय चले है, नहीं ठहरता चले चला चल रुक मत अब गया समय फिर नहीं लौटता। – जे डी कुदाल

जश्न की रात थी जिंदगी बारात थी उनींदी पलकें,होंठों पे ठहरी बात थी गुजर गया हर लम्हा मुट्ठी के रेत सी रौशन दीवारें मगर वो गहरी रात थी।

– सपना चन्द्रा

लोग पोस्ट डालते हैं की हिन्दू मंदिर नहीं जाता लेकिन मंदिर में जो दो चार ट्रस्टी होते हैं जैसे लगता है मंदिर उनकी जागीर हो भगवान का घर सभी भक्तों के लिए एक समान होना चाहिए परन्तु प्रसाद देते समय मुंह देखकर प्रसाद देना बड़े मंदिरों की व्यवस्था आम नागरिक के लिए बहुत सारे नियम लेकिन वीआईपी लोगों के लिए सब सहज।

– सुनिल पुष्पराज पांडेय

तृषा कृष्णन पर भद्दे, डबल मीनिंग स्पीच पर उदयनिधि स्टालिन अरेस्ट हो गया.. गलती कर दी.. इसके बदले पीएम की माँ को गाली देता तो शाबाशी और माफी दोनों मिल जाती.. लिबरलों की वाह वाही मिलती वह अलग.. पहली बार आज जोसफविजय के लिए फुल सपोर्ट रहेगा..

– अंबर दानी

फिर गीत पुरवा आने लगीं हैं। बदली नगमे सुनाने लगीं हैं। ठहरे हैं टीलों पे बादल थके से जुगनू तो अब कर रहे रतजगे से वो नीली नीली सलोनी बदलियां रातों में पायल, बजाने लगीं हैं फिर गीत पुरवा... चूनर हवाओं में, लहरा रहीं हैं घटाएं मचलतीं कहाँ जा रहीं हैं रंगीली सजीली, महकती फिज़ाएं किसे ।गुनगुना कर,बुलाने लगीं हैं फिर गीत पुरवा...

– अजय कुमार सिंह भदौरिया

एक जगह वीडियो देख रही थी जिसमें ट्विंकल खन्ना आत्मश्लाघा से परिपूर्ण पूरे जोश और होशो-हवास में कह रही थी कि मेला फ़िल्म करने के बाद मैंने एक्टिंग से सन्यास ले लिया है,मुझे एक्टिंग में कोई खास रूचि नहीं है।इतना ही नहीं आगे कहते हुए गर्व से भावविभोर होकर कहती है कि एक ज्योतिष ने कहा था कि आप एक बेहतरीन उम्दा लेखिका बनेंगी और सच में बन गई। खैर!

– मधुबाला मौर्या

राशि फल

पं. देवव्रत शर्मा

मेष : आज का दिन आपके लिए मिश्रित फल दायक है आज किसी भी कार्य को करने से पहले उसके लाभ अथवा हानि के बारे में विचार अवश्य करें।

वृष: आज के दिन मध्यांन तक आप कर्म करने की अपेक्षा ख्याली पुलाव पकाएंगे। कार्य क्षेत्र पर काम काज होने के बाद भी मन अन्यत्र घूमेगा। परिवार के बुजुर्ग लंबी बीमारी के कारण परेशान होंगे।

मिथुन: आज परिस्थितियां कार्यों में बाधक बनेंगी दिन के आरंभ से ही मन अनर्गल प्रवृतियों में भटकेगा बिना सोचे समझे किए गए कार्य बाद में पश्चाताप का कारण बनेंगे।

कर्क: आज के दिन परिस्थितियां आपके अनुकूल बन रही हैं फिर भी दिन के पूर्वार्ध में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य जल्दबाजी में ना करें अन्यथा हानि होने की संभावना है।

सिंह: आज के दिन आप जिस भी कार्य को करेंगे उसे ले देकर अवश्य ही संतोषजनक स्थिति तक पहुंचा देंगे। दिन के आरंभ में परिवार के बड़े लोग किसी महत्वपूर्ण विषय में आप का विरोध कर सकते हैं।

कन्या: आज का दिन आपके लिए सामान्य लेकिन आप के संपर्क में रहने वालों के लिए अति उत्तम रहेगा आज आप अपनी निजी आवश्यकताओं को अनदेखा कर परिजन एवं अन्य निकटस्थ लोगों की कामना पूर्ति करने के लिए समय एवं धन खर्च करेंगे।

तुला: आज का दिन आप के लिए परिश्रम सध्या ही रहेगा मध्यांन तक प्रत्येक कार्य में अधिक माथापच्ची करनी पड़ेगी लेकिन मध्यान्ह के बाद परिस्थितियां बेहतर बनने लगेंगी आज आप परिश्रम में कमी नहीं करेंगे।

वृश्चिक: आज का दिन आपके लिए शुभ फलदायी है। आज आप लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे लेकिन स्वयं उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे।

धनु: आज के दिन आप पूर्व में की गई गलतियों में सुधार लाएंगे प्रत्येक कार्य सोच समझकर ही करेंगे फिर भी आप के संपर्क में आने वाले लोगों में आप की छवि जिद्दी इंसान जैसी बनेगी।

मकर: आज के दिन आपको अपनी वाणी एवं व्यवहार को संयमित रखने की आवश्यकता है मध्यांन तक किसी के द्वारा बोली गई।

कुंभ: आज का दिन आपके लिए धन लाभ वाला रहेगा। पूर्व में किए परोपकार एवं धार्मिक कार्यों का फल आज किसी न किसी रूप में अवश्य मिलेगा।

मीन: आज के दिन आप का मन भ्रमित रहेगा मुख से कुछ बोलेंगे करेंगे उसका उल्टा ही।

QUIZ TIME

1) किस राज्य में स्थित ग्लॉ झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है?
2) किस देश द्वारा दुनियां का सबसे बड़ा सुपरकंडक्टिंग चुंबक बनाया गया है?
3) भारत में रेयर पृथ्वी तत्व के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है?
4) विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है?
5) किस राज्य के पारंपरिक पिथौरा चित्रकला को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है?

उत्तरमाला- (1) [illegible] (2) चीन (3) राजस्थान (4) 1-7 अगस्त (5) गुजरात

RamaQuiz

पहेली

शब्द सामर्थ्य -122

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 121 का हल

महुआ ने बदली महिलाओं की जिंदगी, वन धन योजना से मिली आत्मनिर्भरता की नई पहचान

रायपुर/नवप्रदेश। जनजातीय कार्य मंत्रालय और ट्राइफेड की एक पहल है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य वनों से लघु वनोपज एकत्र करने वाले आदिवासी समुदायों को प्रशिक्षित करना, उनके उत्पादों का मूल्यवर्धन करना और उन्हें उद्यमी बनाकर स्थायी आजीविका प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिलने वाला महुआ अब ग्रामीण और आदिवासी महिलाओं के लिए आय और आत्मनिर्भरता का मजबूत साधन बन गया है। राज्य शासन की वन धन विकास केंद्र योजना के माध्यम से महिलाओं को महुआ से मूल्यवर्धित उत्पाद बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे उनकी आमदनी बढ़ रही है और वे सफल उद्यमी बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं।

'राजनांदगांव जिले के कोरिनभाठा वन धन विकास केंद्र की सफलता'

राजनांदगांव जिले के कोरिनभाठा वन धन विकास केंद्र की महिलाओं ने इस योजना का पूरा लाभ उठाया है। पहले वे महुआ केवल संग्रह करती थीं, लेकिन अब प्रशिक्षण के बाद महुआ से लड्डू, कुकीज़, एनर्जी बार, स्क्वैश और अन्य उपयोगी उत्पाद तैयार कर रही हैं। आधुनिक प्रसंस्करण और आकर्षक पैकेजिंग के कारण इन उत्पादों की बाजार में अच्छी मांग बन रही है।

'प्रशिक्षण और कौशल विकास'

वन धन विकास केंद्र में महिलाओं को केवल उत्पाद बनाना ही नहीं सिखाया जाता, बल्कि गुणवत्ता, स्वच्छ उत्पादन, पैकेजिंग, लेबलिंग, भंडारण और विपणन की भी जानकारी दी जाती है। इससे वे बाजार की जरूरत के अनुसार बेहतर उत्पाद तैयार कर पा रही हैं और उन्हें उचित मूल्य भी मिल रहा है।

'आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम'

कोरिनभाठा की महिलाओं की यह सफलता दिखाती है कि सही प्रशिक्षण, आधुनिक तकनीक और विपणन सहयोग मिलने पर वन संपदा को रोजगार और समृद्धि का मजबूत आधार बनाया जा सकता है। वन धन विकास केंद्र योजना आज महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा दे रही है।

महुआ के मूल्यवर्धन से बढ़ा रोजगार

महुआ के मूल्यवर्धन से उसकी उपयोगिता और बाजार मूल्य दोनों बढ़े हैं। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। महिलाओं की आय में वृद्धि हुई है और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हुई है। महुआ के फूलों और बीजों के मूल्यवर्धन से ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं की आय कई गुना बढ़ गई है। अब केवल कच्चे महुआ को बेचने के बजाय उससे लड्डू, कुकीज, जैम, और एनर्जी बार जैसे उत्पाद बनाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर नए रोजगार और स्थायी आजीविका के साधन विकसित हुए हैं।

'छत्तीसगढ़ हर्बल्स के माध्यम से बाजार उपलब्धता'

इन उत्पादों को 'छत्तीसगढ़ हर्बल्स' के माध्यम से व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे वन आधारित उत्पादों को नई पहचान मिल रही है और ग्रामीण महिलाओं को अपने उत्पाद बेचने के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य लघु वन उत्पाद संघ की एक अनूठी पहल है। इसके तहत वनों से मिलने वाले प्राकृतिक और शुद्ध उत्पादों जैसे वन शहद, एलोवेरा जेल, हर्बल जूस, महुआ उत्पाद, आयुर्वेदिक चूर्ण और तेलों को महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा तैयार कर बेचा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों और स्थानीय लोगों को आजीविका देना है।

न्यूज गैलरी

'आरुग सम्मान समारोह' का पोस्टर रायपुर प्रेस क्लब में विमोचित

रायपुर/नवप्रदेश। लोककला और पंडवानी परंपरा को समर्पित प्रसिद्ध पंडवानी गायिका स्वर्गीय तीजन बाई की स्मृति में आयोजित होने वाले 'आरुग सम्मान समारोह' के पोस्टर का विमोचन बुधवार को रायपुर प्रेस क्लब में किया गया। यह सम्मान समारोह 7 अगस्त को शहीद स्मारक, रायपुर में आयोजित होगा। कार्यक्रम का आयोजन अलीम बंसी, तीजन बाई के परिवारजनों द्वारा किया जा रहा है। समारोह में लोककला, संस्कृति और पंडवानी की विरासत को आगे बढ़ाने वाले कलाकारों का सम्मान किया जाएगा तथा स्वर्गीय तीजन बाई के कला-साधना से जुड़े अविस्मरणीय योगदान को श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाएगा। पोस्टर विमोचन के अवसर पर रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी , कोषाध्यक्ष दिनेश यदु सहित आयोजन समिति के सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने प्रदेशवासियों एवं कला प्रेमियों से बड़ी संख्या में समारोह में शामिल होकर स्वर्गीय तीजन बाई को श्रद्धांजलि अर्पित करने और कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाने की अपील की।

रायपुर में मारपीट, चोरी और धमकी के कई मामले दर्ज, पुलिस ने शुरू की जांच

रायपुर/नवप्रदेश। राजधानी रायपुर में मंगलवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों में मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, चोरी और घर में सेंधमारी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने सभी मामलों में अपराध कायम कर जांच शुरू कर दी है। तेलीबांधा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति जैकी जगत और उसके साथी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार आरोपी ने पूर्व में दर्ज रिपोर्ट वापस लेने का दबाव बनाते हुए गाली-गलौज की, जान से मारने की धमकी दी और मारपीट कर घायल कर दिया। इसी थाना क्षेत्र के काशीराम नगर में घरेलू विवाद को लेकर दो व्यक्तियों पर डंडे और हाथ-मुक्कों से मारपीट करने का मामला दर्ज किया गया है। खमतराई थाना क्षेत्र के भनपुरी स्थित संतोषी मंदिर के पास शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर युवक से मारपीट और धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। आजाद चौक थाना क्षेत्र में रवि भवन के पास खड़ी हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल चोरी हो गई। वहीं आमानाका थाना क्षेत्र के अरिहंत नगर, सरोना में सूने मकान का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने सोने-चांदी के जेवर, 20 हजार रुपये नकद और सीसीटीवी कैमरा चोरी कर लिया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के लोधीपारा हार्ट बाजार में एक युवक ने आरोप लगाया कि उसे गलत वीडियो दिखाने की बात को लेकर विवाद कर मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। पुलिस ने नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। डीडी नगर थाना क्षेत्र के रायपुरा स्थित महादेव घाट के पास दो व्यापारियों के बीच विवाद मारपीट में बदल गया।

लिव-इन पार्टनर की संदिग्ध मौत आदिवासी छात्रा की हत्या की आशंका

रायपुर/नवप्रदेश। राजधानी रायपुर के बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही आदिवासी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका के शरीर और गले पर चोट के निशान मिले हैं, जिससे मारपीट के बाद गला घोंटकर हत्या किए जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मृतका के साथ रहने वाले छात्र को हिरासत में ले लिया है। घटना मुजगहन थाना क्षेत्र के बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की है। मृतका भारती नेताम (19) पिता रतिराम नेताम, मूल रूप से कांकेर जिले के कोकपुर की रहने वाली थी। वह रायपुर के विकास महाविद्यालय में बीएड की पढ़ाई कर रही थी और पिछले 6-7 महीनों से कोंडागांव के रावतपुरा सरकार महाविद्यालय के छात्र सावंत बघेल के साथ बोरियाकला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में किराए के मकान में लिव-इन में रह रही थी। मृतका की बड़ी बहन देविका नेताम ने पुलिस को बताया कि सावंत बघेल किसी अन्य के संपर्क में होने के संदेह में अक्सर भारती के साथ मारपीट करता था। भारती ने एक दिन पहले फोन करके बताया कि सावंत ने फिर मारपीट की है। वह कोकपुर लौटना चाहती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है, तब उसने ऑनलाइन 3 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे। इसके बाद 4 अगस्त की रात उसे फोन से सूचना मिली कि भारती को मेकाहारा इलाज के लिए ले जाया गया है, जहां उसकी मौत हो गई, जिसके बाद देविका 5 अगस्त को पिता और बहन के साथ रायपुर पहुंची।

हसदेव बराज के कार्यों के लिए 3.83 करोड़ स्वीकृत

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग द्वारा कोरबा जिले के हसदेव बांगो परियोजना के अंतर्गत हसदेव बरॉज गेट दर्री के सभी गेट स्टाप लॉग एवं संबंधित रेग्यूलेटर गेटों तथा उनके हाइस्टींग एरेंजमेंट के मरम्मत एवं पेटिंग कार्य के लिए 3 करोड़ 83 लाख 21 हजार रूपए स्वीकृत किए गए है। योजना के अंतर्गत कार्यों को कराने के लिए मुख्य अभियंता मिनीमाता (हसदेव) बांगो परियोजना जल संसाधन विभाग बिलासपुर को प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

निक्षय मित्र बनकर जशपुर के निरंजन ने जगाई उम्मीद

19 विशेष पिछड़ी जनजातियों सहित 60 टीबी मरीजों को गोद लेकर दे रहे नया जीवन

रायपुर/नवप्रदेश। टीबी केवल एक बीमारी नहीं है, बल्कि यह गरीबी, कुपोषण और सामाजिक उपेक्षा से जुड़ी एक बड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले से एक ऐसी ही प्रेरणादायक और मानवीय पहल सामने आई है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जिला डाटा प्रबंधक निरंजन प्रसाद गुप्ता ने 'निक्षय मित्र' बनकर अनूठी मिसाल पेश की है। उन्होंने दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्रों के टीबी मरीजों को संबल प्रदान कर एक नई राह दिखाई है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के बीच स्वास्थ्य की अलख

जशपुर के पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जैसे विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों में स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच के कारण टीबी की पहचान और उपचार हमेशा से चुनौतीपूर्ण रहा है। कई मरीज पोषणयुक्त भोजन के अभाव में दवाइयां बीच में ही छोड़ देते थे। इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए निरंजन गुप्ता ने न केवल पोषण किट उपलब्ध कराई, बल्कि घर-घर जाकर मरीजों और उनके परिजनों को टीबी के लक्षणों, नियमित दवा सेवन, और संक्रमण से बचाव के प्रति जागरूक भी किया।

टीबी मुक्त भारत के लिए जन-भागीदारी की अपील

विशेषज्ञों का मानना है कि टीबी के सफल उपचार के लिए दवा के साथ-साथ पर्याप्त पोषण बेहद जरूरी है। जशपुर की यह पहल साबित करती है कि यदि समाज का हर सक्षम व्यक्ति संवेदनशीलता के साथ आगे आए, तो देश से टीबी के खात्मे के लक्ष्य को आसानी से हासिल किया जा सकता है। आज जरूरत इस बात की है कि अधिक से अधिक नागरिक और संगठन 'निक्षय मित्र' बनकर इस राष्ट्रीय अभियान से जुड़ें।

60 टीबी रोगियों का जिम्मा

निरंजन प्रसाद गुप्ता ने अक्टूबर 2024 से 'निक्षय मित्र' के रूप में जिम्मेदारी संभालते हुए कुल 60 टीबी मरीजों को गोद लिया है।

विशेष पिछड़ी जनजातियों को संबल

इनमें पहाड़ी कोरवा और बिरहोर जैसे विशेष पिछड़ी जनजातीय समुदायों के 19 विशेष पिछड़ी जनजाति मरीज भी शामिल हैं।

नियमित पोषण आहार

दूरस्थ और आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को नियमित रूप से पोषण आहार एवं आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

राज्य स्तरीय सम्मान

उनके इन उल्लेखनीय और समर्पित प्रयासों के लिए उन्हें दिसंबर 2024 में 'राज्य स्तरीय निक्षय मित्र पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

दुर्ध्यान से सद्ज्ञान की ओर बढ़ने का बनाएं लक्ष्य: मुनिश्री संवेगरत्न सागर

रायपुर/नवप्रदेश। विवेकानंद नगर स्थित ज्ञानवल्लभ उपाश्रय में सर्वमंगलमय वर्षावास की चातुर्मासिक प्रवचनमाला में परम पूज्य मुनिश्री संवेगरत्न सागर जी म.सा. ने धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मनुष्य का ध्यान उसके मन के माध्यम से होता है। यदि मन अशुभ भावों से ग्रसित हो जाए, तो वह दुर्ध्यान और अज्ञान की ओर बढ़ता है, जबकि सद्ज्ञान आत्मा को सुख, शांति और कल्याण के मार्ग पर ले जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का मुख्य लक्ष्य दुर्ध्यान से निकलकर सद्ज्ञान की ओर बढ़ना होना चाहिए। मुनिश्री ने फरमाया कि ज्ञान में भले ही कोई व्यक्ति कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका सम्मान और भक्ति सर्वोपरि होनी चाहिए। ग्रंथों को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए तथा प्रभु के वचनों का अनुसरण करना चाहिए। आत्मा के कल्याण के लिए केवल दृष्टिकोण और लक्ष्य बदलने की आवश्यकता है। जिस समर्पण भाव से मनुष्य शरीर के लिए कार्य करता है, उसी भावना से आत्मा के लिए भी प्रयास करना चाहिए। चातुर्मास समिति के अध्यक्ष जसराज लुणीया व महासचिव सुरेश बरड़िया ने जानकारी दी कि सर्व मंगलमय वर्षावास में तप की निरंतर श्रृंखला जारी है। श्री पंच परमेष्ठी श्रेणी तपः वर्तमान में 49 दिवसीय इस तप का दूसरा चरण चल रहा है।

विशेष तपस्याः इस कड़ी में श्रावक संयम बैद और श्राविका पूजा सुराना ने 9-9 उपवास की तपस्या पूर्ण की।

अज्ञान और दुर्ध्यान के दुष्परिणाम

मुनिश्री ने कहा कि अज्ञान ही मनुष्य को दुर्ध्यान में बांधे रखता है और इससे बचने के लिए प्रायश्चित आवश्यक है। सत्य को जान लेने के बाद भी उसे जीवन में अपनाने से जो शक्ति रोकती है, वही अज्ञान ध्यान है। अविनयपूर्ण आचरण करना और गलत विचारों में उलझे रहना भी अज्ञान ध्यान का ही रूप है, जो मनुष्य को दुख और दुर्गति की ओर ले जाता है। ज्ञान व्यक्ति के दर्शन को निर्मल बनाता है और जीवन में श्रेष्ठ चारित्र्य का निर्माण करता है।

सही चिंतन और मैत्री भाव से जीवन को मिलती है नई दिशा

रायपुर/नवप्रदेश। 'आत्म उत्क्रांति आध्यात्मिक चातुर्मास-2026' के अंतर्गत श्री जिनकुशलसूरि जैन दादाबाड़ी में 'अध्यात्मसार' ग्रंथ के 'चिंतन' अध्याय पर प्रवचन देते हुए पूज्य साध्वी मंजुलाश्रीजी महाराज साहिबा ने कहा कि यदि चिंतन और मनन सही दिशा में किया जाए, तो मनुष्य जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। साध्वीश्री ने कहा कि यदि हमारे मन में यह भाव हो कि हमारी अपेक्षाएं पूरी हों या न हों, लेकिन हमारे द्वारा दूसरों की अपेक्षाएं अवश्य पूरी हों, तो यही सच्चा मैत्री भाव है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने पर जीवन में मैत्री और करुणा का स्वाभाविक उदय होता है। जब किसी कार्य के प्रति दृढ़ भाव जागृत हो जाता है, तब वह कार्य कितना भी कठिन क्यों न हो, सहज रूप से पूर्ण हो जाता है। सफलता का मूल आधार बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि मन के सकारात्मक भाव होते हैं। प्रवचन के दौरान उन्होंने एक संत और नगरवासियों का प्रेरक प्रसंग सुनाया। संत के पूछने पर नगरवासियों ने नगर के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में एक झाड़ू लगाने वाली महिला का नाम बताया, जो सदैव प्रसन्न रहती थी, मधुर व्यवहार करती थी और नियमित समाधि का अभ्यास करती थी। महिला ने संत के पूछने पर सहज भाव से उत्तर दिया, समाधि के लिए कुछ नहीं करना पड़ता।÷ इस प्रसंग की व्याख्या करते हुए साध्वीश्री ने कहा कि जहां मन की चंचलता समाप्त हो जाती है और भीतर पूर्ण शांति का अनुभव होता है, वहीं से समाधि का आरंभ होता है।

कम्युनिटी बेस्ड सर्विलांस: अब आम नागरिक भी IHIP पोर्टल के जरिए दे सकेंगे संदिग्ध बीमारियों की सूचना

रायपुर/नवप्रदेश। किसी गांव, मोहल्ले या बस्ती में यदि अचानक एक जैसी बीमारी के दो या अधिक मामले सामने आने लगें, तो यह किसी संभावित रोग प्रकोप का संकेत हो सकता है। जनभागीदारी को बढ़ावा देने और बीमारियों की समय रहते पहचान सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच के तहत सामुदायिक आधारित रोग निगरानी की सुविधा शुरू की गई है। अब देश का कोई भी नागरिक अपने आसपास फैलने वाली किसी भी असामान्य बीमारी या संभावित रोग प्रकोप की जानकारी सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करा सकता है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी संक्रामक बीमारी के फैलाव को रोकने में समय पर जानकारी मिलना सबसे अहम कड़ी है। प्रारंभिक स्तर पर सूचना मिलने से स्वास्थ्य विभाग तुरंत जांच, सैंपल संग्रह, उपचार और नियंत्रण के आवश्यक उपाय शुरू कर सकता है, जिससे बीमारी को महामारी बनने से रोका जा सकता है।

पोर्टल पर कैसे दर्ज करें सूचना?

सामान्य विवरण: सूचना दर्ज करते समय प्रदाता का नाम, मोबाइल नंबर, आयु, लिंग, पता और व्यवसाय जैसी बुनियादी जानकारी भरनी होती है।

घटना का विवरण: इसके साथ ही घटना की तिथि, स्थान और बीमारी या स्वास्थ्य समस्या का संक्षिप्त विवरण देना जरूरी है।

प्रमाण: यदि कोई फोटो या अन्य दस्तावेज उपलब्ध हैं, तो उन्हें भी साक्ष्य के रूप में अपलोड किया जा सकता है।

सत्यापन: सभी अनिवार्य विवरण भरने के बाद मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी के जरिए सत्यापन होते ही सूचना सीधे संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों तक पहुंच जाती है।

स्वास्थ्य विभाग की अपील

स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे पोर्टल पर केवल सत्य, तथ्यात्मक और जिम्मेदारीपूर्ण जानकारी ही दर्ज करें। अफवाहों, अपुष्ट सूचनाओं या भ्रामक जानकारियों से बचने की सलाह दी गई है ताकि स्वास्थ्य तंत्र वास्तविक और गंभीर मामलों पर त्वरित कार्रवाई कर सके। आपके द्वारा समय पर दी गई एक सटीक सूचना कई लोगों के जीवन की रक्षा कर सकती है।

अनुकंपा नियुक्ति में सीलिंग हटाने और नई स्थानांतरण नीति लागू करने सीएम को सौंपा ज्ञापन

- तृतीय श्रेणी पदों पर लागू 10% की सीलिंग को तुरंत समाप्त करने की मांग
- 2025 की स्थानांतरण नीति से प्रतिबंध हटाने और नई व्यावहारिक नीति लागू करने का आग्रह

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों से जुड़े दो अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लंबे समय से लंबित विषयों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को विस्तृत मांग-पत्र सौंपा है और इस पर त्वरित निर्णय लेने का आग्रह किया है। फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, महासचिव चंद्रशेखर तिवारी, उप संयोजक पवन शर्मा, रोहित तिवारी, संजय सिंह और प्रदेश प्रवक्ता पंकज पांडे ने संयुक्त विज्ञप्ति जारी कर इन मांगों की पूरी जानकारी दी है।

स्थानांतरण प्रतिबंध हटाने और नई नीति लागू करने की मांग

फेडरेशन ने वर्ष 2025 की स्थानांतरण नीति में आवश्यक संशोधन कर प्रतिबंध हटाने और नई स्थानांतरण नीति जल्द जारी करने की जोरदार मांग उठाई है। मांग-पत्र में निम्नलिखित प्रावधानों को अनिवार्य रूप से शामिल करने पर जोर दिया गया है।

पति-पत्नी प्रकरण: पति-पत्नी के मामलों में पारस्परिक स्थानांतरण का स्पष्ट प्रावधान हो।

कर्मचारी संगठन: मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को स्थानांतरण नियमों में पूर्ववत छूट दी जाए।

विशेष स्वास्थ्य प्राथमिकता: दिव्यांग कर्मचारियों के साथ-साथ कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित शासकीय सेवकों को स्थानांतरण में विशेष छूट और प्राथमिकता मिले। फेडरेशन के नेताओं ने कहा कि ये दोनों मुद्दे प्रदेश के हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़े हैं। अनुकंपा नियुक्ति में देरी के कारण शोकाकुल परिवार भयंकर आर्थिक संकट झेल रहे हैं, वहीं स्पष्ट और व्यावहारिक स्थानांतरण नीति के अभाव में कर्मचारी पारिवारिक व मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री से उम्मीद जताई है कि राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए इन दोनों जनहितैषी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी और जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेगी।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बड़ी मांग

वर्तमान में सामान्य प्रशासन विभाग के 23 फरवरी 2019 के आदेश के अनुसार, तृतीय श्रेणी के पदों पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए सीधी भर्ती के पदों पर 10 प्रतिशत की सीमा (सीलिंग) निर्धारित है।

समस्या: इस सीलिंग की वजह से दिवंगत शासकीय सेवकों के उच्च शिक्षित और पात्र आश्रित परिवार वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति के लिए भटक रहे हैं। इसके विपरीत, चतुर्थ श्रेणी के पदों पर ऐसी कोई सीलिंग लागू नहीं है।

फेडरेशन की मांग: मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तृतीय श्रेणी पदों पर भी चतुर्थ श्रेणी की तरह सीलिंग पूरी तरह समाप्त की जाए, जिससे पीड़ित परिवारों को समय पर न्याय और आर्थिक-सामाजिक सुरक्षा मिल सके।

जवानों की कलाई न रहे सूनी: कांकेर की बहनों ने प्रेम, सम्मान और मातृभूमि की मिट्टी के साथ भेजीं राखियां

कांकेर/नवप्रदेश। रक्षा बंधन के पावन पर्व पर उत्तर बस्तर कांकेर जिले की महिलाओं, छात्राओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों ने देश की सीमाओं पर तैनात वीर जवानों के प्रति अपना स्नेह, सम्मान और कृतज्ञता अनूठे अंदाज में व्यक्त किया। नगर के पुराने बस स्टैंड में आयोजित भव्य कार्यक्रम में हजारों रक्षा सूत्र एकत्रित कर सैनिकों के लिए रवाना किए गए। कार्यक्रम का उद्देश्य था कि देश की रक्षा में जुटे किसी भी जवान की कलाई रक्षा बंधन के दिन सूनी न रहे।

कार्यक्रम में स्कूल की छात्राओं,आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, महतारी वंदन योजना से जुड़ी महिलाओं, सफाई कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों तथा जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों की महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बहनों ने राखियों के साथ अपने घर-आंगन की पवित्र मिट्टी तिलक के लिए भेजी, वहीं छात्राओं ने चॉकलेट और शुभकामना संदेश भी शामिल कर सैनिकों के प्रति अपना प्रेम और सम्मान व्यक्त किया। उपस्थित लोगों ने कहा कि यह केवल एक राखी नहीं, बल्कि बस्तर की माताओं और बहनों के स्नेह, विश्वास और राष्ट्रभक्ति का

प्रतीक है।कार्यक्रम के दौरान सेवानिवृत्त सैनिक महेंद्र प्रताप राणा को बहनों ने रक्षा सूत्र सौंपे, जिन्हें देश की सीमाओं पर तैनात जवानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई। आयोजन पूरे उत्साह और देशभक्ति के वातावरण में संपन्न हुआ।यह अभियान प्रदेश अध्यक्ष विभा अवस्थी के मार्गदर्शन में संचालित किया गया। जिला प्रभारी श्रीमती अर्चना चौबे के नेतृत्व में जिलेभर की महिलाओं ने बड़ी संख्या में सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में रुक्मणी हुई, विजयलक्ष्मी कौशिक, जैना ताराम, उमा शर्मा, शालिनी राजपूत, सुमित्रा मरकाम, राजेंद्र रंधावा, मीरा सलाम, सरिता कुलदीप, चित्रलेखा जैन, शकुंतला जैन, निधि संचेती, मंजूस आरती, स्मृति कौशिक, अंजू नेगी, तमन्ना लखवानी, गीतावती, सीता गुप्ता, आरोही, दीप्ति शाह, सुनीता सरकार सहित अनेक महिलाएं उपस्थित रहीं। जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में बहनों ने राखियां भेजकर इस अभियान को सफल बनाया।इस अवसर पर शासकीय विभागों के कर्मचारियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई और जवानों के लिए रक्षा सूत्र भेजे। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष महेश जैन, विधायक आसाराम नेताम, नगर पालिका अध्यक्ष अरुण कौशिक, दिनेश रजक सहित अनेक जनप्रतिनिधि, पूर्व सैनिक और युवाओं ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए अभियान का समर्थन किया। वक्ताओं ने कहा कि रक्षा बंधन केवल भाई-बहन के प्रेम का पर्व नहीं, बल्कि राष्ट्ररक्षा में लगे सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का भी अवसर है। कांकेर से भेजी गई ये राखियां देश के उन वीर सपूतों तक पहुंचेंगी जो परिवार से दूर रहकर राष्ट्र की सुरक्षा में अपना सर्वस्व समर्पित कर रहे हैं।

संक्षिप्त खबरें

भालू के हमले से हुई जनहानि पर परिजनों को 6-6 लाख रूपए की दी जाएगी मुआवजा राशि

कांकेर /नवप्रदेश। उत्तर बस्तर कांकेर 06 अगस्त 2026/ जिले के वन परिक्षेत्र नरहरपुर (दक्षिण) वन परिसर चनार के तहत ग्राम मरकाटोला में एक वन्य प्राणी भालू द्वारा ग्रामीणों पर हमला करने तथा इससे दो लोगों की मृत्यु व एक महिला के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना पर वन विभाग द्वारा त्वरित कार्यवाही की गई। गंभीर रूप से घायल ग्रामीण महिला को बेहतर उपचार के लिए रायपुर हायर सेंटर ले जाया गया तथा उनकी चिकित्सा के लिए तत्कालिक सहायता राशि की व्यवस्था वन विभाग द्वारा की गई। वन मंडलाधिकारी कांकेर रौनक गोयल ने बताया कि 05 अगस्त को नरहरपुर के ग्राम मरकाटोला में मादा भालू द्वारा किए गए हमले में दो ग्रामीण हलालखोर पिता सुंदरलाल (36 वर्ष) तथा चमरिनबाई पिता सुंदरलाल (48 वर्ष) की मृत्यु हो गई। मृतकों के परिजनों को शासन के नियमानुसार वन्य प्राणी द्वारा जनहानि मुआवजा के तहत् 6-6 लाख रूपए की राशि दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस घटना के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर त्वरित कार्यवाही करते हुए घटना स्थल के आसपास पर्याप्त संख्या में वन अमलों की तैनाती की गई तथा ग्रामीणों के सुरक्षा के सभी आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। साथ ही गांव तथा आसपास के अन्य ग्रामों में भी मुनादी कराकर ग्रामीणों को सावधानी व सतर्कता बरतने की समझाइश लगातार दी जा रही है। वन मंडलाधिकारी कांकेर ने यह भी बताया कि उक्त वन्य प्राणी भालू का वन्य प्राणी विशेषज्ञों की टीम द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू किया जाकर जंगल सफारी नवा रायपुर भिजवाने की कार्यवाही की गई। उन्होंने मरकाटोला एवं आसपास के ग्रामवासियों से अपील की है कि कोई भी ग्रामीण घटना स्थल की ओर एवं उससे लगे वन क्षेत्र की ओर न जाएं तथा अपने आसपास के लोगों एवं परिचितों को भी सूचित कर पर्याप्त सावधानी बरतें। किसी प्रकार से आक्रोशित होकर वन्य प्राणी को चोट पहुंचाने अथवा छेड़ने का प्रयास न करें। साथ ही वन्य प्राणी का फोटो अथवा वीडियो भी न बनाएं।

हर घर तिरंगा' कार्यक्रम: 09 से 17 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी विविध गतिविधियां

कांकेर / नवप्रदेश । उत्तर बस्तर कांकेर 06 अगस्त 2026/ भारत सरकार संस्कृति मंत्रालय नई दिल्ली तथा छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग मंत्रालय अटल नगर नवा रायपुर के निर्देशानुसार वंदे मातरम थीम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आगामी 09 से 17 अगस्त तक 'हर घर तिरंगा' कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर पर किया जाएगा। इसके तहत् नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज अपने घर पर फहराने एवं राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गायन के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे आमजन में देश भक्ति और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना जागृत हो। इस संबंध में बताया गया कि आगामी 09 से 17 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैलियां, तिरंगा दौड़ व मैराथन, तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा कैनवास, तिरंगा प्रतिज्ञा, तिरंगा सेल्फी, तिरंगा सम्मान, तिरंगा मेला, हर घर तिरंगा, वंदे मातरम पर विशेष प्रदर्शनी तथा विशाल तिरंगा रंगोली का प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा 07 से 15 अगस्त के बीच वंदे मातरम थीम पर आधारित कार्यक्रम का विशेष आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत जनप्रतिनिधियों, स्थानीय अधिकारियों व प्रमुख हस्तियों और नागरिकों की उपस्थिति में व्यापक जन भागीदारी के साथ जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालयों, ग्राम पंचायतों तथा सभी स्कूल-कॉलेजों में ध्वजारोहण के उपरांत राष्ट्रगीत, वंदे मातरम का सामूहिक गान कराया जाएगा। इन गतिविधियों के आयोजन से संबंधित फोटोग्राफ्स एवं वीडियो ई-मेल आईडी harghartirangaacgstate@gmail.com में अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

ग्राम पंचायत सचिव के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु पात्र-अपात्र आवेदकों की सूची जारी

कांकेर/ नवप्रदेश ।उत्तर बस्तर कांकेर 06 अगस्त 2026/ जिला पंचायत कांकेर द्वारा जिले के ग्राम पंचायतों में सचिव के 27 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया था। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने जानकारी दी है कि प्राप्त आवेदन पत्रों में से पात्र-अपात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन किया गया है। जिसका अवलोकन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कांकेर के सूचना पटल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत कांकेर, चारामा, नरहरपुर, भानुप्रतापपुर, दुर्गूकोंदल, अंतागढ़ एवं कोयलीबेड़ा के सूचना पटल पर तथा कांकेर जिले के वेबसाइट www.kanker.gov.in में अवलोकन किया जा सकता है। पात्र-अपात्र सूची के संबंध में यदि किसी आवेदक को आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वे लिखित में आवेदन आवश्यक दस्तावेज सहित 20 अगस्त सायं 05 बजे तक मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कार्यालय कांकेर में दावा-आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।

पखांजूर को गौरव पथ की सौगात की तैयारी, सड़क निर्माण प्रक्रिया तेज

पखांजूर। नव प्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने भानुप्रतापपुरक्कपखांजूरक्कबांदे मार्ग (राज्य मार्ग क्रमांक-25) के उन्नयन की दिशा में प्रक्रिया तेज कर दी है। इसके तहत नया बाजार से पुराना बाजार तक प्रस्तावित गौरव पथ के निर्माण की प्रशासनिक तैयारियां आगे बढ़ाई जा रही हैं। परियोजना को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक औपचारिकताओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। गौरव पथ निर्माण के लिए नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित नेताजी सुभाषचंद्र बोस एवं डॉ भीमराव अंबेडकर की प्रतिमाओं को सम्मानपूर्वक अन्य उपयुक्त स्थान पर स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने नगर पंचायत से प्रतिमाओं के स्थानांतरण की अनुमानित लागत और प्राक्कलन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, ताकि इसे मुख्य परियोजना में शामिल कर निर्माण कार्य बिना बाधा के पूरा किया जा सके।नगर पंचायत के सहयोग और विभागीय समन्वय से परियोजना को गति देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अधिवक्ताओं और बीमा कंपनियों के पदाधिकारियों की हुई बैठक

राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर बैठक में बनी रणनीति

जगदलपुर / नवप्रदेश। 12 सितंबर 2026 को आयोजित होने वाली वर्ष की द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में अधिवक्ताओं और बीमा कंपनियों के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अधिक से अधिक प्रकरणों के आपसी समझौते के माध्यम से निराकरण कराने तथा पक्षकारों को लोक अदालत के लिए प्रेरित करने पर जोर दिया गया।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण,नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,बिलासपुर के निर्देशानुसार आयोजित बैठक में राष्ट्रीय लोक अदालत की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी न्यायालयों में लंबित आपराधिक,व्यवहार वाद,मोटर दुर्घटना दावा,चेक बाउंस,बीमा तथा धारा 138 एनआई एक्ट से संबंधित मामलों का अधिकाधिक निराकरण कराने के लिए प्री-सिटिंग आयोजित करने और आपसी राजीनामे को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया। अधिवक्ताओं एवं बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों से पक्षकारों को लोक अदालत की उपयोगिता बताकर स्वैच्छिक समझौते के लिए प्रेरित करने तथा अधिक से अधिक मामलों का निराकरण सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया।

जगदलपुर में आयोजित बैठक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में हुई। व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंकिता कश्यप ने सभी संबंधित पक्षों से राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग की अपील की।

इन मामलों का होगा निराकरण

राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक,व्यवहार वाद, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस,बीमा तथा धारा 138 एनआई एक्ट सहित समझौता योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति से त्वरित एवं सरल निराकरण किया जाएगा। इसके लिए पक्षकारों को पहले से संपर्क कर राजीनामे के लिए प्रेरित किया जाएगा।

शासकीय आईटीआई बस्तर में उद्योग विशेषज्ञों ने दिए सफल करियर के गुर

जगदलपुर / नवप्रदेश। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) बस्तर में आयोजित तीन दिवसीय अभिमुखीकरण कार्यक्रम 'नव कौशल पथ नयी राह,नया हुनर' के दूसरे दिन नव-प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को उद्योग जगत की जरूरतों और रोजगार के अवसरों से अवगत कराया गया। कार्यक्रम में उद्योग प्रतिनिधियों, पूर्व विद्यार्थियों और संस्थान के शिक्षकों ने कौशल विकास के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विद्यार्थियों को उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रेरित किया।मुख्य सत्र में जिंदल स्टील रायपुर के उद्योग प्रतिनिधि सूर्योदय दुबे और सुभाष साव ने आधुनिक उद्योगों की कार्यप्रणाली, कार्य-संस्कृति तथा तकनीकी क्षेत्र में निरंतर सीखते रहने की आवश्यकता पर विस्तार से जानकारी दी। संस्थान के पूर्व छात्र एवं एल्युमिनी सदस्य जीएस ठाकुर ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि आईटीआई से प्राप्त व्यावहारिक प्रशिक्षण और अनुशासन ने उन्हें करियर में आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राचार्य डॉ एके मांडले ने

नव-प्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए कहा कि कौशल ही आधुनिक भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और तकनीकी शिक्षा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मजबूत माध्यम है।

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने बढ़ाया उत्साह

मार्गदर्शन सत्र के बाद विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बस्तर की पारंपरिक लोक प्रस्तुतियों ने सभी का मन मोह लिया और नए विद्यार्थियों में आत्मविश्वास व उत्साह का संचार किया।

उद्योग,शिक्षा और संस्कृति का मिला संगम

कार्यक्रम के सफल आयोजन में आईटीआई बस्तर के अधिकारियों,शिक्षकों,कर्मचारियों तथा वरिष्ठ प्रशिक्षणार्थियों की सक्रिय भूमिका रही।

दिव्यांग भृत्य की भावुक विदाई बच्चों को कराया स्नेहभोज

■ 10 वर्षों की सेवा के बाद स्थानांतरण,एक हाथ से दिव्यांग होने के बावजूद निभाई जिम्मेदारी

जगदलपुर/नव प्रदेश। शासकीय उच्च प्राथमिक शाला भूरसुंडी में गुरुवार को एक भावुक विदाई समारोह आयोजित किया गया। विद्यालय में लगभग 10 वर्षों तक सेवाएं देने वाले एक हाथ से दिव्यांग भृत्य पीलू राम नाग के स्थानांतरण पर विद्यालय परिवार और विद्यार्थियों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। अपने मूल पदस्थापना स्थल माध्यमिक शाला फरसापारा स्थानांतरित होने से पहले उन्होंने बच्चों के प्रति स्नेह व्यक्त करते हुए निजी खर्च से सभी विद्यार्थियों के लिए न्योता भोज का आयोजन कराया।

विदाई समारोह में पीलू राम

नाग ने कहा कि भूरसुंडी विद्यालय उनके लिए केवल कार्यस्थल नहीं, बल्कि परिवार जैसा रहा है। यहां के बच्चों का स्नेह, शिक्षकों का सहयोग और ग्रामीणों का अपनापन जीवनभर याद रहेगा। उन्होंने कहा कि जहां भी रहेंगे, विद्यालय और बच्चों की मधुर स्मृतियां हमेशा उनके साथ रहेंगी।

स्नेहभोज में विद्यार्थियों को राहर की दाल, छोले, आलू की सब्जी तथा मिष्ठान के रूप में जलेबी परोसी गई। बच्चों ने उत्साहपूर्वक भोजन किया और अपने प्रिय भृत्य को शुभकामनाओं के साथ विदाई दी।

सेवा और स्नेह की मिसाल

एक हाथ से दिव्यांग होने के बावजूद पीलू राम नाग ने पूरे समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभाईं। स्थानांतरण से पहले निजी खर्च पर बच्चों के लिए स्नेहभोज का आयोजन उनकी संवेदनशीलता और विद्यालय परिवार के प्रति आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक बन गया। उनकी विदाई ने सभी को भावुक कर दिया और यह आयोजन सेवा,समर्पण तथा मानवीय रिश्तों की प्रेरक मिसाल बन गया।

सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर बसपा ने खोला मोर्चा

■ आरक्षित एवं मूलनिवासी समाज के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप,

कांकेर/नवप्रदेश। सोशल मीडिया पर आरक्षित वर्ग एवं मूलनिवासी समाज के प्रति कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने के मामले में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) कांकेर ने पुलिस प्रशासन से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। पार्टी के जिला अध्यक्ष तिलक मरकाम के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक, कांकेर को एक लिखित आवेदन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता , 2023 की लागू धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई।बसपा द्वारा सौंपे गए

आवेदन में उल्लेख किया गया है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर "Adarsh Mishra" नामक प्रोफाइल से एक सार्वजनिक पोस्ट साझा की गई, जिसमें आरक्षण व्यवस्था तथा आरक्षण का लाभ लेने वाले समुदायों के संबंध में कथित रूप से अपमानजनक एवं आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं। पार्टी का आरोप है कि इस प्रकार की सामग्री अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वंचित समुदायों की भावनाओं को आहत करने के साथ-साथ समाज में जातीय वैमनस्य और सामाजिक तनाव उत्पन्न कर सकती है।बसपा पदाधिकारियों ने पुलिस प्रशासन से मांग की कि मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट की तकनीकी एवं कानूनी जांच कर दोषी पाए जाने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर घृणा, जातीय अपमान और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री के विरुद्ध समय पर कार्रवाई होना आवश्यक है, ताकि समाज में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनी रहे।

अटल आरोग्य लैब का दायरा बढ़ा

अब ग्रामीण अस्पतालों में भी मिलेगी आधुनिक जांच सुविधा

जगदलपुर/ नव प्रदेश। राज्य शासन ने शासकीय अस्पतालों में मरीजों को त्वरित, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण पैथोलॉजी जांच उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। जिला अस्पतालों में सफल संचालन के बाद अब 'अटल आरोग्य लैब' का विस्तार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सिविल अस्पतालों तक किया जा रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को आवश्यक जांच के लिए जिला मुख्यालय का रुख नहीं करना पड़ेगा।

राज्य में लैब सेवाओं के प्रभावी संचालन के लिए केस सूचना डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड को सहयोगी संस्था बनाया गया है। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं ने महेंद्र पांडे को जिला नोडल अधिकारी (लैब) की जिम्मेदारी सौंपी है।

बस्तर सीएचसी में जल्द स्थापित होंगे आधुनिक उपकरण

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बस्तर में लैब स्थापना के लिए स्थान का चयन पूरा हो चुका है और जल्द ही आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। वर्तमान में यहां से रक्त के नमूने जांच के लिए जिला अस्पताल भेजे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार एचएलएल के माध्यम से उपकरणों की स्थापना और संचालन की नियमित निगरानी की जा रही है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों का लगातार निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मरीजों को अपने नजदीकी अस्पताल में ही समय पर बेहतर जांच और उपचार की सुविधा मिल सके।

हाल ही में अधिकारियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकावंड और बस्तर का निरीक्षण किया। बकावंड में लैब तैयार कर सीबीसी, यूरिन एनालाइजर और फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर स्थापित किए जा चुके हैं तथा गुणवत्ता परीक्षण के बाद सीबीसी जांच भी शुरू कर दी गई है। जटिल जांचों के नमूने फिलहाल जिला अस्पताल भेजे जा रहे हैं।

मावा मोदोल और पूना पर्रियान का कमाल एसआई भर्ती प्रीलिम्स में 12 अभ्यर्थी सफल

कांकेर/नवप्रदेश।जिला प्रशासन उत्तर बस्तर कांकेर की महत्वाकांक्षी पहल ÷मावा मोदोल (मेरा भविष्य) निःशुल्क कोचिंग सेंटर÷ एवं ÷पूना पर्रियान (नई उड़ान)÷ ने एक बार फिर अपनी गुणवत्ता और प्रभावशीलता साबित कर दी है। छत्तीसगढ़ सब-इंस्पेक्टर भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के घोषित परिणामों में इन दोनों निःशुल्क कोचिंग संस्थानों से तैयारी करने वाले 12 अभ्यर्थियों ने सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। इस उपलब्धि से जिले में खुशी की लहर है, वहीं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं में नया उत्साह और आत्मविश्वास पैदा हुआ है। जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर तथा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरेश मंडावी के मार्गदर्शन में संचालित इन निःशुल्क कोचिंग केंद्रों से लगातार बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रशासन का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर एवं ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रतियोगी परीक्षा मार्गदर्शन उपलब्ध कराकर उन्हें सरकारी सेवाओं में अवसर दिलाना है। मावा मोदोल निःशुल्क कोचिंग सेंटर, कांकेर से गुलशन कुमार जैन, मोनिका नेताम, अंजली उसेंडी, संदीप गढ़पाले, भुनेश्वर साहू एवं कुलेश्वर पटेल ने प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त की। वहीं मावा मोदोल निःशुल्क कोचिंग सेंटर, भानुप्रतापपुर से पुष्पलता जाड़े, विक्रांत ठाकुर, यजेश नेताम, कविता गोयल, नागेश्वर कुमेटी एवं पुष्पलता बसेरा ने सफलता हासिल कर जिले का गौरव बढ़ाया। इस उपलब्धि पर कलेक्टर निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर एवं जिला पंचायत सीईओ हरेश मंडावी ने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

कोर्ट के आदेश के बाद भी अमरकंटक का रंगमहल मंदिर पूजा-अर्चना से वंचित

अमरकंटक/अनूपपुर/नवप्रदेश। मां नर्मदा की पावन नगरी अमरकंटक स्थित प्राचीन कलचुरीकालीन रंगमहल मंदिर एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। मंदिर में विराजमान पातालेश्वर महादेव, भगवान विष्णु, सत्यनारायण एवं अन्य देवस्थानों में नियमित पूजा-अर्चना शुरू न होने को लेकर धार्मिक संगठनों और श्रद्धालुओं में असंतोष व्याप्त है। भगवा पार्टी ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए मांग की है कि न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित कराया जाए तथा श्रद्धालुओं को निर्बाध दर्शन और पूजा का अधिकार मिले। भगवा पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल मिश्र ने कहा कि रंगमहल मंदिर निजी धार्मिक संपत्ति है तथा यहां पूजा-अर्चना का अधिकार न्यायालय द्वारा भी मान्य किया जा चुका है। इसके बावजूद मंदिर का बड़ा हिस्सा आज भी प्रभावी रूप से आम श्रद्धालुओं के लिए सुलभ नहीं हो पाया है। उन्होंने मांग की कि मंदिर को पुरातत्व विभाग के नियंत्रण से मुक्त कर धार्मिक परंपराओं के अनुरूप पूजा-अर्चना की व्यवस्था बहाल की जाए।गौरतलब है कि मां नर्मदा मंदिर के सामने स्थित यह प्राचीन रंगमहल मंदिर लंबे समय तक पूजा-अर्चना से वंचित रहा। इस विषय को लेकर ब्रह्मलीन जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने रंगमहल मंदिर में पूजा-अर्चना के अधिकार को लेकर न्यायालय में कानूनी लड़ाई लड़ी थी। इस प्रकरण में उनकी ओर से अधिवक्ता मुरलीधर शर्मा एवं श्रीधर शर्मा ने प्रभावी पैरवी की थी। न्यायालय में दोनों अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार

पर द्वारका शारदा पीठ के पक्ष में निर्णय आया, जिसमें मंदिर की देखरेख एवं विधि-विधान से पूजा-अर्चना का अधिकार पीठ को प्रदान किया गया। इसके बावजूद स्थानीय श्रद्धालुओं का आरोप है कि न्यायालय के आदेश का पूर्ण रूप से पालन अब तक नहीं हो पाया है, जिससे धार्मिक आस्था से जुड़े लोगों में निराशा और असंतोष बना हुआ है। कानूनी लड़ाई लड़ी थी। उनके पक्ष में आए निर्णय के बाद मंदिर में विधि-विधान से पूजा प्रारंभ होने की उम्मीद जगी थी। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि निर्णय की भावना के अनुरूप व्यवस्था आज तक पूरी तरह लागू नहीं हो सकी है।

धार्मिक संगठनों में नाराजगी

अमरकंटक स्थित प्राचीन कलचुरीकालीन रंगमहल मंदिर में नियमित पूजा-अर्चना शुरू न होने को लेकर धार्मिक संगठनों और श्रद्धालुओं ने नाराजगी जताई है। भगवा पार्टी के जिला अध्यक्ष कन्हैयालाल मिश्र ने कहा कि न्यायालय द्वारा मंदिर में पूजा-अर्चना का अधिकार मान्य किए जाने के बावजूद आदेश का पूर्ण पालन नहीं हो रहा है। उनका कहना है कि पातालेश्वर महादेव, भगवान विष्णु, सत्यनारायण, हनुमान सहित अन्य देवस्थानों में नियमित पूजा व्यवस्था बहाल की जाए तथा श्रद्धालुओं को निर्बाध दर्शन का अधिकार मिले।

न्यूज गैलरी

संत रविदास की पवित्र कलश यात्रा का स्वागत, बालाजी मंदिर में हुई स्थापना

जशपुर/नवप्रदेश। संत शिरोमणि रविदास महाराज की पवित्र कलश यात्रा का जशपुर शहर आगमन पर श्रद्धालुओं और जनप्रतिनिधियों द्वारा अपार उत्साह तथा भक्ति भाव से ससम्मान स्वागत किया गया। इस दौरान पूरे शहर में माहौल भक्तिमय बना रहा। अतिथियों एवं शहरवासियों ने पूर्ण श्रद्धा के साथ कलश यात्रा की अगवानी की और वेद-मंत्रों के उच्चारण के बीच विधिवत पूजन-अर्चन संपन्न किया। पूजन के पश्चात पवित्र कलश को पूरे आदर और सत्कार के साथ स्थानीय बालाजी मंदिर में स्थापित किया गया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय विधायक रायमुनी भगत ने संत रविदास के विचारों, शिक्षाओं और सामाजिक समरसता के संदेश को अपने जीवन में आत्मसात करने पर जोर दिया। कार्यक्रम में पूर्व हस्तशिल्प बोर्ड अध्यक्ष कृष्ण कुमार राय, विधायक रायमुनी भगत, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, नरेश नंदे, शहर मंडल अध्यक्ष मुकेश सोनी, रागनी भगत, दीपू मिश्रा, रजनी प्रधान, देवधन नायक, दीपक चौहान, अभिषेक गुप्ता, नागेंद्र भगत, सुधीर भगत, रविंद्र पाठक, गणेश साहु , शरद चौरसिया, शशि बाई, मालती भगत, अनीता पैकरा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता व श्रद्धालु उपस्थित रहे ।

काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए गए सब इंजीनियर के घर से 20 लाख की चोरी

अंबिकापुर/नवप्रदेश। शहर के कोणार्क रेजीडेंसी में अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए करीब 20 लाख रुपये के जेवरात एवं अन्य सामान चोरी कर लिया। जानकारी के अनुसार मकान मालिक, जो लोक निर्माण विभाग में सब इंजीनियर हैं, अपनी पत्नी के साथ बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए वाराणसी गए हुए थे। इसी दौरान शनिवार और रविवार की दरमियानी रात चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। दंपति के लौटने पर घर का मुख्य गेट टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो अलमारी का लॉक टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात और अन्य कीमती सामान गायब मिले। पीड़ित दंपति ने अज्ञात चोरों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए आरोपियों की तलाश की जा रही है।

महेंद्र कर्मा की जयंती मनाई गई

लखनपुर/नवप्रदेश। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यालय लखनपुर में गुरुवार को छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं शहीद स्वर्गीय महेंद्र कर्मा की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उनके छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि महेंद्र कर्मा ने समाज, आदिवासी समुदाय और प्रदेश के विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। उनका साहस, संघर्ष, जनसेवा और बलिदान आज भी सभी के लिए प्रेरणास्रोत है। कांग्रेसजनों ने उनके आदर्शों पर चलकर जनता की सेवा के लिए निरंतर कार्य करने का संकल्प भी लिया। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अमित सिंह देव, वीरेन्द्र सिंह देव, रमेश जायसवाल, शराफत अली, जगरोपन यादव, असफाक खान, देवनारायण सिंह, मोजिब खान सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी, वरिष्ठ कांग्रेसजन और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

6 जुआरियों से 1.12 लाख जब्त वीडियोग्रॉफी भी कराई गई

रामनगर/नवप्रदेश। पुलिस ने अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेल रहे 6 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके से ताश के पत्तों, नगदी और दो मोटरसाइकिलों सहित कुल 1,12,200 रुपए का मशरूका जब्त किया है। थाना प्रभारी सुमित कौशिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आमाडांड क्षेत्र में छापेमारी की। आरोपी वहां ताश के 52 पत्तों से हार-जीत का दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे। पुलिस ने मौके से 2,200 रुपए नगद, एक हीरो स्प्लेंडर प्लस और एक बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल बरामद की। गिरफ्तार आरोपियों में अजय कुमार चौधरी, राजाराम चौधरी, श्रवण कुमार गुप्ता, राजकुमार चौधरी, सुरेन्द्र चौधरी और एक अन्य मोटरसाइकिल चालक शामिल हैं। पुलिस ने नियमानुसार जब्ती और वीडियोग्राफी की कार्रवाई पूरी करते हुए आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 228/26 के तहत धारा 13 सार्वजनिक जुआ अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर लिया है। सभी आरोपियों को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए पाबंद किया गया है। अनूपपुर पुलिस ने आमजन से अपील की है कि जुआ, सट्टा या अन्य अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

गौठान की 11 एकड़ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायत

तहसीलदार के बेदखली आदेश के बाद भी नहीं हटा बेजाकब्जा

बम्हनीडीह/नवप्रदेश। नगर पंचायत बम्हनीडीह स्थित गौठान की शासकीय भूमि पर कथित बेजाकब्जे का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है । पूर्व सरपंच प्रतिनिधि राजकुमार पटेल द्वारा कलेक्टर जनदर्शन, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एवं राजस्व विभाग में लगातार शिकायतें किए जाने के बाद भी अब तक कब्जा नहीं हटाया गया है।

शिकायत के अनुसार ग्राम गौठान की खसरा नंबर 1265 की कुल 11 एकड़ भूमि पर दो लोगों द्वारा कथित रूप से अवैध कब्जा किया गया है। इस मामले में तहसीलदार बम्हनीडीह ने 20 जून 2023 को बेदखली आदेश क्रमांक 849 जारी किया था, लेकिन आदेश के तीन वर्ष बाद भी उसका पालन नहीं हो सका। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कब्जाधारियों ने पक्का मकान बनाकर लगभग 150 फीट तक शेड का निर्माण कर लिया है,

जिससे सरकारी भूमि पर अतिक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। गौठान जैसी सार्वजनिक उपयोग की शासकीय भूमि पर लंबे समय से कथित कब्जा बने रहने और बेदखली आदेश के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से राजस्व प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं । अब जबकि कलेक्टर कार्यालय ने पुनः संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं, स्थानीय लोगों की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासन वास्तव में अतिक्रमण हटाकर शासकीय भूमि को मुक्त करा पाता है या नहीं । पूरे मामले में आगामी प्रशासनिक कार्रवाई पर क्षेत्रवासियों की निगाहें बनी हुई हैं ।

एसडीएम नहीं हटा पाए अतिक्रमण

लगातार प्राप्त शिकायतों के बाद कलेक्टर कार्यालय, जांजगीर-चांपा की शिकायत शाखा ने 8 जुलाई 2026 को एक आधिकारिक ज्ञापन जारी कर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चांपा को प्रकरण भेजा । ज्ञापन में ग्राम गौठान बम्हनीडीह से तत्काल अतिक्रमण हटाकर आवेदक के आवेदन का निराकरण करने तथा की गई कार्रवाई से कलेक्टर कार्यालय को अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं । शिकायतकर्ता का कहना है कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 में भी इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी और कई बार राजस्व विभाग को पत्राचार किया गया, लेकिन अब तक जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया।

एयर टैंक फटने से घायल युवक की अस्पताल में मौत

अनूपपुर/नवप्रदेश। जिले के कोतमा स्थित श्रमिक नगर बस स्टैंड के पास एक ऑटो वर्कशॉप में हादसा हो गया। काम के दौरान अचानक एयर टैंक फटने से युवक प्रिंस साहू गंभीर रूप से घायल हो गए। धमाका इतना तेज था कि उनके सिर में गंभीर चोट आई। हादसे के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उपचार शुरू किया। हालांकि गंभीर चोटों के कारण इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।जानकारी के अनुसार, प्रिंस साहू का विवाह कुछ समय पहले ही हुआ था। उनकी असमय मौत की खबर से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, वहीं पूरे कोतमा क्षेत्र में शोक का माहौल है।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में एयर टैंक फटने की वजह सामने आई है। हालांकि हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है।

इस हादसे ने एक बार फिर ऑटो वर्कशॉप और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों एवं उपकरणों के नियमित रखरखाव को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों ने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक सख्त किए जाने की मांग की है।

850 तीर्थयात्री अयोध्या धाम दर्शन के लिए विशेष ट्रेन से रवाना

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा संचालित श्री रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत 5 अगस्त को सरगुजा संभाग के 850 तीर्थयात्रियों को लेकर विशेष ट्रेन अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई।

विशेष ट्रेन को महापौर, अंबिकापुर मंजूषा भगत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योजना के जिला स्तरीय नोडल अधिकारी एवं उप संचालक, समाज कल्याण विभाग व्ही.के. उके ने बताया कि जिला सरगुजा से कुल 170 तीर्थयात्री अयोध्या

धाम दर्शन के लिए रवाना हुए हैं। इनमें जनपद पंचायत से 18, उदयपुर से 18, लखनपुर से 18, लुण्ड्रा से 18, बतौली से 18, सीतापुर से 18 तथा मैनपाट से 18 तीर्थयात्री शामिल हैं। इसके अलावा नगर निगम अंबिकापुर से 30, नगर पंचायत लखनपुर से 7 तथा नगर पंचायत सीतापुर से 7 तीर्थयात्री यात्रा में शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या धाम दर्शन के लिए रवाना हुई विशेष ट्रेन 08 अगस्त को वापस लौटेगी। विशेष ट्रेन के प्रस्थान के अवसर पर जिला पंचायत सरगुजा की अध्यक्ष निरूपा सिंह, नगर निगम के सभापति हरमिंदर सिंह टिन्नी, जनप्रतिनिधिगण एवं पार्षदगण उपस्थित रहे।

टीकाकरण अभियान: छात्राओं को किया गया जागरूक

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिले के विभिन्न विद्यालयों में छात्राओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस संक्रमण, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर से बचाव में एचपीवी वैक्सीन की प्रभावशीलता, टीकाकरण के लाभ एवं आवश्यक सावधानियों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। दशमेश पब्लिक स्कूल में 60, कार्मेल स्कूल में 125 तथा होली क्रॉस स्कूल में 310 छात्राओं ने जागरूकता कार्यक्रम में

सहभागिता की। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छात्राओं को बताया कि एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम का एक सुरक्षित एवं प्रभावी उपाय है।

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं की एचपीवी संक्रमण एवं टीकाकरण से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान किया गया तथा उन्हें अपने अभिभावकों को भी एचपीवी टीकाकरण के महत्व के संबंध में जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने जिले की सभी पात्र छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से अपील की है कि वे राष्ट्रीय एचपीवी टीकाकरण अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें तथा स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करें।

खेत में काम करने गए व्यक्ति की संदिग्ध मौत

लखनपुर/नवप्रदेश। थाना लखनपुर क्षेत्र के ग्राम टपरकेला में खेत पर काम करने गए एक ग्रामीण की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार ग्राम केवरा गांधी चौक नावापारा निवासी महेश्वर सिंह टपरकेला स्थित अपने खेत में काम करने गए थे। इसी दौरान सुरेश नामक ग्रामीण ने विष्णु सिंह को फोन कर सूचना दी कि महेश्वर सिंह खेत में मुंह के बल गिरा पड़ा है। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लखनपुर ले गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर लखनपुर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पीएम कराया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक तौर पर मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।

डाटा एनालिसिस टूलकिट की कार्यप्रणाली पर प्रशिक्षण

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा संचालित आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत जिला पंचायत सभाकक्ष में नीति तारा डाटा एनालिसिस टूलकिट की कार्यप्रणाली एवं उपयोग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को डाटा आधारित योजना निर्माण, विकास संकेतकों की नियमित निगरानी तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तकनीकी रूप

से दक्ष बनाना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम कलेक्टर अजीत वसंत एवं जिला पंचायत सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी विनय अग्रवाल के मार्गदर्शन में आयोजित हुआ। इसमें मास्टर ट्रेनर विजय सोलंकी ने प्रतिभागियों को नीति तारा प्लेटफॉर्म की कार्यप्रणाली, डाटा विश्लेषण, पोर्टल के प्रभावी उपयोग तथा विकास योजनाओं की मॉनिटरिंग के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की प्रगति का वैज्ञानिक एवं तथ्यात्मक विश्लेषण कर समयबद्ध एवं प्रभावी निर्णय लिए जा सकते हैं। कार्यक्रम में जिला पंचायत के एपीओ मिथलेश पैंकरा, जपं लखनपुर की मुख्य कार्यपालन अधिकारी खुशबू शास्त्री, आकांक्षी विकासखंड फेलो सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, स्वच्छ भारत मिशन तथा प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न विभागों के जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण

विकसित भारत जी-राम जी योजना: 6 जिले के पंचायत प्रतिनिधि शामिल हुए

पंचायतों को सशक्त, जवाबदेही बनाने पर प्रशिक्षण कार्यशाला

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन (ग्रामीण) ग्रामीण योजना-2025' के प्रभावी क्रियान्वयन तथा ग्राम पंचायतों को सशक्त, जवाबदेह एवं विकासोन्मुख बनाने के उद्देश्य से सरगुजा संभाग मुख्यालय अम्बिकापुर स्थित जिला पंचायत सभाकक्ष में तीन दिवसीय संभाग स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में सरगुजा संभाग के सभी छह जिलों के जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों ने सहभागिता करते हुए ग्राम विकास, सुशासन एवं पंचायतों की भूमिका से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत प्रशिक्षण प्राप्त किया।यह कार्यशाला पंचायत प्रतिनिधियों की प्रशासनिक दक्षता, नेतृत्व क्षमता तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हुई।

प्रशिक्षण के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को ग्राम पंचायतों के समग्र एवं सहभागी विकास की नई कार्यप्रणाली से परिचित कराया गया। कार्यशाला का आयोजन जिलेवार चरणबद्ध तरीके से किया गया। प्रथम दिवस 03 अगस्त 2026 को एमसीबी एवं

जशपुर जिले के जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को प्रशिक्षण दिया गया। द्वितीय दिवस 04 अगस्त 2026 को सूरजपुर एवं कोरिया जिले के जनप्रतिनिधियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया, जबकि अंतिम दिवस 05 अगस्त 2026 को बलरामपुर एवं सरगुजा जिले के जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य प्रशिक्षण में शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान विषय विशेषज्ञों द्वारा ग्रामीण योजना-2025 के विभिन्न आयामों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण (पीपीटी) के माध्यम से जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को योजना के उद्देश्य, कार्यान्वयन प्रक्रिया तथा पंचायतों की भूमिका के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। साथ ही विकसित भारत ग्राम पंचायत प्लान के निर्माण, ग्राम स्तर पर समग्र विकास की योजना तैयार करने की प्रक्रिया तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन की जानकारी साझा की गई। कार्यशाला में ग्रामीण आजीविका संवर्धन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संरक्षण, स्थानीय संसाधनों के समुचित उपयोग तथा सतत विकास के उपायों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। विभिन्न विभागों की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से अधिकतम लाभ ग्रामीणों तक पहुँचाने की रणनीतियों को समझाया गया।

स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग बताए

तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिलेवार चरणबद्ध तरीके से किया गया। पहले दिन एमसीबी और जशपुर, दूसरे दिन सूरजपुर एवं कोरिया तथा अंतिम दिन बलरामपुर और सरगुजा जिले के जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। कार्यशाला में ग्रामीण आजीविका संवर्धन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जल संरक्षण, स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग, विभागीय योजनाओं के अभिसरण और सतत विकास के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई।

सूख चुके बोरवेल और हैंडपंपों में फिर से पानी आने लगा

मुंगेली/नवप्रदेश। जनपद पंचायत मुंगेली के ग्राम पंचायत पौनी में वाटर लेबल नीचे चले जाने से हैन्ड पम्प एवं बोर सूख गये थे। अव्यवस्थित रूप से पड़े सूखी खदानों में पानी भारे जाने से सूख चुके बोरवेल और हैंडपंपों में फिर से पानी आने लगा है।

किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने से खेतों में दोबारा हरियाली लौट रही है, वहीं पशुपालकों को भी राहत मिली है। समय पर की गई पहल से जल संकट काफी हद तक दूर हो गया है। क्षेत्र की समस्याओ को निराकरण करने की इच्छा शक्ति हो तो बंजर धरती में हरियाली वापस लाई जा सकती है। ग्राम पंचायत पौनी में वाटर लेबल नीचे चले जाने से बोरवेल एवं हैडपम्प सूख चुके थे। ग्राम में आस-पास जल स्त्रोत न होने के चलते पेय जल से लेकर कृषि कार्य में ग्रामीणो को परेशानी होने लगी थी। ग्रामीणो की समस्या को देख कर सरपंच भारत रत्न मंडेला के प्रयासों पर जल संसाधन विभाग ने दुल्लीपार हाफ डायवर्सन मानपुर शाखा नहर से गांव की सूखी खदान, तालाबों और जलाशयों में पानी छोड़ा। करीब 15 दिनों तक लगातार पानी पहुंचने से वर्षों से सूखी पड़ी खदान पूरी तरह भर गई। इसका सकारात्मक असर आसपास के भू-जल स्तर पर भी देखने को मिला। कई सूख चुके बोरवेल और हैंडपंपों में फिर से पानी आने लगा है। किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलने से खेतों में दोबारा हरियाली लौट रही है, वहीं पशुपालकों को भी राहत मिली है। ग्रामीणों ने बताया कि समय पर यह पहल नहीं होती तो गांव को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ता। सरपंच की पहल और जल संसाधन विभाग की तत्परता से गांव में जल संरक्षण को नई दिशा मिली है। पौनी की यह पहल ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन और जनप्रतिनिधि-प्रशासन के बेहतर समन्वय का प्रेरक उदाहरण बनकर सामने आई है।

न्यूज गैलरी

खाद की कालाबाजारी पर कृषि मंत्री का सख्त रुख, अफसर बख्शे नहीं जाएंगे

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। खाद की कालाबाजारी और अनियमित वितरण को लेकर छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने अंबिकापुर में अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों को समय पर और निर्धारित दर पर खाद उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। खाद की कालाबाजारी में किसी अधिकारी या कर्मचारी की मिलीभगत सामने आने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को खाद माफिया पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री ने जिला कृषि विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए उप संचालक कृषि को निर्देशित किया कि खाद की कालाबाजारी में शामिल लोगों और उनसे सांठगांठ रखने वाले अधिकारी-कर्मचारियों की पहचान की जाए। उन्होंने कहा कि जांच में गड़बड़ी और मिलीभगत की पुष्टि होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय है। मंत्री ने अंबिकापुर के फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए जांच के बाद दोषी पाए जाने पर कार्रवाई के संकेत दिए। मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष खाद वितरण में अनियमितताओं की शिकायतों के बाद संबंधित फर्टिलाइजर इंस्पेक्टर को हटाया गया था। इसके बावजूद यदि वही अधिकारी दोबारा उसी जिम्मेदारी पर तैनात किया गया है और उसकी भूमिका संदिग्ध पाई जाती है, तो मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

कॉमनवेल्थ गेम्स में ज्ञानेश्वरी ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ और देश का मान

मुंगेली/नवप्रदेश।-ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल-2026 में महिलाओं की 53 किलोग्राम भारोत्तोलन स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव को भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राकेश साहू ने बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वरी ने 199 किलोग्राम वजन उठाकर देश और छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाया है। यह उपलब्धि प्रदेश के खेल इतिहास में स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज होगी। उन्होंने बताया कि दृढ़ इच्छाशक्ति, कठोर परिश्रम और अनुशासन के बल पर कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। मुख्यमंत्री साय ने ज्ञानेश्वरी को उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए 30 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि तथा आउट ऑफ टर्न डीएसपी पद पर पदोन्नति देने की घोषणा की है। राकेश साहू ने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश की भाजपा सरकार मातृशक्ति को आगे बढ़ने का पूरा अवसर दे रही है, जिससे महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ज्ञानेश्वरी की सफलता प्रदेश के युवाओं, विशेषकर बेटियों के लिए प्रेरणास्त्रोत है।

दुष्कर्म का फरार आरोपी पटना से गिरफ्तार

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। सरगुजा जिले में 14 वर्षीय आदिवासी नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहे आरोपी तरुण कुमार जायसवाल को बिहार की राजधानी पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी एक महिला मित्र के साथ छिपा हुआ था। मोबाइल सर्विलांस के जरिए उसकी लोकेशन मिलने पर बिहार पुलिस ने बुधवार देर रात छापेमारी कर दोनों को पकड़ लिया। अब सरगुजा पुलिस आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर अंबिकापुर लाने की तैयारी कर रही है। मामला 20 जुलाई का है, जब आरोपी पर नाबालिग से दुष्कर्म और धमकी देने का आरोप लगा था। घटना सामने आने के बाद आरोपी फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी पर एसएसपी राजेश अग्रवाल ने 5 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। हाल ही में गिरफ्तारी में देरी को लेकर विभिन्न संगठनों ने प्रदर्शन भी किया था। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।

मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान

अम्बिकापुर/नवप्रदेश। माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए निवेशित परिषद (इंवेस्टिचर सेरेमनी) एवं शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन से हुआ, जिसके बाद नवगठित छात्र परिषद के पदाधिकारियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। समारोह में महापौर मंजूषा भगत, रेड क्रॉस सोसायटी अंबिकापुर के अध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंह देव, 10वीं बटालियन की असिस्टेंट कमांडर कविता ठाकुर, विद्यालय प्रबंधन, शिक्षक एवं अभिभावक उपस्थित रहे। आदित्येश्वर शरण सिंह देव ने विद्यार्थियों से अनुशासन, ईमानदारी और सेवा-भाव के साथ नेतृत्व निभाने का आह्वान किया।

सामान सहित चोर गिरफ्तार

रायगढ़/नवप्रदेश। भूपदेवपुर पुलिस ने घर में चोरी के मामले का त्वरित खुलासा करते हुए आरोपी सनत कुमार उर्फ नानू साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी के कब्जे से चोरी गए चांदी के एक जोड़ी पायल, बिछिया तथा पोको कंपनी का मोबाइल सहित करीब 30 हजार का पूरा सामान बरामद कर लिया। पुलिस के अनुसार ग्राम डोंगाढकेल निवासी घनश्याम साहू ने 4 अगस्त को घर से जेवर और मोबाइल चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी रोशन कुमार कौशिक के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर गांव लौटते ही आरोपी को पकड़ लिया।

जिले में औद्योगिक निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा

हैवी अर्थ मूविंग संयंत्र के लिए 79.70 एकड़ भूमि की मंजूरी

मुंगेली/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास के मानचित्र पर जिले ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) के प्रस्तावित हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए ग्राम चंद्रगढ़ी, तहसील पथरिया में 79.70 एकड़ शासकीय भूमि रियायती दर पर आबंटित करने के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के साथ मुंगेली में बड़े औद्योगिक निवेश और आधुनिक विनिर्माण गतिविधियों के विस्तार का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

यह संयंत्र राज्य का पहला उद्योग होगा, जिसकी स्थापना से छत्तीसगढ़ को देश के औद्योगिक मानचित्र पर नई पहचान मिलेगी और राज्य में आधुनिक भारी मशीन निर्माण उद्योग की शुरुआत होगी। जिले में इस प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रम की परियोजना शुरू होने से रोजगार, कौशल विकास, तकनीकी प्रशिक्षण, उद्यमिता और सहायक उद्योगों के लिए नए अवसर सृजित होंगे। कलेक्टर कुन्दन कुमार ने इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर जिलेवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बीईएमएल संयंत्र जिले में औद्योगिक विकास का आधार बनेगा। कैबिनेट के द्वारा मिली मंजूरी जिले में औद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि तैयार करने में ऐतिहासिक कदम है। इससे आधुनिक विनिर्माण का आधार मजबूत होगा तथा स्थानीय युवाओं, उद्यमियों और व्यवसायियों के लिए विकास के नए रास्ते खुलेंगे। यह पहल जिले को आधुनिक विनिर्माण और इंजीनियरिंग गतिविधियों के नए केंद्र के रूप में नई पहचान दिलाएगी। विशेष प्रयासों से

परियोजना को मुंगेली तक लाने में मिली सफलता - पथरिया एसडीएम रेखा चंद्रा ने बताया कि बीईएमएल की प्रस्तावित परियोजना के लिए प्रारंभिक स्तर पर रायगढ़ एवं जांजगीर-चांपा जिलों में भूमि चिन्हांकन की प्रक्रिया चल रही थी।

इसी दौरान कंपनी ने जिले में भी उपयुक्त भूमि की उपलब्धता में रुचि व्यक्त की। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र तथा राजस्व विभाग ने त्वरित कार्यवाही करते हुए उपयुक्त शासकीय भूमि की खोज और चिन्हांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की। संयुक्त टीम द्वारा विस्तृत सर्वेक्षण के बाद 79 एकड़ से अधिक भूमि की उपलब्धता का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। भूमि की उपयोगिता का परीक्षण करने के बाद आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित की गई।

कलेक्टर ने की त्वरित पहल

पथरिया एसडीएम रेखा चंद्रा ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर बीईएमएल परियोजना के लिए अन्य जिलों में भूमि चिन्हांकन किया जा रहा था, लेकिन कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देश पर जिला प्रशासन ने त्वरित कार्यवाई करते हुए चंद्रगढ़ी में उपयुक्त शासकीय भूमि चिन्हित की। सर्वेक्षण, विभागीय अनुमतियों और पहुंच मार्ग की व्यवस्था के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा गया, जिसे अब कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्रों के उन्नयन के लिए राशि मंजूर

***15.85 करोड़ की विकास परियोजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति**

रायगढ़/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी के प्रयासों से जिले के खनिज प्रभावित क्षेत्रों के समग्र विकास को प्राथमिकता देते हुए जनहित के कार्यों को लगातार स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से 15 करोड़ 85 लाख 60 हजार रुपये की लागत के विभिन्न विकास कार्यों को प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इन परियोजनाओं से जिले के स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अधोसंरचना को नई मजबूती मिलेगी तथा हजारों ग्रामीणों को बेहतर सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा। स्वीकृत कार्यों के अंतर्गत खरसिया विकासखंड के सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं उप स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण और उन्नयन के लिए 88 लाख 81 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। वहीं धरमजयगढ़ विखं के सिविल अस्पताल के निर्माण एवं उन्नयन कार्यों के लिए 5 करोड़ 28 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त धरमजयगढ़, लैलूंगा, तमनार एवं घरघोड़ा विकासखंडों में मॉडल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सेंटर भवनों के निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए 9 करोड़ 56 लाख 18 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इन परियोजनाओं से विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं और बेहतर अधोसंरचना उपलब्ध होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा भी विस्तृत होगा। शिक्षा अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में लैलूंगा विकासखंड के ग्राम पंचायत कुर्रा में अतिरिक्त कक्ष सहित प्राथमिक शाला भवन के जीर्णोद्धार के लिए 3 लाख 48 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसी प्रकार ग्राम पंचायत चोरंगा के माध्यमिक शाला भवन के जीर्णोद्धार कार्य के लिए 9 लाख 13 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।

युवाओं ने 8 विधाओं में दिखाया हुनर, विजेता जाएंगे राज्यस्तर पर

रायगढ़/नवप्रदेश। शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ के मार्गदर्शन में उत्तम मेमोरियल कॉलेज पटेलपाली रायगढ़ के तत्वावधान में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य पीएम मोदी के आह्वान पर इन दिनों देश भर में नशा मुक्त युवा फॉर विकसित ।

भारत संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है इसी कड़ी में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की स्वायत संस्था माय भारत रायगढ़ द्वारा जिला युवा अधिकारी वसुंधरा साहू के निर्देशन और कार्यक्रम समन्वयक डॉ. रविंद्र चौबे के मार्गदर्शन में 4 अगस्त मंगलवार को उत्तम मेमोरियल कॉलेज पटेलपाली रायगढ़ के व्यवस्था में जिला स्तरीय प्रतियोगिता संपन्न कराया गया। इस कार्यक्रम मे कुल आठ विधा गीत, नृत्य, चित्रकला, कविता, नारालेखन, लघु फिल्म निर्माण, नुक्कड़ नाटक और भाषण की प्रतियोगितायें आयोजित हुई जिनमें जिले भर से आये 15 से 29 वर्षीय सैकड़ों युवाओं ने भाग लिया। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित कलाविद मनोज श्रीवास्तव, विशिष्ट अतिथि भोजराम पटेल , बच्छ भोय रहे, कार्यक्रम की अध्यक्षता उत्तम मेमोरियल कालेज के प्राचार्य डॉ. गोमती सिंह ने की। आठ विधाओं की इस स्पर्धा में भाषण में ऐश्वर्या राणा, कविता में नवीन कुमार दुबे, चित्रकला मे उषा पटेल, लघु फिल्म/रिल्स निर्माण में हर्ष मालाकार, नारा लेखन में पलक ठाकुर, नृत्य में कृतिका एवं समूह, गीत में महेंद्र एवं समूह एवं नाटक में विजय एवं समूह ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।

चोरी के मामले में दंपती सहित चार आरोपी बंदी

रायगढ़/नवप्रदेश। रायगढ़ पुलिस ने संपत्ति संबंधी अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए थाना चक्रधरनगर क्षेत्र में महज 48 घंटे के भीतर दो अलग-अलग चोरी की घटनाओं का खुलासा कर एक महिला सहित चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन तथा एडिशनल एसपी अनिल सोनी एवं एसडीओपी खरसिया सतीश भार्गव के मार्गदर्शन में की गई कार्रवाई में पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से करीब दो लाख रुपए मूल्य की नकदी, जेवर, साइकिल, दो

मोटरसाइकिल और चोरी में प्रयुक्त सामान बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों में थाना क्षेत्र का निगरानी बदमाश शिव सारथी उर्फ शिवा सारथी भी शामिल है। पुलिस के अनुसार पहली घटना सूर्या बिहार, कौहाकुंडा में प्रोफेसर सरोज कुमार चंद्रा के मकान के पोर्च से बच्चे की रेंजर साइकिल चोरी की थी। वहीं दूसरी घटना दीनदयालपुरम कॉलोनी फेस-1 में हुई, जहां सूने मकान का ताला तोड़कर अलमारी से 70 हजार रुपये नकद, सोने का टॉप्स और पीतल का लोटा चोरी कर लिया गया। गृहस्वामिनी सेवती पटेल पारिवारिक कारणों से बरमकेला गई थीं और लौटने पर चोरी का पता चला। थाना प्रभारी निरीक्षक राकेश मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थलों का निरीक्षण कर आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर संदिग्ध शिवा सारथी और उसकी पत्नी पिंकी सारथी की पहचान की गई।

एनालॉग प्रतिबंध की जानकारी दी

रायगढ़/नवप्रदेश। खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विशेष जांच अभियान लगातार चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में मंगलवार को विभागीय टीम ने शहर की डेयरी दुकानों, मिठाई प्रतिष्ठानों, होटल, रेस्टोरेंट और बेकरी का सघन निरीक्षण कर खाद्य कारोबारियों को आवश्यक निर्देश दिए। अभियान के दौरान पनीर एनालॉग और डेयरी एनालॉग उत्पादों के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी आदेशों की जानकारी भी दी गई। नियंत्रक के आदेश के परिपालन में 4 अगस्त को अभिहित अधिकारी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा टीम ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को राज्य शासन द्वारा डेयरी एनालॉग के निर्माण एवं विक्रय पर लगाए गए प्रतिबंध से अवगत कराया गया। साथ ही दुकानदारों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे किसी भी प्रकार का पनीर एनालॉग बिक्री के लिए न रखें तथा केवल मानक अनुरूप खाद्य सामग्री का ही विक्रय करें।

एनालॉग पनीर: डेयरी विक्रेताओं की दुकानों की जांच

मुंगेली/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना के अनुपालन में जिले में एनालॉग पनीर के निर्माण, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण एवं विक्रय पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जिले के डेयरी प्रतिष्ठानों, रेस्टोरेंट, होटल एवं खाद्य दुकानों का निरीक्षण कर संचालकों को प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। खाद्य एवं औषधि प्रशासन

विभाग के उपसंचालक ने बताया कि राज्य शासन के निर्देशानुसार ऐसे सभी गैर-मानकीकृत डेयरी एनालॉग उत्पाद, जो वास्तविक दूध से बने उत्पादों का आभास कराते हैं, अब प्रतिबंधित रहेंगे। इस संबंध में जिलेभर में निरीक्षण अभियान प्रारंभ कर दिया गया है तथा नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

एनालॉग पनीर एक तरह का नकली या सिंथेटिक पनीर है, जो असली दूध के बजाय वेजिटेबल ऑयल (जैसे पाम ऑयल), स्टार्च, स्किम्ड मिल्क पाउडर और रसायनों से बनाया जाता है। यह दिखने और खाने में असली पनीर जैसा लगता है, लेकिन बहुत सस्ता होता है और सेहत के लिए हानिकारक माना जाता है। उक्त प्रतिबंध विशेष रूप से ऐसे उत्पादों पर लागू होगा, जो वास्तविक दूध से निर्मित नहीं हैं, जिनमें दूध के स्थान पर वनस्पति वसा, वनस्पति तेल अथवा अन्य गैर-दुग्ध अवयवों का उपयोग किया गया है। साथ ही जिनकी लेबलिंग, पैकेजिंग अथवा बिक्री की प्रस्तुति उपभोक्ताओं को भ्रमित करती है। उन्होंने बताया कि जिले में संचालित डेयरी प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। सभी संचालकों को एनालॉग पनीर का निर्माण, भंडारण, वितरण एवं विक्रय तत्काल बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

पेज 1 का शेष...

डीपफेक पर सरकार का...

लोकसभा में दी।

आईटी नियमों में मध्यस्थों की जिम्मेदारी बढ़ी

आईटी नियम, 2021 के तहत मध्यस्थों को उचित सावधानी बरतना अनिवार्य है। उन्हें उपयोगकर्ताओं को ऐसी सामग्री होस्ट, अपलोड, प्रकाशित या साझा करने से रोकना होता है जो किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन करती हो, अश्लील या निजता का उल्लंघन करने वाली हो, बच्चों के लिए नुकसानदेह हो, घृणा या हिंसा को बढ़ावा देती हो या गलत सूचना फैलाती हो। एआई के जरिए किसी अन्य व्यक्ति का रूप धारण करने वाली सामग्री और राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा पैदा करने वाली सामग्री भी इसके दायरे में आती है।

बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त दायित्व

50 लाख या उससे अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ताओं वाले महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थों (एसएसएमआई) पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां लागू हैं। उन्हें गैरकानूनी सामग्री के प्रसार का पता लगाने और उसे सीमित करने के लिए स्वचालित उपकरणों का इस्तेमाल करना होता है। साथ ही, अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करने, स्थानीय अधिकारियों की नियुक्ति करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए भारत में भौतिक पता उपलब्ध कराने जैसी व्यवस्थाएं भी अनिवार्य हैं।

एआई कंटेंट पर स्पष्ट लेबल और मेटाडेटा

10 फरवरी 2026 को आईटी नियमों में संशोधन के बाद एआई से उत्पन्न सामग्री को लेकर नियामक व्यवस्था और सख्त की गई। मध्यस्थों को एआई-जनित सामग्री पर स्पष्ट लेबलिंग और पता लगाने योग्य मेटाडेटा उपलब्ध कराना होगा, ताकि उपयोगकर्ता ऐसी सामग्री की पहचान कर सकें। इसका उद्देश्य धोखाधड़ी और एआई तकनीक के दुरुपयोग को रोकना है।

वेनेजुएला समेत अमेरिका का...

उनके कार्यकाल के दौरान, अमेरिकी और वेनेजुएला के अधिकारियों ने एक नए द्विपक्षीय एजेंडे पर बातचीत शुरू की है, जिसमें ड्रग तस्करी से निपटने में सहयोग, वेनेजुएला के फंड्ड की रिहाई, दक्षिण अमेरिकी देश के तेल की बिक्री, माइनिंग एक्सप्लोरेशन और राजनयिक बातचीत को फिर से शुरू करना शामिल है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 9 जनवरी को शेवरॉन, एक्सॉन, शेल और कोनोकोफिलिप्स जैसी बड़ी तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। बैठक के दौरान, उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में कम से कम 100 अरब डॉलर का निवेश करने की आवश्यकता होगी।

23,731 करोड़ की 'गोबरधन'...

स्तंभ के रूप में स्थापित करेगी। सरकार का लक्ष्य इस योजना के माध्यम से देश में सीबीजी उत्पादन को करीब 10 गुना बढ़ाना, निजी निवेश आकर्षित करना और सर्कुलर बायोइकोनॉमी को मजबूत करना है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा संचालित इस योजना के तहत सीबीजी उत्पादकों को सुनिश्चित बाजार, स्थिर मूल्य, पूंजी सहायता, पाइपलाइन कनेक्टिविटी, ऋण सहायता और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे परियोजनाओं की आर्थिक व्यवहार्यता और निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा।

योजना के छह प्रमुख घटक

सुनिश्चित सीबीजी खरीद

सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां सीबीजी की खरीद करेंगी। इसके तहत 2026-27 में 3 प्रतिशत, 2027-28 में 4 प्रतिशत और 2028-29 से 5 प्रतिशत सीबीजी मिश्रण (ब्लेंडिंग) का लक्ष्य तय किया गया है।

स्थिर मूल्य व्यवस्था

सरकार ने सीबीजी के लिए 2,110 रुपये प्रति एमएमबीटीयू का प्रशासित मूल्य तय किया है, जिससे उत्पादकों को दीर्घकालिक राजस्व की स्थिरता मिलेगी।

पूंजी सहायता

नई (ग्रीनफील्ड) सीबीजी परियोजनाओं को प्रति टन प्रतिदिन क्षमता पर अधिकतम 2 करोड़ रुपये की पूंजी सहायता दी जाएगी। उत्पादन क्षमता बढ़ाने वाली ब्राउनफील्ड परियोजनाएं भी इसके दायरे में आएंगी।

सीमांकन मामलों में लापरवाही...

मामलों पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि सक्षम अधिकारियों के आदेश के बावजूद समय पर सीमांकन न होना नागरिकों के लिए परेशानी का सबब है। उन्होंने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सीमांकन संबंधी प्रत्येक प्रकरण का निर्धारित समय-सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से निराकरण किया जाए।

अतीक के बेटे की सड़क...

बेकाबू होने से पहले अबान के आखिरी शब्द मुझे बचा लो थे।

परिवार का आपराधिक और त्रासद इतिहास

अतीक अहमद के पांच बेटों में अबान सबसे छोटा था। इससे पहले 2023 में उसका भाई असद भी झांसी में ही पुलिस एनकाउंटर में मारा गया था। वहीं, अप्रैल 2023 में उमेश पाल हत्याकांड के दौरान प्रयागराज में पुलिस कस्टडी में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफकी भी हत्या हो चुकी है।

मानगढ़ धाम विवादः केंद्र के इनकार पर गरमाई सियासत और इतिहास का सच

नई दिल्ली/ए.। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में स्थित ऐतिहासिक मानगढ़ धाम एक बार फिर बड़े राजनीतिक और सामाजिक विवाद के केंद्र में आ गया है। केंद्र सरकार द्वारा इस स्थल को 'राष्ट्रीय महत्व का स्मारक' घोषित करने से इनकार किए जाने के बाद आदिवासी समाज और विपक्षी दलों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है।

'आदिवासियों के बलिदान का अपमान' - विपक्षी दलों का हमला

केंद्र सरकार के इस रुख के बाद विपक्षी दलों और आदिवासी संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत आदिवासी पार्टी के संस्थापक और बांसवाड़ा के सांसद राजकुमार रोत ने केंद्र के बयान को 1,500 आदिवासियों के ऐतिहासिक बलिदान का अपमान बताया है। उनका कहना है कि सरकार के इस फैसले से आदिवासी समाज की भावनाएं आहत हुई हैं और यह साबित होता है कि आदिवासियों का इतिहास भाजपा के लिए कोई महत्व नहीं रखता। बीएपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन लाल रोत ने भी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि राजनीतिक फायदे के लिए रैलियों में तो इन स्थलों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब सम्मान देने की बारी आती है तो सौतेला व्यवहार किया जाता है। वहीं, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि इस फैसले से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'आदिवासी विरोधी चेहरा' बेनकाब हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आदिवासियों को सिर्फ वोट बैंक मानती है और उनकी पहचान का सम्मान नहीं करती।

केंद्र सरकार का तर्क और संसद में बयान

यह पूरा विवाद हाल ही में संसद में उठे एक सवाल के बाद शुरू हुआ। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP) के प्रमुख हनुमान बेनीवाल के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्पष्ट किया कि मानगढ़ धाम राष्ट्रीय महत्व का स्मारक बनने के लिए निर्धारित पात्रता और मानदंडों को पूरा नहीं करता है। मंत्री ने अपने जवाब में कहा कि स्थल का निरीक्षण करने पर पाया गया कि वहां काफी निर्माण कार्य हो चुका है, जिसके कारण राष्ट्रीय स्मारक के लिए जरूरी पुरातात्विक विशेषताएं, प्रमाणिकता और अखंडता अब सुरक्षित नहीं बची है। इससे पहले मार्च में भी भाजपा सांसद मन्ना लाल रावत के सवाल पर सरकार ने ऐसा ही रुख अपनाया था।

मानगढ़ धाम का ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व

बांसवाड़ा जिले में गुजरात सीमा के पास स्थित मानगढ़ धाम का इतिहास बहुत दर्दनाक और गौरवशाली है। आदिवासियों का जलियांवाला बागः 17 नवंबर 1913 को समाज सुधारक गोविंद गुरु के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफएकत्रित हुए लगभग 1,500 भील आदिवासियों पर ब्रिटिश सेना ने अंधाधुंध गोलीबारी की थी, जिसमें वे शहीद हो गए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से छह साल पहले हुई इस घटना को 'आदिवासियों का जलियांवाला बाग' कहा जाता है।

देशभर में 'बोलती पब्लिक' अभियान चलाएगी सीजेपी

नई दिल्ली/ए.। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने जंतर-मंतर आंदोलन और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को युवाओं की बड़ी जीत बताते हुए पार्टी के आगामी एजेंडे का ऐलान किया। दिपके ने गुरुवार को कहा कि पिछले कई वर्षों से सरकार यह संदेश देती रही कि सत्ता में बैठे लोगों से कोई सवाल नहीं पूछ सकता। लेकिन युवाओं के आंदोलन ने इस धारणा को बदल दिया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फएक व्यक्ति का इस्तीफा नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक आंदोलन की सफलता और जनता के भीतर से डर खत्म होने का प्रतीक है।

उन्होंने कहा कि 25 जुलाई का आंदोलन देश के युवाओं की ऐतिहासिक जीत थी। इस आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि लोगों में सरकार से सवाल पूछने का साहस पैदा हुआ। कॉकरोच जनता पार्टी की विचारधारा पर बोलते हुए दिपके ने कहा कि उनकी पार्टी भारतीय संविधान के मूल्यों पर चलने वाली पार्टी है।

अब 'बोलती पब्लिक' नाम से राष्ट्रीय अभियान

दिपके ने बताया कि पार्टी की दो दिवसीय कोर कमेटी की बैठक में सितंबर से देशभर में 'बोलती पब्लिक' नाम से राष्ट्रीय अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के तहत पार्टी देशभर में जाकर लोगों से उनकी समस्याएं और अपेक्षाएं जानेगी। उनका कहना है कि आज राजनीतिक दल और सरकारें आम जनता, खासकर युवाओं से कट चुकी हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का पहला और सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा सुधार होगा। उनका आरोप है कि देश में शिक्षा लगातार महंगी होती जा रही है। निजी स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों की बढ़ती फीस ने आम परिवारों पर भारी आर्थिक बोझ डाल दिया है। उन्होंने कहा कि शिक्षा को व्यवसाय नहीं, बल्कि हर नागरिक का मौलिक अधिकार माना जाना चाहिए।

10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे प्रदर्शनकारी छात्र

■ परीक्षाओं में गड़बड़ी पर प्रदर्शन तेज, बातचीत के लिए सरकार ने बनाई टीम

रांची/नवप्रदेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने गुरुवार को कहा कि वे सरकार के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों ने बातचीत के लिए शर्त भी रखी है। छात्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी बातचीत बंद कमरे में नहीं बल्कि मीडिया की मौजूदगी में होनी चाहिए। छात्रों ने कहा है कि उनकी मांगें यदि पूरी नहीं हुईं तो वे 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। बता दें कि छात्र जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली एवं अनियमितताओं को लेकर धरना दे रहे हैं। इस बीच, प्रदर्शनकारी छात्रों से बातचीत के लिए हेमंत सरकार ने एक टीम गठित की है।

10 अगस्त को विधानसभा का करेंगे घेराव

समाचार एजेंसी एएनआई के साथ बातचीत में कुमार ने कहा, 'छात्र 10 अगस्त को विधानसभा का घेराव करेंगे। कल एसडीओ सहित सरकार के कुछ अधिकारी हम लोगों से मिलने आए और हमने अपनी मांगें उन्हें बता दीं। हमारी मांगें यदि पूरी नहीं हुईं तो 10 अगस्त को घेराव करने के लिए हजारों की संख्या में छात्र विधानसभा की तरफ कूच करेंगे।' कुमार ने कहा कि प्रदर्शनकारी छात्र टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से संपन्न जेपीएससी, जेएसएससी सीजीएल एवं अन्य भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

महतो से सोनम वांगचुक ने की फोन पर बात : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने का मुद्दा एक राष्ट्रीय समस्या है और उन्होंने इस गतिरोध को सुलझाने के लिए बातचीत का प्रस्ताव दिया है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में भूख हड़ताल कर रहे देवेंद्र नाथ महतो से बुधवार को बातचीत की और उनसे पानी पीने की अपील की। वांगचुक की अपील मानते हुए महतो ने अपने अनशन के चौथे दिन पानी पिया।

गुरुवार से शुरू हो रहा विधानसभा का मानसून सत्र

झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार से शुरू हो रहा है। समझा जाता है कि इस सत्र में परीक्षाओं में कथित धांधली का मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा। वहीं, छात्रों ने विधानसभा के घेराव की बात कहते हुए हेमंत सरकार पर अपना दबाव बढ़ा दिया है। प्रदर्शनकारी राधे कुमार ने कहा कि सरकार की ओर से आंदोलनकारी छात्रों के साथ संपर्क करने की पहल के बाद विधानसभा का घेराव करने का फैसला किया गया।

विधायक नौशाद सिद्दीकी ने पुलिस को दी चुनौती

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मस्जिदों के लाउडस्पीकर को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। आईएसएफ (इंडियन सेक्युलर फ्रंट) के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने आरोप लगाया है कि पुलिस बिना किसी लिखित आदेश या आधिकारिक अधिसूचना के मस्जिद कमेटियों पर माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर हटाने का दबाव बना रही है। उन्होंने कहा कि यदि किसी मस्जिद में ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन हो रहा है, तो प्रशासन को मौजूदा कानून के तहत कार्रवाई करनी चाहिए, न कि मौखिक निर्देशों के आधार पर। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने अदालत जाने और पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को ईमेल भेजने की बात भी कही।

आईएसएफ के विधायक नौशाद सिद्दीकी ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, 'मुझे स्थानीय लोगों के कई फोन आ रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस ने मस्जिद कमेटियों को बुलाकर माइक्रोफोन और लाउडस्पीकर हटाने के लिए कहा है। जब कमेटियों ने पुलिस से इस मांग का आधार जानने के लिए कोई लिखित आदेश या अधिसूचना (नोटिफिकेशन) मांगी, तो पुलिस ऐसा कोई दस्तावेज नहीं दिखा सकी। पुलिस ने केवल इतना कहा कि 'हमने कह दिया है, इसलिए यह करना ही होगा।' हालांकि, हमारा स्पष्ट रुख है कि यदि इन्हें हटाना है तो प्रशासन लिखित आदेश जारी करे या फिर पुलिस खुद आकर इन्हें हटाए। मैंने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के साथ किसी भी तरह का टकराव न करें, क्योंकि बंगाल में बीजेपी इस समय दबाव में है। नौशाद सिद्दीकी ने कहा, 'ध्वनि प्रदूषण के मुद्दे पर पहले भी कलकत्ता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने क्षेत्रों को औद्योगिक (इंडस्ट्रियल), आवासीय (रेजिडेंशियल), व्यावसायिक (कमर्शियल) और साइलेंस ज़ोन में विभाजित किया है।

एएम/एनएस इंडिया स्टील ने भारतीय नौसेना के नए पोत आईएनएस मालवन को दी ताकत

हज़ीरा निर्मित स्टील भारत के बढ़ते रक्षा निर्माण इकोसिस्टम को दे रहा है बढ़ावा

नई दिल्ली/मुंबई। 2026: आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया (एएम/एनएस इंडिया) ने भारतीय नौसेना के नवीनतम स्वदेशी रूप से निर्मित पनडुब्बी रोधी युद्धक शैलो वॉटरक्राफ्ट 'आईएनएस मालवन' के निर्माण के लिए आवश्यक 100त्न विशेष स्टील की आपूर्ति की है। इस पोत को 22 जुलाई 2026 को कारवार, कर्नाटक में नौसेना में शामिल किया गया। हज़ीरा, गुजरात में स्थित एएम/एनएस इंडिया की एकीकृत इस्पात निर्माण सुविधा में निर्मित, इस पोत में इस्तेमाल किया गया विशेष स्टील देश के बढ़ते रक्षा निर्माण इकोसिस्टम और समुद्री सुरक्षा का समर्थन करने में उन्नत भारतीय इस्पात निर्माण की भूमिका को उजागर करता है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण सामग्रियों की आपूर्ति करके भारत की आत्मनिर्भरता की यात्रा में एएम/एनएस इंडिया के योगदान को और मजबूत करता है। एएम/एनएस इंडिया के निदेशक और उपाध्यक्ष - बिक्री एवं विपणन, श्री रंजन धर ने कहा, आईएनएस मालवन का नौसेना में शामिल होना यह दर्शाता है कि भारत में उन्नत विनिर्माण किस तरह देश की रक्षा तैयारियों का समर्थन कर रहा है। विशेष नौसेना-ग्रेड स्टील के उत्पादन के लिए सख्त गुणवत्ता मानकों, उन्नत धातुकर्म विशेषज्ञता और हमारे ग्राहकों के साथ घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता होती है। हमें गर्व है कि एएम/एनएस इंडिया का स्टील भारतीय नौसेना के अगली पीढ़ी के जहाजों में योगदान दे रहा है, साथ ही घरेलू रक्षा विनिर्माण को मजबूत करने की भारत की महत्वाकांक्षा का समर्थन कर रहा है। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित, आईएनएस मालवन आठ माहे-क्लास एएसडब्ल्यू-एसडब्ल्यूसी में से दूसरा है और भारतीय नौसेना के बेड़े में सेवा में प्रवेश करने वाला अपनी श्रेणी का दूसरा पोत है। 80त्न से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ निर्मित, यह कार्यक्रम भारत सरकार की 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत' पहलों का समर्थन करता है, साथ ही नौसेना डिजाइन, इंजीनियरिंग, सिस्टम एकीकरण और रक्षा पोत निर्माण में देश की बढ़ती क्षमताओं को प्रदर्शित करता है। पानी के नीचे निगरानी, पनडुब्बी रोधी युद्ध, माइन वॉरफेयर और तटीय सुरक्षा अभियानों के लिए डिज़ाइन किया गया, आईएनएस मालवन भारत के समुद्री हितों की रक्षा करने और तटीय जल में प्रभावी ढंग से काम करने की भारतीय नौसेना की क्षमता को मजबूत करेगा।

आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत; अंतरिम जमानत नहीं मिली

नई दिल्ली/ए.। सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को फिलहाल अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने उन्हें अपनी पसंद का एक प्रशिक्षित केयरटेकर (देखभाल करने वाला) रखने की अनुमति दे दी, जो 24 घंटे उनकी चिकित्सकीय जरूरतों का ध्यान रख सकेगा। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति पी.बी. वराले की पीठ ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत मांगने वाली आसाराम की याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे फिलहाल लंबित रखा। अदालत ने कहा कि यदि भविष्य में उनकी तबीयत और बिगड़ती है तो वे दोबारा अदालत का रुख कर सकते हैं।

सरकार ने पैरोल का मुद्दा उठाया

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि आसाराम ने यह तथ्य छिपाया है कि उनके वकील ने पहले पैरोल के लिए भी आवेदन किया था। इस पर आसाराम के वकील ने कहा कि पैरोल की अर्जी पहले दायर की गई थी और वह स्वास्थ्य कारणों के आधार पर नहीं थी।

AIIMS ने अस्पताल में भर्ती की जरूरत नहीं बताई

सुप्रीम कोर्ट को पहले बताया गया था कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) के विशेषज्ञों की मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार आसाराम को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, उन्हें चौबीसों घंटे चिकित्सकीय सहायता और देखभाल की जरूरत है।

प्रारूप 01
समाचार पत्र में प्रकाशित की जानी वाली सूचना

मैं दीपेश्वरी कर्ष Dipeshwari karsh (पुराना नाम जिसे बदला जाना है।) सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी / पिता अमीर कर्ष ग्राम पचोरी तहसील सारागांव जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) में अपना नाम दीपेश्वरी कर्ष पुराना से बदलकर दीपिका कर्ष Deepika karsh रख लिया है।

हस्ताक्षर
(पुराने नाम से)

नाबालिग पुत्री / पुत्र के नाम परिवर्तन के मामले में (अभिभावक / पालक द्वारा प्रमाणित)

मैं अमीर कर्ष पिता बुधराम कर्ष ग्राम पचोरी तहसील सारागांव जिला जांजगीर-चांपा (छ.ग.) राज्य में अपने नाबालिग सुपुत्र / सुपुत्री का नाम दीपेश्वरी कर्ष Dipeshwari karsh पुराना नाम से बदलकर दीपिका कर्ष Deepika karsh नया नाम रख लिया है।

माता/पिता / पालक के हस्ताक्षर

न्यायालय तहसीलदार लखनपुर जिला सरगुजा छ.ग.
= ईश्तहार

लखनपुर दिनांक 29.07.2026

एतद् द्वारा आम जनता ग्राम लखनपुर को सूचित किया जाता है कि आवेदक निर्मल कुमार आ.स्व. नंदलाल निवासी ग्राम जुड़वानी के पिता स्व.नंदलाल की मृत्यु दिनांक 03.04.2020 को मृत्यु होना बताते हुए जन्म / मृत्यु रजिस्टीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) एवं छ.ग. जन्म मृत्यु रजि. नियम 2001 के नियम 9 नियत (3) के तहत मृत्यु प्रमाण पत्र हेतू आवेदक इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिस पर दिनांक 18.08.2026 को सुनवाई की जानी है।

आवेदक के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में किसी को कोई आपत्ति हो तो वो न्यायालय की पेशी 18.08.2026 तक अपना दावा / आपत्ति पेश कर सकता है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

मुहर
नायब तहसीलदार
लखनपुर सरगुजा (छ.ग.)

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा
ब्राउन शुगर विक्रय हेतु ई-निविदा आमंत्रण सूचना

भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्यादित कवर्धा द्वारा उत्पादन वर्ष 2025-26 मे उत्पादित ब्राउन शुगर लगभग 772 क्विंटल (जो कम / ज्यादा हो सकती है) के विक्रय हेतु कारखाने कार्यालय मे दिनांक 07/08/2026 से 13/08/2026 को दोपहर 02:00 बजे तक ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा मे ब्राउन शुगर क्रय हेतु न्यूनतम मात्रा 772 क्विंटल होगी, इससे कम मात्रा हेतु निविदा स्वीकार नही की जायेगी, ई-निविदा दिनांक 13/08/2026 को दोपहर 02:00 बजे पश्चात् खोला जायेगा, जिसमे निविदाकार/प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते है। निविदा प्रपत्र में प्रस्तावित ब्राउन शुगर के क्रय मूल्य का 10% ई.एम.डी. राशि केवल आर.टी.जी.एस./ बैंक ट्रांस्फर के माध्यम से भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना मर्या. कवर्धा के नाम एकाउन्ट नम्बर 19012191000743 पंजाब नेशनल बैंक कवर्धा शाखा आईएफएससी कोड PUNB0208520 मे जमा करना अनिवार्य होगा । निविदाकार को ब्राउन शुगर क्रय हेतु निविदा ई-टेंडर वेबसाइट https:eproc.cgstate.govt.in मे अपलोड किया जाना होगा । विस्तृत जानकारी कारखाना कार्यालय वेबसाइट www.Bssuk.co.in., एवं मो. नं. 9039584027, 9179197556 से प्राप्त की जा सकती है

महाप्रबंधक

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स क्लीन कोल इंटरप्राइजेज प्रा. लि., ग्राम-गतोरा, तहसील-मस्तूरी, जिला-बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा संचालित 2.50 मिलियन टन प्रति वर्ष (MTPA) क्षमता की वेट कोल वॉशरी के क्षमता विस्तार (Expansion) 2.50 MTPA से 5.00 MTPA हेतु प्रस्तावित परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमांक J-11015/410/2013-IA-II(M) दिनांक 16.06.2026 के माध्यम से उक्त क्षमता विस्तार परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति (Environmental Clearance - EC) प्रदान की गई है।पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र एवं उससे संबंधित दस्तावेज मंत्रालय की वेबसाइट https://environmentclearance.nic.in पर देखे जा सकते हैं। साथ ही इसकी प्रति छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के मुख्य कार्यालय, पर्यावरण परिसर, अटल नगर नवा रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर तथा जिला कार्यालय बिलासपुर में अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

सूचनार्थ

क्लीन कोल इंटरप्राइजेज प्रा. लि.
ग्राम-गतोरा, तहसील-मस्तूरी,
जिला-बिलासपुर (छ.ग.)

कार्यालय अधीक्षण अभियंता,
लोक निर्माण विभाग, रायपुर मण्डल क्रमांक 1 (छत्तीसगढ़)
निविदा सूचना

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है :-

एन.आई.टी. क्र. / सिस्टम टेन्डर नं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत रू. (लाख में)
1	2	3
39/195202	Estimate for Room for Various Purpose at Family Court, Raipur (C.G) (तृतीय आमंत्रण)	रू. 59.02 लाख
07/195323	Road safety work for Vidhansabha road to Haritage Hospital Kachna Raipur (C.G.) (पंचम आमंत्रण)	रु. 131.05 लाख
10/195324	Construction of (Balance Work) 4 Way Direction Cc Road, Bt Road & Drain Work (Length - 2.373 km) at Pt. Jawahar Lal Nehru, Ward No.2, Kabeer Nagar, Municipal Corporation, Raipur I/C Culverts At Dist. Raipur (चतुर्थ आमंत्रण)	रु. 124.59 लाख
304/195974	Special Repair work in (1) Km-3/2 & Km-3/4 (100m) to KM-3/8 in Borid to Mokhla Road (VR-113), (2) KM 59/8, 72/2 & KM 78/4 in Simga Tilda Kharora Arang Nawapara Kurud (SH-20) Road, (3) at Km 8/4 (Length= 180Meter) in Charoda Gidhwa Chhatera (MDR-305) Road, (4) in KM 16/2 to 16/4(100m), in Paragaon Goinda Tila (MDR-220) Road, (तृतीय आमंत्रण)	रु. 85.06 लाख
152/194983	Construction of Boundary Wall, Drain Line & Renovation Work for Govt. College Mana at Mana Camp, Raipur (C.G.) (प्रथम आमंत्रण)	रू. 43.37 लाख
153/194984	Construction of Govt. High School Building at Puraina, Raipur, C.G.(As Per Revised Approved Drawing) (प्रथम आमंत्रण)	रु. 68.39 लाख
154/194985	उपसंभाग क्र.-1 के अंतर्गत उपखंड क्र-4 में गैर आवासीय भवन में विशेष मरम्मत, लघुमुल गौण कार्य एवं डिपॉजिट कार्य। (प्रथम आमंत्रण)	रू. 25.00 लाख

एन.आई.टी. क्र.39 सिस्टम टेन्डर नं. 195202, एन.आई.टी. क्र. 07 सिस्टम टेन्डर नं. 194227, एन.आई.टी. क्र.10 सिस्टम टेन्डर नं. 195324 एवं एन.आई.टी. क्र.304 सिस्टम टेन्डर नं. 195974 निविदा डाउनलोड़ करने की अंतिम तिथि दिनांक 13.08.2026 समय सायं 5:30 बजे तक एवं एन.आई. टी. क्र.152 सिस्टम टेन्डर नं. 194983, एन.आई.टी. क्र.153 सिस्टम टेन्डर नं. 194984 एवं एन.आई.टी. क्र. 154 सिस्टम टेन्डर नं. 194985, निविदा डाउनलोड़ करने की अंतिम तिथि दिनांक 23.08.2026 समय सायं 5:30 बजे तक

उपरोक्त निर्माण कार्यों की निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी https://eproc.cgstate.gov.in पर देखी जा सकती है. एवं डाउनलोड की जा सकती है।

अधीक्षण अभियंता,
लो.नि.वि., रायपुर मंडल क्रं.-1, रायपुर (छ.ग.)

जी- 262702587/3

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
शाखाः जांजगीर, जिला- जांजगीर-चाम्पा (छ.ग.) 495668
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (1)] के तहत

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **बैंक ऑफ बड़ौदा**, का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) **सहपठित नियम 3** प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में मांग सूचना जारी की थी तथा ऋणी को मांग सूचना में उल्लिखित धनराशि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का भुगतान सूचना प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर करने को कहा गया था। ऋणी के यह राशि लौटाने में विफल होने पर ऋणी/बंधककर्ता और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त नियम के **नियम 8** के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में एतस्मिन नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य (कब्जा) नीचे वर्णित दिनांक को ग्रहण कर लिया है तथा जिसका विवरण अधोवर्णित है।

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता (ओं) का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों के मोचन के लिये उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिये आमंत्रित किया गया है।

ऋणी/बंधककर्ता को विशिष्ट रूप से और सर्वसाधारण को सामान्य रूप से एतद् द्वारा सम्पत्ति के साथ व्यवहार (क्रय-विक्रय) नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और उक्त सम्पत्ति का **किसी भी प्रकार से क्रय-विक्रय बैंक ऑफ बड़ौदा के मूल ब्याज व अन्य व्यय के भार के अधीन होगा** जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

क्र. सं.	गारंटर/ऋणी का नाम	बंधक संपत्ति का विवरण एवं संपत्ति का स्वामी	मांग सूचना की तिथि / कब्जा सूचना की तिथि / कब्जा के प्रकार	मांग पत्र तिथि को बकाया राशि
1.	ऋणी श्री बीरबल निषाद पुत्र उत्तम निषाद	श्री बीरबल निषाद पुत्र उत्तम निषाद के संपत्ति से संबंधितः आवासीय भूमि/मकान खसरा नं. 732/10, शंकर नगर, पीसी नं. 63, वार्ड नं. 28, महर्षि वाल्मीकि वार्ड, रायपुर, छत्तीसगढ़ । क्षेत्रफल 1250.00 वर्ग फुट में स्थित भूमि एवं भवन का साम्यिक बंधक । चौहद्दीः उत्तर- मुस्लिम भाई की भूमि, दक्षिण- तिवारी की भूमि, पूर्व- सड़क, पश्चिम- सड़क ।	20/05/2026 / 30/07/2026 / सांकेतिक कब्जा	₹ 39,98,680.15 साथ में उस पर ब्याज
2.	ऋणी पंकज केशरवानी एवं श्रीमती अनिता बाई	श्रीमती अनिता बाई केशरवानी से संबंधित संपत्ति- डायवर्टेड भूमि खसरा नं. 3638/2 क्षेत्रफल 0.01 एकड़, 3641/3 क्षेत्रफल 0.04 एकड़, प.ह.नं. 12, ग्राम- बिर्रा, रा.नि.मं.- बिर्रा एवं तहसील- बाम्हनीडीह, जिला- जांजगीर-चांपा में स्थित भूमि एवं भवन का साम्यिक बंधक । चौहद्दीः उत्तर- बालमुकुंद की भूमि, दक्षिण- प्रतिभा केशरवानी की भूमि, पूर्व- सड़क, पश्चिम- अमरनाथ कश्यप की भूमि ।	20/05/2026 / 30/07/2026 / सांकेतिक कब्जा	₹ 23,90,019.00 साथ में उस पर ब्याज

दिनांक : 06.08.2026 स्थान : जांजगीर-चांपा (छ.ग.) प्राधिकृत अधिकारी / बैंक ऑफ बड़ौदा

सेवा सेतु
जनता के द्वार, डिजिटल सरकार
डिजिटल सुशासन की नई पहचान
सेवाएं हुईं त्वरित, पारदर्शी और आसान
श्री विष्णु देव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़
श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री
प्रमुख सेवाएं
✓ जाति प्रमाण पत्र
✓ आय प्रमाण पत्र
✓ निवास प्रमाण पत्र
✓ विवाह प्रमाण पत्र
✓ राशन कार्ड सेवाएं
✓ पेंशन योजनाएं
✓ नाम परिवर्तन सेवा
✓ व्यापार लाइसेंस
सेवा सेतु
जनता के द्वार, डिजिटल सरकार
sewasetu.cgstate.gov.in
आपकी ज़रूरत की सेवाएं, अब घर बैठे एक क्लिक में
639 सेवाएँ
36 विभाग एक मंच पर
सेवा केंद्र
17,065 सेवा केंद्र
45 लाख+ आवेदन
S-48665
अधिक जानकारी हेतु
स्कैन करें
जनहित में तकनीक, जनसेवा में नवाचार
sewasetu.cgstate.gov.in
92034 06400

भारतीय रेल ने लाइसेंसिंग व्यवस्था को बनाया सरल, एक लाइसेंस से सभी मार्गों पर परिचालन

अलग-अलग पंजीकरण शुल्क लेने की मौजूदा व्यवस्था खत्म

बिलासपुर/नवप्रदेश। भारतीय रेल ने भारतीय रेल नेटवर्क पर कंटेनर ट्रेनों के परिचालन के लिए ऑपरेटरों को अनुमति देने संबंधी मॉडल कन्सेशन एग्रीमेंट (एमसीए) में संशोधनों को मंजूरी दी है। स्वीकृत संशोधनों के तहत अब कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों (सीटीओ) को अलग-अलग मार्ग श्रेणियों के लिए पृथक अनुमति और शुल्क की मौजूदा व्यवस्था के स्थान पर 25 करोड़ रुपए के एकसमान पंजीकरण शुल्क के साथ सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस के आधार पर भारतीय रेल नेटवर्क के सभी मार्गों पर कंटेनर ट्रेनों का परिचालन करने की अनुमति होगी। इन संशोधनों को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

स्वीकृत संशोधनों के तहत लाइसेंस की वर्तमान मार्ग-वार श्रेणीकरण व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। रेल मंत्रालय की स्वीकृति के अधीन, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटरों को सिंगल ऑल इंडिया लाइसेंस प्रदान किया जाएगा, जिससे वे भारतीय रेल नेटवर्क के सभी मार्गों पर कंटेनर ट्रेनों का परिचालन कर सकेंगे। विभिन्न मार्ग श्रेणियों के लिए अलग-अलग पंजीकरण शुल्क लेने की मौजूदा व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब प्रत्येक आवेदक को भारतीय रेल नेटवर्क के सभी मार्गों पर परिचालन के लिए 25 करोड़ रुपये का अप्रतिदेय एकसमान पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा। एक समान पंजीकरण शुल्क तथा लाइसेंस विस्तार शुल्क समाप्त किए जाने से ऑपरेटरों के नियामकीय एवं अनुपालन संबंधी खर्चों में कमी आएगी तथा अनुमोदन प्रक्रिया सरल होगी। सरल लाइसेंसिंग व्यवस्था से निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा तथा कंटेनर ट्रेन परिचालन का विस्तार होगा, जिससे देशभर में रेल आधारित माल परिवहन को प्रोत्साहन मिलेगा।

ऑपरेटरों को राहत

कैटेगरी-1 लाइसेंसधारी ऑपरेटर अपनी वर्तमान श्रेणी के अंतर्गत अपनी कन्सेशन अवधि समाप्त होने तक परिचालन जारी रख सकेंगे। नई लाइसेंस व्यवस्था के तहत नवीनीकरण या विस्तार के समय उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। कैटेगरी- 2, 3 और 6 के ऑपरेटर भी अपनी वर्तमान श्रेणियों के अंतर्गत अपनी कन्सेशन अवधि पूरी होने तक परिचालन जारी रख सकेंगे। नई लाइसेंस व्यवस्था के तहत नवीनीकरण या विस्तार के लिए उन्हें 15 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। यह राशि नए 25 करोड़ रुपये के शुल्क और पहले से जमा किए गए 10 करोड़ रुपये के बीच का अंतर है। यह राशि अप्रतिदेय होगी। ये ऑपरेटर अपनी 20 वर्ष की कन्सेशन अवधि पूरी होने से पहले भी नई लाइसेंस व्यवस्था में स्थानांतरित होने का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसी स्थिति में भी उन्हें 15 करोड़ रुपये का ही भुगतान करना होगा। स्वीकृत संशोधनों के अनुसार, कंटेनर ट्रेन ऑपरेटर को दी गई अनुमति की अवधि समाप्त होने के बाद उसे आगे 20 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकेगा। यह विस्तार सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऑपरेटर के आवेदन तथा उसके संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर प्रदान किया जाएगा। इस विस्तार अथवा भविष्य में उसी ऑपरेटर को दिए जाने वाले किसी भी अन्य विस्तार के लिए कोई विस्तार शुल्क नहीं लिया जाएगा।

न्यूज गैलरी

आईटीआई की परीक्षाएं 17 से आज आवेदन की अंतिम तिथि

बिलासपुर/नवप्रदेश। राज्य व्यावसायिक परीक्षा (एससीवीटी) एवं हायर सेकेंडरी-आईटीआई संयुक्त अध्यापन योजना के अंतर्गत आईटीआई ट्रेड की प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक परीक्षाएं 17 अगस्त से 24 अगस्त तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं के लिए पात्र प्रशिक्षणार्थियों से 7 अगस्त तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जारी जानकारी के अनुसार परीक्षा में सत्र 2025-26 के एक वर्षीय व्यवसाय, सत्र 2025-27 के द्विवर्षीय व्यवसाय के प्रथम वर्ष तथा सत्र 2024-26 के द्विवर्षीय व्यवसाय के द्वितीय वर्ष के नियमित प्रशिक्षणार्थी शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा सत्र 2023-25 के द्विवर्षीय व्यवसाय के द्वितीय वर्ष, सत्र 2024-26 के द्विवर्षीय व्यवसाय के प्रथम वर्ष, सत्र 2024-25 के एक वर्षीय एवं छह माह के व्यवसाय तथा सत्र 2023-24 के छह माह और सत्र 2022-24 के द्विवर्षीय व्यवसाय के ऐसे पूरक प्रशिक्षणार्थी, जिनके प्रयास शेष हैं, भी परीक्षा के लिए आवेदन करने के पात्र होंगे। परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक सभी पात्र प्रशिक्षणार्थियों को 7 अगस्त तक आवेदन जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

नहर निर्माण के लिए 16.86 एकड़ भूमि अधिग्रहण की अनुशंसा

बिलासपुर/नवप्रदेश। जिले की बेलगहना तहसील के ग्राम लूफा में प्रस्तावित नहर निर्माण के लिए 16.86 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की अनुशंसा की गई है। सामाजिक समाघात दल द्वारा किए गए मूल्यांकन में पाया गया कि प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण से किसी मकान या अन्य संरचना पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और किसी भी परिवार के विस्थापन की आवश्यकता नहीं होगी। सामाजिक समाघात दल ने ग्राम लूफा में भू-अर्जन से होने वाले प्रभावों का विस्तृत आकलन किया। अध्ययन के दौरान प्रभावित किसानों से भी सहमति ली गई। मूल्यांकन में यह भी सामने आया कि प्रस्तावित परियोजना से किसी प्रकार की सार्वजनिक अधोसंरचना प्रभावित नहीं होगी और न ही विकास कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न होगी। दल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जल संसाधन विभाग द्वारा नहर निर्माण के लिए केवल आवश्यक भूमि का ही अधिग्रहण किया जा रहा है।

दूसरी पत्नी ने दो शादी करने की शिकायत की थी

दूसरी शादी के मामले में पुलिस अफसर को हाईकोर्ट से राहत

बिलासपुर/नवप्रदेश। दूसरी शादी के मामले में पुलिस अफसर के खिलाफ 15 साल बाद शुरू हुई विभागीय कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी की सिंगल बेंच ने वर्ष 2023 में जारी चार्जशीट को रद्द करते हुए उससे जुड़ी पूरी विभागीय कार्रवाई खत्म कर दी। कोर्ट ने कहा कि जब विभाग को वर्ष 2008 में ही दूसरी शादी की जानकारी हो गई थी, तो करीब 15 साल तक कार्रवाई नहीं करने के बाद अचानक विभागीय कार्रवाई शुरू करना उचित नहीं है।

मामला यह है कि पुलिस अधिकारी इरफान-उल-रहीम खान ने वर्ष 2007 में दूसरी शादी की थी। उन्होंने 2008 में ही विभाग को इसकी जानकारी देते हुए दूसरी शादी की अनुमति के लिए आवेदन किया था। इसके बावजूद लंबे समय तक विभाग की ओर से

कोई विभागीय कार्रवाई नहीं की गई। बाद में दूसरी पत्नी की ओर से 2017 और 2019 में शिकायतें किए जाने के बाद मामला फिर सामने आया और अंततः 14 फरवरी 2023 को अधिकारी को चार्जशीट जारी कर दी गई। अधिकारी ने हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए कहा कि विभाग को शादी की जानकारी पहले से थी और इतनी लंबी देरी के बाद कार्रवाई शुरू करना अनुचित है। वहीं राज्य सरकार ने दावा किया कि अनुमति के लिए दिया गया आवेदन वर्ष 2013 में ही खारिज कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि आवेदन खारिज किए जाने का कोई आदेश या दस्तावेज रिकॉर्ड में पेश नहीं किया गया था। उल्टा 2019 की विभागीय रिपोर्ट में आवेदन को विचाराधीन बताया गया था। कोर्ट ने कहा कि विभागीय कार्रवाई के लिए भले ही कोई तय समय-सीमा न हो, लेकिन कार्रवाई उचित समय में होनी चाहिए। करीब 15 साल की इस अस्पष्ट देरी से अधिकारी के बचाव का अधिकार भी प्रभावित हो सकता है। हाईकोर्ट ने इसे अनुचित मानते हुए चार्जशीट और उससे जुड़ी पूरी विभागीय कार्रवाई को रद्द कर दिया।

शादीशुदा बहन भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार

हाईकोर्ट के जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने यह टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार के 19 सितंबर 2019 के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही मृतक की शादीशुदा बहन को अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है। दरअसल, बिलासपुर नेहरू नगर के रहने वाले दुर्गेश मिश्रा जांजगीर-चांपा में जिला लोक अभियोजन अधिकारी के पद पर पदस्थ थे। 13 जून 2018 को सेवा में रहते हुए उनका निधन हो गया। मृतक अविवाहित थे। मिश्रा के निधन के बाद उनकी बुजुर्ग मां तारा मिश्रा ने साल राज्य शासन की 2013 की अनुकंपा नीति के तहत अपनी बेटी अमिता दुबे और मृतक की बहन को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग करते हुए आवेदन पेश किया। राज्य सरकार के गृह एवं सामान्य प्रशासन विभाग ने 19 सितंबर 2019 को यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया था कि अनुकंपा नियुक्ति नीति में विवाहित बहन को अनुकंपा नियुक्ति देने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। शासन के इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। पीड़ित परिवार ने याचिका में बताया कि सुप्रीम कोर्ट के कुलसुम निशा विरुद्ध यूपी राज्य और सायरा खातून बनाम बिहार राज्य के मामलों में दिए गए फैसलों के अनुसार, केवल शादी हो जाने से किसी बेटी या बहन का अपने मूल परिवार से नाता खत्म नहीं होता। शासन की नीति में स्पष्ट उल्लेख है कि अविवाहित शासकीय सेवक के निधन पर माता-पिता की अनुशंसा पर उसके भाई-बहन को नियुक्ति दी जाएगी। जब विवाहित बेटे या भाई को अलग नहीं किया जाता, तो केवल शादीशुदा होने के आधार पर बहन के साथ भेदभाव करना संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15(1)का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि, अनुकंपा नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य परिवार के कमाऊ सदस्य की असमय मृत्यु के बाद संकटग्रस्त परिवार को तुरंत वित्तीय राहत पहुंचाना है। इसमें मुख्य मानदंड आर्थिक निर्भरता और वित्तीय जरूरत है, न कि वैवाहिक स्थिति। वर्तमान समाज में कई शादीशुदा बेटियां-बहनें अपने माता-पिता और परिवार का सहारा बनती हैं।

नक्सली हमले में शहीद परिवार का भाजयुमो ने किया सम्मान

सीपत/नवप्रदेश। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) जिला ग्रामीण द्वारा संचालित 'हर घर तिरंगा' अभियान के अंतर्गत बुधवार को भाजयुमो सीपत मंडल के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने नक्सली हमले में शहीद हुए स्वर्गीय विनोद कौशिक के निवास पहुंचकर उनके परिजनों से आत्मीय भेंट की।

इस दौरान शहीद के पिता उमाशंकर कौशिक को राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया तथा देश की रक्षा में दिए गए उनके पुत्र के सर्वोच्च बलिदान को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर भाजयुमो जिला अध्यक्ष ऋषभ चतुर्वेदी ने कहा कि तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि देश की अस्मिता, गौरव और वीर शहीदों के अदम्य साहस एवं सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों का सम्मान करना प्रत्येक देशवासी का नैतिक दायित्व है और ऐसे परिवारों के प्रति समाज का सम्मान सदैव बना रहना चाहिए। भाजयुमो जिला महामंत्री तुषार चंद्राकर ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान केवल घर-घर तिरंगा फहराने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रप्रेम, देशसेवा और शहीदों के त्याग व बलिदान के प्रति सम्मान की भावना जागृत करना है। उन्होंने कहा कि शहीद परिवारों का सम्मान करना पूरे समाज के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। कार्यक्रम में भाजयुमो जिला महामंत्री अंकुर सिंह, जिला कार्यालय मंत्री यश गौरहा, मंडल महामंत्री मिथलेश, मंडल उपाध्यक्ष ओम पाटनवार, यश प्रजापति सहित भारतीय जनता युवा मोर्चा के अनेक पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सभी ने शहीद विनोद कौशिक के बलिदान को नमन करते हुए राष्ट्रसेवा और राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

नई शिक्षा नीतिः व्यावहारिक क्षमता का विकास व भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकें

सीपत/नवप्रदेश। शासकीय मदनलाल शुक्ल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए इंडक्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को महाविद्यालयीन वातावरण, शैक्षणिक व्यवस्था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की विशेषताओं तथा उपलब्ध सुविधाओं से परिचित कराना रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आर. एस. खेर ने की।

उन्होंने विद्यार्थियों का स्वागत करते हुए महाविद्यालय की अधोसंरचना, शैक्षणिक एवं अन्य सुविधाओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बदलते समय और जीवनशैली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यह नीति लागू की गई है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को केवल पुस्तकीय ज्ञान तक सीमित न रखकर उनके कौशल, रचनात्मकता, नवाचार और व्यावहारिक क्षमता का विकास करना है, ताकि वे भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना कर सकें। महाविद्यालय की सांस्कृतिक प्रभारी श्वेता पंड्या ने वर्षभर आयोजित होने वाली सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों की जानकारी देते हुए विद्यार्थियों से उनमें सक्रिय सहभागिता निभाने का आह्वान किया। इस अवसर पर डॉ. आर. एन. पटेल, डॉ. के. वेणु आचारी एवं भूपेंद्र देवांगन ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत पाठ्यक्रम चयन, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट व्यवस्था, क्रेडिट प्रणाली, सीआईए (सतत आंतरिक मूल्यांकन), परीक्षा पद्धति एवं अन्य शैक्षणिक प्रावधानों की विस्तार से जानकारी देकर विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. राम प्रसाद चन्द्रा एवं शत्रुघ्न धृतलहरे ने किया, जबकि आभार प्रदर्शन जीवन प्रभाकर गोरे ने किया।

कार्यशाला में जीने के व्यावहारिक उपायों से अवगत कराया

बिलासपुर/नवप्रदेश। मैढ़ क्षत्रिय मारवाड़ी सोनी समाज के तत्वावधान में आयोजित 'द आर्ट ऑफ इमोशनल रिलीज' ओरिएंटेशन वर्कशॉप का आयोजन संपन्न हुआ। समाज के वरिष्ठ प्रशिक्षक भवानी शंकर, जिनके पास इस क्षेत्र में लगभग 15 वर्षों का अनुभव है, ने प्रतिभागियों को भावनात्मक संतुलन, मानसिक शांति एवं जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से जीने के व्यावहारिक उपायों से अवगत कराया। कार्यशाला में समाज के अनेक सदस्यों ने सहभागिता की। तीन घंटे के इस सत्र में प्रतिभागियों ने भावनाओं को समझने, तनाव को कम करने, मानसिक स्पष्टता बढ़ाने तथा स्वयं से जुड़ने की विभिन्न सरल एवं प्रभावी तकनीकों का अनुभव किया। कार्यक्रम के पश्चात प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि इस कार्यशाला से उन्हें मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा, आत्मविश्वास तथा जीवन को नई दिशा से देखने की प्रेरणा मिली। कई प्रतिभागियों ने इसे अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक एवं व्यावसायिक जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी बताया। उन्होंने यह भी कहा कि आध्यात्म और विज्ञान के समन्वय से प्रस्तुत यह कार्यशाला उनके लिए एक अनूठा और प्रेरणादायक अनुभव रही। अंत में प्रतिभागियों ने भवानी शंकर के मार्गदर्शन की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया। समाज के अध्यक्ष सजन सोनी के मार्गदर्शन में जीण सेना के सभी सदस्य भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी, व्यक्तित्व विकास एवं समाजहित से जुड़े कार्यक्रमों का निरंतर आयोजन करेंगे। उनका उद्देश्य समाज में एकता, संगठन और आपसी सहयोग की भावना को और अधिक सुदृढ़ करना है। जीण सेना का मानना है कि युवाओं की मेहनत, लगन और सकारात्मक सहभागिता ही समाज को मजबूती प्रदान करेगी।

विद्यार्थियों को दिलाई नशा मुक्ति की शपथ

बिलासपुर/नवप्रदेश। आंध्रा समाज द्वारा संचालित आंध्रा समाज स्कूल, बुधवारी बाज़ार, रेलवे परिक्षेत्र, बिलासपुर में आज विद्यार्थियों के मध्य 'नशा मुक्त भारत - स्वस्थ भारत' अभियान के अंतर्गत नशा मुक्ति शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना तथा उन्हें स्वस्थ, अनुशासित एवं संस्कारित जीवन के लिए प्रेरित करना था। कार्यक्रम में विद्यालय के प्राचार्य, सी एच दया मानी, प्रधान पाटिका आर वरलक्ष्मी, प्रधान पटाक एम श्रीनिवास राव कृष्वेणी, राजेश सिंह, शिक्षकगण एवं समस्त विद्यार्थियों की उपस्थिति में सभी ने सामूहिक रूप से नशा मुक्ति की शपथ ली। विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि वे अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करेंगे तथा अपने परिवार, मित्रों और समाज के लोगों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। शपथ के दौरान विद्यार्थियों ने यह भी संकल्प लिया कि वे अपने शरीर एवं मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे संस्कार, नियमित अध्ययन, खेलकूद, योग एवं सकारात्मक जीवन मूल्यों को अपनाएंगे। साथ ही अपने विद्यालय एवं समाज को नशा मुक्त बनाने में सक्रिय सहभागिता निभाते हुए एक जिम्मेदार, जागरूक एवं आदर्श नागरिक बनने का प्रयास करेंगे।

जागरुकताः नवीन कानून के प्रावधानों व लोगों को अधिकारों के लिए किया जागरुक

अपराधी में हो पुलिस का डर, आम लोगों को पुलिस से सुरक्षा का दिलाएं भरोसाः सिंह

बिलासपुर/नवप्रदेश। बिलासपुर पुलिस द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रजनेश सिंह आईपीएस के निर्देशन पर सार्वजनिक स्थलों पर विभिन्न कार्यक्रम के दौरान लोगों को नवीन कानून/ न्याय सहिंता के प्रमुख प्रावधानों और नागरिकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए पुलिस अधिकारी कर्मचारी द्वारा फ्लैक्स वीडियो एवं संदेश के माध्यम से लोगों को जानकारी दे रहे हैं।

इस दौरान पुलिस लाइन, थाना चौकी द्वारा अपने अपने क्षेत्रों के प्रमुख स्थानों पर लोगों को संबोधित करते हुए न्याय सहिंता के प्रावधान और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। महिला, बच्चे, युवा व वरिष्ठ नागरिक प्रत्येक वर्ग के लोगों को नवीन कानून के प्रावधानों की जानकारी दी जा रही है। पुलिस ग्राउंड पर कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें 2000 से अधिक लोगों को जागरूक किया गया। सिम्स ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ डांस चैंपियन सीजन-3 में जिला के साथ राज्य के कई कलकारों ने हिस्सा लिया जिनको लगातार

19/7/2026 से 24/7/2026 तक प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें प्रतिदिन 2000 नागरिकों जानकारी पीपीटी,फ्लैक्स और संदेश के माध्यम से नवीन कानून के प्रावधानों का जानकारी दिया गया साथ साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक रजनेश सिंह द्वारा लोगों को संबोधन करते हुए न्याय सहिंता के प्रावधान जिसमें महिला सशक्तिकरण, बाल संरक्षण, संगठित अपराधों और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि पुलिस के प्रति भय का वातावरण केवल उनको होना चाहिए जो अपराध में लिप्त है, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होकर समाज को प्रभावित कर रहे उनको पुलिस से डर होना चाहिए। आम लोगों को पुलिस से डरने की आवश्यकता नहीं पुलिस के साथ फ्रेंडली विहेवीयर रखना चाहिए ताकि जनता और पुलिस के बीच सकारात्मक संवाद और तालमेल बने, समाज के प्रत्येक अच्छे बुरे की जानकारी पुलिस तक पहुँच सके और सामुदायिक पुलिसिंग, बेसिक पुलिसिंग, और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से समाज की सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके। इसी क्रम में पुलिस विभाग द्वारा समय समय पर ज़िले के विभिन्न महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शनी लगाकर लोगों को जागरुक किया जा रहा है, 26-7-2026 को कारगिल विजय दिवस के अवसर पर लखीराम ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान फ्लैक्स वीडियो द्वारा 1000 लोगों को जागरूक किया गया। पुलिस विभाग द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे और अन्य पुलिस अधिकारी कर्मचारी द्वारा लगातार प्रमुख स्थानों पर लोगों को जागरूक करने हेतु अनेक स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

जिले में अब तक 621 मिमी वर्षा

बिलासपुर/नवप्रदेश। जिले में एक जून से अब तक 621. 5 मिली मीटर वर्षा हो चुकी है। सबसे अधिक वर्षा बिलासपुर तहसील में हुई है।

क्रमांक	जिला/तहसील	आज दिनांक की वर्षा	01 जून 2026 से आज दिनांक तक की वर्षा	विगत 10 वर्षों के आधार पर 1 जून से आज दिनांक तक की औसत वर्षा
1	2	3	4	5
1	बिलासपुर	9.2	710.2	590.8
2	बिल्हा	29.0	597.6	542.7
3	मस्तूरी	13.2	648.4	536.2
4	तखतपुर	17.2	610.0	609.1
5	कोटा	12.0	500.4	566.9
6	सीपत	28.5	597.5	542.8
7	बोदरी	21.3	704.4	542.3
8	बेलगहना	18.0	604.6	591.6
9	बेलतरा	15.3	544.1	570.3
10	रतनपुर	17.4	617.0	574.8
11	सकरी	20.6	737.8	617.2
12	पचपेड़ी	15.5	586.4	533.0
जिले का योग		217.2	7458.4	6817.7
जिले का औसत		18.1	621.5	568.1

बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों को कौशल, प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने की अनूठी पहल

■ मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की संवेदनशील शुरुआत

रायपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन की महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत अनाथ एवं निराश्रित बच्चों के पुनर्वास, कौशल विकास और आत्मनिर्भर भविष्य की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय पहल की है। इसी क्रम में उन्होंने अपने निवास कार्यालय में एक्सिस बैंक के भारत प्रमुख विजय तथा 'कैटलिस्ट फॉर सोशल एसोसिएशन' की भारत प्रमुख सुश्री स्मिता रांधे से मुलाकात की। इस दौरान बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और रोजगारोन्मुख अवसरों से जोड़ने के विषय पर व्यापक चर्चा की गई।

बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता: बैठक में एक्सिस बैंक के सी.एस.आर. फंड के माध्यम से बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों को आवश्यक सुविधाएं देने, कौशल आधारित प्रशिक्षण सिखाने और अंततः उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए ठोस सहयोग पर विचार-विमर्श हुआ। यह पहल बच्चों को केवल संस्थागत संरक्षण तक सीमित न रखकर उन्हें एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने का बड़ा प्रयास है। मंत्री राजवाड़े ने इस दौरान कहा, अनाथ और निराश्रित बच्चों को शिक्षा, कौशल और रोजगार से जोड़ना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमारा यह प्रयास है कि बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाला प्रत्येक बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ समाज की मुख्यधारा में आगे बढ़े।

सभी जिलों में होगा योजना का विस्तार: मंत्री ने जानकारी दी कि लगभग एक वर्ष पूर्व सामुदायिक सहयोग से बाल संरक्षण एवं बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों के सामाजिक पुनर्वास के लिए यह सराहनीय पहल शुरू की गई थी। वर्तमान में प्रदेश के पांच जिलों में इसका सफल क्रियान्वयन किया जा चुका है, और अब इसे और विस्तार देते हुए राज्य के सभी जिलों में लागू करने की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। श्रीमती राजवाड़े ने जोर देते हुए कहा कि राज्य सरकार, सामाजिक संस्थाओं, कॉरपोरेट क्षेत्र और औद्योगिक घरानों के सामूहिक सहयोग से बच्चों के समग्र विकास के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे। बाल देखरेख संस्थाओं के बच्चों को डिजिटल प्रशिक्षण, रोजगार मार्गदर्शन और आत्मनिर्भरता के अवसर उपलब्ध कराना आज के समय की सबसे बड़ी मांग है।

- **महत्वपूर्ण पहल:** छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने अनाथ और निराश्रित बच्चों के पुनर्वास व आत्मनिर्भर भविष्य के लिए राज्य स्तरीय कदम उठाया है।
- **बैठक और सहयोग:** एक्सिस बैंक के भारत प्रमुख विजय और 'कैटलिस्ट फॉर सोशल एसोसिएशन' की भारत प्रमुख सुश्री स्मिता रांधे के साथ निवास कार्यालय में विस्तृत चर्चा हुई।
- **सी.एस.आर. फंड का उपयोग:** एक्सिस बैंक के सी.एस.आर. फंड के जरिए बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे।
- **विस्तार योजना:** वर्तमान में प्रदेश के 5 जिलों में सफल क्रियान्वयन के बाद अब इसे राज्य के सभी जिलों में लागू करने की कार्ययोजना बनाई जा रही है।

न्यूज गैलरी

कवर्धा जिले के सरपंचों और जनप्रतिनिधियों के लिए चार दिवसीय विशेष प्रशिक्षण आयोजित

कवर्धा/नवप्रदेश। 'विकसित भारत - रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम' के तहत जिले के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का चार दिवसीय विशेष प्रशिक्षण 4 से 7 अगस्त तक जिला पंचायत संसाधन केंद्र, डंगनिया में आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान जनपद पंचायत कवर्धा, बोड़ला, सहसपुर लोहारा और पंडरिया क्षेत्र के सरपंचों को नई योजना के सभी जरूरी प्रावधानों से परिचित कराया जा रहा है। प्रशिक्षण शिविर में ग्रामीणों को 125 दिवस का रोजगार देने की कार्ययोजना, ग्राम पंचायतों में कार्यों की पहचान, परिसंपत्तियों का निर्माण, रोजगार प्रदान करने की व्यवस्था, मजदूरी भुगतान की प्रणाली, पारदर्शिता और 'युक्त धारा पोर्टल' जैसे सभी महत्वपूर्ण विषयों पर सरपंचों का ज्ञानवर्धन किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य जनप्रतिनिधियों की क्षमता का विकास करना है ताकि योजना का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कबीरधाम, अभिषेक अग्रवाल ने प्रशिक्षण में उपस्थित रहकर सरपंचों को योजना के नवीन प्रावधानों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण के बिना संभव नहीं है। ऑनलाइन अटेंडेंसः उन्होंने एनएमएमएस (हस्र्स) के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने और युक्त धारा पोर्टल से कार्यों की स्वीकृति व समय पर मजदूरी भुगतान के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि पुरानी महात्मा गांधी नरेगा योजना में कई जनकल्याणकारी संशोधन करते हुए केंद्र सरकार ने 'विकसित भारत जी राम जी योजना' लागू की है, जो जिले में 2 जुलाई 2026 से प्रभावशील हो चुकी है। प्रशिक्षण के दौरान जिला पंचायत के सहायक परियोजना अधिकारी विनायक गुप्ता, समन्वयक तकनीकी अशोक झारिया और कार्यक्रम अधिकारी लवकेश मरकाम द्वारा योजना के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। जिला पंचायत सदस्यः कबीरधाम जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू सहित सभी सदस्यों का प्रशिक्षण ठाकुर प्यारेलाल ग्रामीण विकास संस्थान, निमोरा (राज्य स्तर) में आयोजित किया गया, जहाँ आयुक्त द्वारा नए अधिनियम और बदलावों की जानकारी दी गई। कवर्धा, बोड़ला, सहसपुर लोहारा और पंडरिया के सभी जनपद सदस्यों का प्रशिक्षण दुर्ग संभाग मुख्यालय में चल रहा है, जिसमें ग्रामीण विकास की रूपरेखा और जनप्रतिनिधियों की भूमिका पर मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

इंटर्न डॉक्टरों की मांगों का कांग्रेस ने किया समर्थन

जगदलपुर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता जावेद खान ने इंटर्न डॉक्टरों की जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि इंटर्न डॉक्टरों का मासिक स्टाइपेंड 15,900 रुपये से बढ़ाकर तुरंत 30 हजार रुपये किया जाए। उन्होंने कहा कि बस्तर और सरगुजा जैसे दूरस्थ आदिवासी अंचलों में इंटर्न डॉक्टर दिन-रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन उन्हें उनकी बड़ी जिम्मेदारियों और वर्तमान महंगाई के अनुरूप सम्मानजनक स्टाइपेंड नहीं मिल रहा है। इसके अलावा, मौजूदा स्टाइपेंड भी समय पर न मिलने के कारण उन्हें गंभीर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जावेद खान ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है जहाँ इंटर्न डॉक्टरों को सबसे कम स्टाइपेंड दिया जाता है। उन्होंने बताया कि पड़ोसी राज्य ओडिशा में इंटर्न डॉक्टरों को 41 से 44 हजार रुपये तक स्टाइपेंड मिलता है, जबकि छत्तीसगढ़ में यह राशि मात्र 15,900 रुपये है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के समय इंटर्न डॉक्टरों को 12 हजार रुपये स्टाइपेंड मिलता था, जिसे पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में बढ़ाकर 15,900 रुपये किया गया था। प्रदेश प्रवक्ता ने कहा कि इंटर्न डॉक्टरों की इस हड़ताल से बस्तर संभाग सहित पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से अपील की है कि सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़कर इन युवा डॉक्टरों की जायज मांगों पर गंभीरता से विचार करे और शीघ्र समाधान निकालकर हड़ताल समाप्त कराए। कांग्रेस का कहना है कि इंटर्न डॉक्टर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ और एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यदि यह हड़ताल लंबी चली और आम जनता को स्वास्थ्य लाभ मिलने में दिक्कतें आईं, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। सरकार को तुरंत 30 हजार रुपये मासिक स्टाइपेंड लागू करने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।

हर गांव में मुक्तिधाम और हर बालिका के लिए स्कूलों में बनेगा शौचालय

मुख्यमंत्री ने 'मेरी बेटी-मेरा अभिमान' अभियान का किया शुभारंभ

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज महानदी भवन, नवा रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में विकसित भारतङ्करोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) वीबी-जी राम जी के अंतर्गत राज्यव्यापी 'मेरी बेटी-मेरा अभिमान' अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने घोषणा की कि 15 अगस्त 2026 से 26 जनवरी 2027 तक चलने वाले इस विशेष अभियान के दौरान प्रदेश के प्रत्येक गांव में मुक्तिधाम एवं प्रतीक्षालय का निर्माण सुनिश्चित किया जाएगा तथा ग्रामीण क्षेत्रों के सभी शासकीय विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान बेटियों के सम्मान, ग्रामीण स्वच्छता, सामाजिक गरिमा और आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने की दिशा में राज्य सरकार का ऐतिहासिक कदम है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने बताया कि अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के शासकीय विद्यालयों में 286.85 करोड़ रुपए की लागत से 6,671 बालिका शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। प्रत्येक शौचालय की लागत 4.30 लाख रुपए निर्धारित की गई है। इसी प्रकार प्रदेश के 6,524 गांवों में 391.44 करोड़ रुपए की लागत से प्रतीक्षालय सहित मुक्तिधाम बनाए जाएंगे, जिनकी प्रति इकाई लागत 6 लाख रुपए होगी।

ग्रामीण विकास और रोजगार का सबसे बड़ा अभियान

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि वीबी-जी राम जी योजना पूरे देश में 1 जुलाई 2026 से लागू हुई है। योजना के अंतर्गत सभी विकास कार्यों का चयन ग्राम सभा की स्वीकृति से किया जाएगा तथा मजदूरी की दर बढ़ाकर 300 रुपए प्रतिदिन कर दी गई है। उन्होंने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारतङ्क2047' के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में मनरेगा और वीबी-जी राम जी के माध्यम से राज्य को लगभग 6,855 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जो ग्रामीण रोजगार और विकास कार्यों के लिए राज्य में अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय निवेश है। भारत सरकार से योजना की प्रथम किस्त के रूप में 1,538 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति भी प्राप्त हो चुकी है।

318 प्रकार के विकास कार्यों से बदलेगी गांवों की तस्वीर

मुख्यमंत्री ने बताया कि योजना में 318 प्रकार के कार्यों को चार प्रमुख श्रेणियों में शामिल किया गया है। इनमें 107 प्रकार के जल संरक्षण एवं जल संवर्धन कार्य, 90 प्रकार के ग्रामीण अधोसंरचना विकास कार्य, 86 प्रकार के आजीविका संवर्धन कार्य तथा 35 प्रकार के जलवायु अनुकूलन एवं आपदा प्रबंधन संबंधी कार्य शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के अंतर्गत तालाब, चेकडैम, रिचार्ज संरचनाएं, सिंचाई विस्तार, भू-जल संरक्षण, मृदा संरक्षण और वृक्षारोपण को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं ग्रामीण अधोसंरचना के अंतर्गत सड़क, पुलिया, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, अतिरिक्त स्कूल कक्ष, ग्रामीण पुस्तकालय, प्रयोगशाला, किचन शेड, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, मुक्तिधाम और पशु चिकित्सालय जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

बायोफैच इंडिया-2026 में छाई छत्तीसगढ़ की गूंज

■ विष्णुभोग चावल और प्राकृतिक शहद ने बटोरी राष्ट्रीय सराहना

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के जैविक उत्पादों ने एक बार फिर राष्ट्रीय मंच पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। नई दिल्ली में आयोजित देश के सबसे बड़े जैविक उद्योग व्यापार मेले 'बायोफैच इंडिया-2026' में गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के महिला स्वसहायता समूहों और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा तैयार जैविक उत्पादों ने विशेष पहचान बनाई है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले के राष्ट्रीय स्टॉल में जिले के प्रसिद्ध 'अरपा बिहान विष्णुभोग राइस' और 'केवची के जंगलों से संग्रहित प्राकृतिक शहद' का आकर्षक प्रदर्शन किया गया।

इन उत्पादों ने देश-विदेश से पहुंचे खरीदारों, निर्यातकों और उद्योग विशेषज्ञों का ध्यान अपनी ओर खींचा, जिससे राज्य के जैविक उत्पादों के लिए नए राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजारों के द्वार खुले हैं। बिहान योजना के तहत महिलाएं अब केवल उत्पादन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बड़े व्यापारिक आयोजनों में भाग लेकर 'लखपति दीदी' अभियान को नई ऊंचाइयां दे रही हैं। जिला मिशन प्रबंधक दुर्गाशंकर सोनी ने बताया कि जिले में जैविक विष्णुभोग धान और शहद के साथ-साथ सूरन, कटहल और अन्य जैविक सब्जियों के उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अपनी उच्च गुणवत्ता और प्राकृतिक पद्धति के कारण राष्ट्रीय बाजार में इनकी मांग लगातार बढ़ रही है।

इस प्रतिष्ठित सम्मेलन में राज्य स्तर से राज्य कार्यक्रम प्रबंधक राजन सोनी, जिला कार्यक्रम प्रबंधक अभिषेक जायसवाल और तिपान किसान उत्पादक संगठन के सीईओ जितेन्द्र खैरवार ने भाग लिया तथा जिले के उत्पादों का प्रभावी प्रदर्शन कर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से सराहना प्राप्त की।

बस्तर के केंद्रीय विद्यालयों में स्थायी भवन व स्मार्ट क्लास की मांग

■ सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन

जगदलपुर/नवप्रदेश। बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बस्तर संभाग के केंद्रीय विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं के विस्तार, शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति तथा स्थायी भवनों के निर्माण की पुरजोर मांग उठाई और इस संबंध में मंत्री को एक विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा।

सांसद ने बताया कि जगदलपुर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा जिलों में संचालित केंद्रीय विद्यालय जनजातीय एवं दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई विद्यालयों में स्थायी भवन, पर्याप्त कक्षाएं, विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, खेल सुविधाएं और अन्य जरूरी आधारभूत संसाधनों का विस्तार किया जाना बेहद आवश्यक है। इसके साथ ही, अध्यापन कार्य को सुचारू बनाने के लिए शिक्षकों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को भी जल्द से जल्द भरने की जरूरत है। महेश कश्यप ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री से आग्रह किया कि बस्तर के सभी केंद्रीय विद्यालयों का विशेष निरीक्षण कराया जाए। साथ ही, उनकी आवश्यकताओं का आकलन कर स्थायी भवनों, अतिरिक्त कक्षाओं, आधुनिक प्रयोगशालाओं, डिजिटल स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालय और खेल अधोसंरचना के विकास के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाए।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने सांसद द्वारा उठाए गए सभी विषयों को बेहद गंभीरता से सुना और छात्रहित में इन मांगों पर सकारात्मक विचार करने का पूर्ण आश्वासन दिया है। सांसद महेश कश्यप ने कहा कि बस्तर के विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए वे केंद्र सरकार के समक्ष क्षेत्र की शैक्षणिक आवश्यकताओं को लगातार और प्रभावी ढंग से रख रहे हैं। बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप ने नई दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा।

चिरायु योजना: जन्म से असमर्थ 6 वर्षीय रिया को मिला नया जीवन

उत्तर बस्तर कांकेर/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी 'चिरायु योजना' ने एक बार फिर एक जरूरतमंद परिवार के जीवन में खुशियां लौटा दी हैं। जिला मुख्यालय कांकेर के संजय नगर निवासी अमित सिंदूर की 6 वर्षीय पुत्री रिया सिंदूर, जो जन्म से ही सुनने और बोलने में असमर्थ थी, का सफल इलाज इस योजना के माध्यम से संभव हो सका है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार होने के कारण माता-पिता निजी अस्पताल में इस महंगे उपचार का खर्च उठाने में असमर्थ थे, लेकिन सरकारी योजना ने बच्ची को नया जीवन दे दिया है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.सी. ठाकुर ने जानकारी दी कि चिरायु टीम के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान रिया की स्थिति संज्ञान में आई। इसके बाद उसे विस्तृत जांच के लिए एम्स रायपुर भेजा गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों ने 'कॉक्लियर इम्प्लांट' की सलाह दी। निजी अस्पतालों में इस प्रकार के जटिल उपचार पर लगभग 10 से 12 लाख रुपए तक का खर्च आता है, लेकिन चिरायु योजना के अंतर्गत 06 जुलाई 2026 को एम्स रायपुर में यह ऑपरेशन पूरी तरह निःशुल्क किया गया। ऑपरेशन के बाद से रिया के स्वास्थ्य में तेजी से और उल्लेखनीय सुधार देखा जा रहा है। अब वह सामान्य रूप से सुनने और बोलने लगी है, तथा एम्स रायपुर में उसकी स्पीच थैरेपी की प्रक्रिया जारी है। अपनी बेटी की इस कायापलट से खुश माता-पिता ने शासन और स्वास्थ्य विभाग को धन्यवाद दिया है।

सफल इलाज: कांकेर की जन्म से सुनने और बोलने में असमर्थ 6 वर्षीय रिया सिंदूर का 'चिरायु योजना' के तहत सफल कॉक्लियर इम्प्लांट किया गया है।

निःशुल्क ऑपरेशन: निजी अस्पतालों में 10 से 12 लाख रुपए खर्च होने वाले इस महंगे उपचार को 6 जुलाई 2026 को एम्स रायपुर में पूरी तरह निःशुल्क किया गया।

स्वास्थ्य में सुधार: ऑपरेशन के बाद बच्ची अब न केवल सुनने लगी है, बल्कि बोलने भी लगी है और वर्तमान में एम्स रायपुर में उसकी थैरेपी चल रही है।

परिवार की प्रतिक्रिया: गरीब माता-पिता ने महंगे इलाज का खर्च उठाने में असमर्थ होने पर छत्तीसगढ़ शासन, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया है।

बलौदाबाजार के किसानों ने खेती में किया तकनीक इस्तेमाल

ड्रोन से खरपतवार नाशक का छिड़काव कर 40 हेक्टेयर में बचाया समय और श्रम

बलौदाबाजार/नवप्रदेश। जिले के किसान अब खेती में नई तकनीक का इस्तेमाल कर आधुनिक कृषि की ओर तेजी से अग्रसर हो रहे हैं। इसी कड़ी में विकासखंड भाटापारा के ग्राम पाटन, धौरभठा और खोलवा के किसानों ने खेती में एक नया उदाहरण पेश करते हुए करीब 40 हेक्टेयर रकबे में ड्रोन के माध्यम से खरपतवार नाशक का छिड़काव करवाया है।

पारंपरिक विधि की तुलना में अत्यधिक फायदेमंद: ग्राम धौरभठा के किसान आलोक जायसवाल एवं खोलवा के कृषक गुड्डू चांडक ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि पहले 2 से 3 एकड़ में छिड़काव करने के लिए 2 मजदूरों को पूरा दिन लग जाता था। वहीं, ड्रोन की मदद से 40 हेक्टेयर का यह बड़ा काम महज एक दिन में ही पूरा हो गया। इसमें पानी की खपत भी कम हुई और किसानों को पीठ पर भारी टंकी ढोने की शारीरिक परेशानी से भी राहत मिली।

ड्रोन छिड़काव के प्रमुख लाभ: समय की बचत: मैनुअल छिड़काव की तुलना में 80 प्रतिशत समय कम लगा।

समान छिड़काव: ड्रोन ने निर्धारित ऊंचाई से एक समान रूप से खरपतवार नाशक का छिड़काव किया, जिससे दवा की बर्बादी कम हुई और फसल पर इसका असर बेहद बेहतर रहा।

लागत में कमी: मजदूरी और दवा दोनों की बचत हुई तथा खरपतवार नियंत्रण अधिक प्रभावी तरीके से हुआ।

प्रशासनिक सहयोग और भविष्य की योजना: जिला प्रशासन द्वारा सहकारी समिति के माध्यम से किसानों को ड्रोन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 4 ड्रोन इफ्को कंपनी के भी हैं। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस व्यवस्था से अब छोटे किसानों को भी बेहद कम दर पर ड्रोन सेवा मिल रही है। फिलहाल भाटापारा क्षेत्र में धान और दलहन की फसलों में खरपतवार नियंत्रण के लिए यह तकनीक तेजी से लोकप्रिय हो रही है। पाटन, धौरभठा और खोलवा के किसान इस सफल प्रयोग से बेहद संतुष्ट हैं और आने वाले सीजन में और अधिक रकबे में ड्रोन से छिड़काव करवाने की योजना बना रहे हैं।

-आधुनिक कृषि की पहल: बलौदाबाजार जिले के भाटापारा विकासखंड के किसानों ने खेती में तकनीक का बेहतरीन उदाहरण पेश किया है।

-ड्रोन से छिड़कावः ग्राम पाटन, धौरभठा और खोलवा के किसानों ने करीब 40 हेक्टेयर रकबे में ड्रोन के माध्यम से खरपतवार नाशक का छिड़काव करवाया।

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक प्रधान संपादक यशवंत धोटे द्वारा, मिनल पब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन प्रा.लि. शेड नंबर 74, सेक्टर-सी, उरला इंडस्ट्रीयल एरिया रायपुर, से मुद्रित कर सुपर मार्केट कॉम्पलेक्स, अग्रसेन चौक, बिलासपुर से प्रकाशित, RNI NO.CHHHIN/2015/62431, संपादक-चन्द्रशेखर धोटे*, स्थानीय संपादक-विक्रम सिंह ठाकुर, समाचार संपादक-संदीप दीवान, फोन नंबर : 07752-468654, navpradeshbilaspur01@gmail.com